STATEMENT *RE*: U.P. SUGARCANE CESS VALIDATION ORDINANCE

Dr. B. Gopala Reddi: On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the U.P. Sugarcane Cess (Validation) Ordinance, 1961, as required under Rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [*See* Appendix I, annexure No. 54]

BANKING COMPANIES (AMENDMENT) BILL*

Dr. B. Gopala Reddi: On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Banking Companies Act, 1949.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Banking Companies Act, 1949"

The motion was adopted.

Dr. B. Gopala Reddi: I introduce the Bill.

STATEMENT *RE*: BANKING COMPANIES (AMENDMENT) ORDINANCE

Dr. B. Gopala Reddi: I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Banking Companies (Amendment) Ordinance, 1961, as required under Rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [*See* Appendix I, annexure No. 55]

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 2, dated 21-2-61.

12·13 hrs.

MOTION ON ADDRESS BY THE PRESIDENT—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now proceed with further consideration of the following Motion moved by Shri Bhakt Darshan and seconded by Shri C. R. Pattabhi Raman on the 20th February, 1961, namely:

"That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament assembled together on the 14th February, 1961",

along with the amendments moved thereon.

Shri Vajpayee was in possession of the House. He has taken 8 minutes. He may continue.

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल राज्य सभा में प्रधान मंत्री जी ने जो यह घोषणा की है कि चीन के साथ समझौता केवल इसी आधार पर हो सकता है कि चीन भारत का क्षेत्र खाली कर दे, इस में लेन देन का कोई प्रश्न नहीं उठता, मैं उस घोषणा का स्वागत करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने फिलहाल पेकिंग न जाने के संबंध में जो निर्णय किया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। जब तक चीन के रवैये में, चीन के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता, चीन के साथ वार्ता करने का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए भी मैं प्रधान मंत्री जी के भाषण में इस प्रश्न का कोई उत्तर न खोज सका कि अगर चीन भारत की भूमि पर से अपने आक्रमण को नहीं हटाता तो हम भारत की भूमि को मुक्त करने के लिए कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। यदि आज सैनिक कार्रवाई करना सम्भव नहीं है तो कम से कम

[श्री वाजपेयी]

यह तो संभव है कि हम सीमा पर जो चौकियां हैं, वहां पुलिस की जगह अपनी फौज तैनात करें। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में यह बताया है कि काला पानी तथा गरबियान की चैक पोस्ट पर अभी सिविल पुलिस लगी हुई है, वहां हमारी फौज के जवान तैनात नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि ये चौकियां पूरे साल काम नहीं करतीं, कुछ महीने ही काम करती हैं और बाद में पुलिस के सिपाही वापिस चले आते हैं। अगर चीन के जवान तकलाकोट में बारहों महीने चौकियां पर काम कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम भी वहां पुलिस की जगह फौज के जवान न रखें और बारह महीने वहां पर सीमा की देख भाल का इंतिजाम न करें।

इस के साथ यह भी प्रश्न है कि क्या सैनिक कार्रवाई को छोड़ कर हम ऐसे और कोई कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिन से पता लगे कि हम चीन के आक्रमण को बरदाश्त नहीं करेंगे। उस दिन उप-विदेश मंत्री ने राज्य सभा में बताया था कि पेंगिकग में हमारा जो इंडियन मिशन है, उस के राजदूत के परसनल असिस्टेंट के साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया गया। हमने एक विरोध की चिट्ठी भेजी है। पर क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? क्या हम उस दिन की प्रतीक्षा कर र हैं जब इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार हमारे राजदूत के साथ किया जाएगा? चीन का हमारे प्रति जो भी आचरण है, उसके विरोध-स्वरूप हमें पकिंग से अपने राजदूत को वापिस बुला लेना चाहिये और जब तक हम उन्हें वापिस नहीं बुलाते, तब तक चीन में हमारे राजदूत और उन के कर्मचारियों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, उसी प्रकार के प्रतिबन्ध नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास के कर्मचारियों पर भी लगने चाहियें।

12.16 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

दोनों देशों के अधिकारियों ने जो वार्ता की है, उस से एक बात स्पष्ट हो गई है कि तिब्बत के सम्बन्ध में हमने जो नीति अपनाई है वह नीति ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट नहीं होती। चीन ने भी, तिब्बत संधियां कर सकता है, इस अधिकार की पुष्टि की है। हमने भी इसका उल्लेख किया है कि तिब्बत को अन्तर्राष्ट्रीय संधियां करने का अधिकार था। तो फिर हम तिब्बत पर चीन के अधिकार को सौ फीसदी किस तरह से स्वीकार कर सकते हैं? जो तथ्य हमने रखे हैं, जो संधियां हमने उद्धत की हैं, उन से इस बात की पुष्टि होती है कि तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में जीवित रहने का अधिकार था। अगर आज सरकार किन्हीं कारणों से इतना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है तो कम से कम तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का जो प्रश्न है जिसे थाईलैंड और मलाया ने राष्ट्र संघ में उठाया है, हमें उसके समर्थन का तो उन्हें आश्वासन देना चाहिये। यह प्रस्ताव कैसा बने, इस के सम्बन्ध में भारत सरकार की राय जानने की कोशिश की गई है। मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न शीत युद्ध का प्रश्न न बने, इस के लिए प्रयत्न किया जा सकता है, अगर भारत सरकार इस बात का संकेत दे कि वह प्रस्ताव किस रूप में होना चाहिये। लेकिन अब तिब्बत के मानवाधिकारों के प्रश्न पर चीन की शक्ति को देखते हुए हम चुप बैठे रहें, यह ठीक नहीं होगा।

इस के साथ ही विश्व के जनमत को भी हमें सीमा विवाद के प्रश्न पर अपनी ओर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। कल ऐसा वाद-विवाद में कहा गया कि चीन हमें हमारे पड़ोसियों से अकेला कर रहा है, अलग कर रहा है। नेपाल और बर्मा ने चीन के

साथ समझौता किया है, हमें कोई शिकायत नहीं है, वे समझौता करें। मगर उन्हें हमारे अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। चीन का आज तक का सारा इतिहास समझौतों को तोड़ने का इतिहास है। चीन के प्रधान मंत्री नई दिल्ली में आ कर कह गए कि हम भूटान और सिक्किम के साथ भारत के सम्बन्धों का सम्मान करेंगे। उसका टेप रिकार्ड भी मौजूद है। मगर पेकिंग रिव्यू ने सम्बन्धों के पहले "प्रापर" शब्द लगा दिया, उचित शब्द लगा दिया है। नेपाल और बर्मा अगर आज चीन के इरादों को न समझते हुए और भयभीत हो कर, जिस के लिए भारत सरकार भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती, चीन पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो उन्हें भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम चीन के इरादों से पड़ोसियों को परिचित करायें, विश्व में प्रचार करें, विशेषकर ब्रिटेन में जहां चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उस के सम्बन्ध में बड़ी गलतफहमियां हैं। ब्रिटेन के लोग बहुत कानूनदां बनते हैं। अब हमारी रिपोर्ट से हमारा पक्ष कानून की दृष्टि से भी बड़ा प्रबल हो गया है। इस रिपोर्ट का दुनिया के अन्य देशों में भी प्रचार किया जाना चाहिये। अफ्रीका के नये देश जो स्वतंत्र हो गये हैं उन को भी हम चीन के इरादों से परिचित करायें और उन की आजादी का स्वागत करते हुए चीन के विस्तारवाद के रूप में जो नया साम्राज्य-वाद पैदा हो रहा है उस से उन को सावधान करें, इस बात की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता के लिये जो नये संकट पैदा हो गये हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कल प्रधान मंत्री जी ने राज्य सभा में कहा कि राष्ट्रीय एकता पंचवर्षीय योजनाओं से भी अधिक महत्व रखती है। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते; लेकिन सवाल यह है कि पिछले १३ सालों में इस देश में राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने के लिये हम ने क्या कदम उठाये हैं। एकता की अपीलें करने से अथवा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भाषण करने से एकता पैदा नहीं हो सकती। जबलपुर में जो कुछ हुआ उस से हर एक भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन केवल गुस्सा प्रकट कर के और ऊपर से लीपा पोती कर के या किसी पर दोषारोपण कर के हम यह समझें कि यह समस्या हल हो गई, तो हम बड़ी भूल कर रहे हैं। जबलपुर कांड कोई रोग नहीं है, रोग का प्रकटीकरण मात्र है। कल कुछ सदस्यों ने कहा कि एक लड़की पर कुछ लोगों ने बलात्कार किया, तो लोगों ने यह बात क्यों देखी कि लड़की किस मजहब की थी और लड़के किस मजहब के थे? मैं उन से सहमत हूं। अपराध अपराध है, बुराई बुराई है, कौन सा मजहब या कौन सा मजहब मानने वाले करते हैं, यह नहीं देखा जाना चाहिये। मगर क्या हमने पिछले १३ सालों में ऐसा वातावरण पैदा किया है कि हम सवालों को हिन्दू-मुसलमानों के रूप में न सोचें या इस के विपरीत हम ने एक ऐसी फिजा बनाई है कि हम हिन्दू-मुसलमान के रूप में अब भी सोच रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह संसद् और यह सरकार इस पृथकता की भावना को पैदा करने के लिये जिम्मेदार है।

संविधान में लिखा हुआ है कि सभी जातियों के लिये एक सिविल कोड होना चाहिये, फिर क्या कारण है कि केवल हिन्दुओं का कोड बना है? क्या हम सिविल कोड नहीं बना सकते? क्या शादी विवाह का कानून सम्प्रदायों के लिये अलग अलग होना चाहिये? क्या दो शादियां करना एक सम्प्रदाय के लिये बुरा है, दूसरे सम्प्रदाय के लिये बुरा नहीं है? ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि अगर किसी हिन्दू को दूसरी शादी करनी होती है तो वह हिन्दू धर्म को छोड़ कर दूसरी शादी करता है। क्या यह चीज हमारे देश में एक राष्ट्रीयता

[श्री वाजपेयी]

की भावना पैदा कर सकती है। अभी हमारी सरकार ने हिन्दू मठों और मन्दिरों की सम्पत्ति के दुरुपरोग को रोकने के लिये कमिशन बनाया है। मैं इस कमिशन का स्वागत करता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मठों और मन्दिरों की सम्पति का ही दुरुपयोग होता है? मस्जिदों और गिर्जाघरों की सम्पति का दुरुपयोग नहीं होता? क्या सेकुलर स्टेट में सब के लिये एकसा कानून नहीं होना चाहिये ? क्यों नहीं इस कमिशन का कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाता ? क्यों नहीं आप इस चीज भूल जाते कि यह हिन्दू है और यह मुसलमान है ? हिन्दू होंगे पूजा पाठ के लिये और मुसलमान होंगे रोजा नामज के लिये, लेकिन जहां तक राज्य का सम्बन्ध है, शासन का सम्बन्ध है, किसी को हिन्दू मुसलमान नहीं माना जायेगा। हमें एक भारतीय समाज की रचना करनी है, मगर हिन्दुओं के लिये अलग कोड बना कर, हिन्दू मठों और मन्दिरों के लिये अलग कमिशन बना कर हम इस एकता को नहीं पैदा कर सकते, जिस को पैदा करने की हम घोषणायें करते हैं।

यह मेरी अपनी बात नहीं है, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है कि केन्द्र के एक मंत्री हैं, मैं नहीं जानता कि यह समाचार कहां तक सही है, उन्होंने प्रधान मंत्री जी को लिखा है कि नौकरियों में मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिये । मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी इस बात का खंडहन करें। कौन है वह मंत्री जो रिलीजन के हिसाब से सर्विसेज में रिजर्वेशन चाहता है ? अगर सर्विसेज में मजहब के हिसाब से रिजर्वेशन होगा तो देश में राष्ट्रीयता की भावना कभी पैदा नहीं हो सकती। क्या आप नौकरी देंगे, तो किसी का मजहब पूछेंगे ? अगर आप मजहब पूछेंगे तो यह भेद भाव और यह साम्प्रदायिकता सर्विसेज में भी फैल जायेगी। जिस व्यक्ति को मजहब देख कर, काबिलियत न देख कर, नौकरी में रक्खा जायेगा, वह नौकरी में जाने के बाद भी भेद भाव बरतेगा। अगर एक व्यक्ति भेद भाव बरतेगा तो उस की प्रतिक्रिया होगी, फिर दूसरे भी बरतेंगे, और फिर एक विषम चक्र चलेगा और देश को एकता के सूत्र में बान्धने का हमारा स्वप्न खंडित हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इस मंत्री का केन्द्रीय मंत्रिमंडल से स्तीफा मांगा जाना चाहिये । वह हमारी सेकुलर डिमाक्रेसी में विश्वास नहीं करता। उस दिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने हैदराबाद में हरिजन बन्धुओं को परामर्श दिया कि यह रिजर्वेशन ठीक नहीं है, यह खत्म होना चाहिये, यह स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। किन्तु हरिजनों तथा वनवासियों के लिये रिजर्वेशन हम समझते सकते हैं क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से उन के साथ अन्याया किया गया है, मगर मजहब के आधार पर रिजर्वेशन का क्या सवाल है ? किन्तु यह आवाज उठाई जा रही है और मैं चाहता हूं। एकता की दुहाई देने वाले इस के बारे में अपनी राय प्रकट करें जिस से पता लग सके कि कौन कहां पर खड़ा है । मेरा निवेदन है कि अगर आप विनाशकारी शक्तियों से लड़ना चाहते हैं तो पार्टी से ऊपर इस सवाल को उठा कर देखिये, उस से लड़ने के लिये मैं आप के साथ हूं। अगर हिन्दू साम्प्रदायिकता अपनाते हैं तो उस का विरोध होना चाहिये, उस से लडा जाना चाहिये, मगर आप एक सम्प्रदाय की साम्प्रदायिकता को बर्दाश्त कर लें, यह ठीक नहीं है ।

कुछ समय से इस तरह के संगठित प्रयत्न हो रहे हैं कि साम्प्रदायिकता को पैदा किया जाय और जब से केरल में मुसलिम लीग के साथ गठबन्धन किया गया है, यह साम्प्रदायिकता और भी बढ़ रही है मैं क्या बताऊं ? आज कहा जा रहा है कि अगर स्कूल की किताबों में हमारे विद्यार्थिय को दिवाली, दशहेरा और होली के बारे में

पाठ पढ़ाये जायेंगे तो हमारा मजहब खतरे में पड़ जायगा। यह मांग की जा रही है कि इस तरह के पाठ किताबों से निकाल दिये जायें। मैं पूछता हूं कि क्या यह मांग ठीक है? होली, दशहेरा, और दिवाली हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, उन से किसी मजहब का सम्बन्ध नहीं है। अगर कोई होली नहीं मनाना चाहता है तो घर में बैठ सकता है, मगर हम होली मनायेंगे हम गायेंगे। जब बसन्त की बयार बहेगी, नई फसल घर में आयेगी तो हम फागुन के गीत गायेंगे, और अगर धोखे से किसी पर रंग गिर गया तो क्या खून बहाया जायेगा? यह चीज ऐसी हैं जिन पर साफ बातें होनी चाहियें। हमारा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय क्या कर रहा है? इस समय समस्या है एक संस्कृति पैदा करने की किन्तु यहां तो अलग-अलग संस्कृतियों की बातें हो रही हैं।

और हमारा दुर्भाग्य है कि जब से पाकिस्तान बना है, ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं कि देश में पंचमार्गी भेज कर, हमारे यहां साम्प्रदायिक उत्तेजना उत्पन्न कर के राष्ट्रीय एकता को विघटित किया जाय। जबलपुर कांड के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं **नागपुर टाइम्स** का एक उद्धरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। नागपुर टाइम्स कांग्रेस का समर्थक कहा जाता है। **नागपुर टाइम्स** का कहना है कि इस बात की जांच की जानी चाहिये कि जबलपुर कांड में पाकिस्तान के पांचमार्गियों का क्या हाथ है?

नागपुर टाइम्स ने प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए कहा है:

"Prime Minister Nehru's statement on Jabalpur disturbances does not differ from what people may have expected of him. He denounced the heinous crime against the girl, and said that 'events that had taken place later indicated that "ourhealth is not good"'.

Violence is bad. It shows lack of restraint and impatience with the processes of Law. Generally viewed, Nehru's reaction to the events is, as it ought to be.

One would have, however, expected Nehru to be in possession of more facts than are available to the common man. But even from what is now known of events in Jabalpur, a platitudinous disapproval of violence would not appear to be enough.

Stocking of fire-arms in the mosques, attacks against the police and prompt and detailed relay of broadcasts from Radio Pakistan about incidents in Jabalpur and Sagar within an hour of their occurrence, are all facts which point to planned fifth-column activities in the very heart of the country.

There is no dearth of sermons to those who have been humiliated by the molestation of the helpless girl. We published one such sermon in our letters columns only the other day. But the main question is, what is the Government going to do about the Fifth Columnists who are preparing for disturbances in the country and have direct wireless contacts with our unfriendly neighbours across the border? The people would very much like to have an answer to that question from the Prime Minister."

जबलपुर के दंगों की निन्दा होनी चाहिए, वहां के दंगों की जांच के लिए हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति बननी चाहिए। जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, हिंसा की है, हत्या की है, उन्हें दंड मिलना चाहिए। मगर मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय एकता का प्रश्न पार्टी का प्रश्न नहीं है। उनको चाहिए कि वह एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन करें। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं

[श्री वाजपेयी]

खड़ी हैं उन के निराकरण का प्रयास करें समस्या की तह में जा कर देखें और समझे, फिर साम्प्रदायिकता, चाहे वह किसी की भी हो, उस के मुकाबले के लिये सारे देश को तैयार करें, सारा देश उनकी बात का आदर करेगा। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि एक की साम्प्रदायिकता को तो उछाला जाए और दूसरे की को दबाया जाए।

अभी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि जो मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों का राजनीतिक उपयोग होता है उस पर रोक लगायी जाए। क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए तैयार है ?

श्री त्यागी (देहरादून) : तैयार है ?

श्री वाजपेयी : अगर तैयार है तो इस प्रस्ताव को पास करिए। साम्प्रदायिकता किसी भी रूप में हो उसे कुचल दीजिए। हम आप के साथ हैं। लेकिन साम्प्रदायिकता के नाम पर आप एक साम्प्रदाय के तुष्टीकरण की नीति अपनाएं, इस का आज असर नहीं होगा। अगर चिनगारी गिरेगी तो आग भड़केगी। अगर ऐक्शन होगा तो उसका रिऐक्शन होगा। हम नहीं चाहते कि वह हो।, लेकिन क्या हम जबलपुर की घटनाओं को रोक सके ? कल हमारे मित्र श्री अशोक महता ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सके ? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियां फिर से पैदा न हों इस के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिये। धन्यबाद

Shri Ranga (Tenali): Sir, I would like to repeat what the Prime Minister had stated, that the health of the nation is not quite sound. But who is responsible for this? It is easy to blame the people. It would be all right if a great national leader like Mahatma Gandhi had said so. But is it all right for the Prime Minister who has been in charge of law and order in this country during the last 14-15 years to come and say that now and at the same time take so little action. Some years ago, there was a terrible and tragic accident on the railways and one of his own colleagues had shown the way by setting an example to the railwaymen and showed how strongly the Union Government felt about that matter and expected them to live up to their own code of conduct and profession and sense of discipline. We have not heard of any such sort of thing on the part of the leaders of the Madhya Pradesh Government or of this Government here in that direction. As if he had nothing to do with the administration at all he goes and gives a historian's judgment: the health of the nation is not sound. That is a judgment which cannot be accepted without proper action on their own behalf—with impunity from the Prime Minister.

Terrible things had happened there in Madhya Pradesh. Just now my hon. friend had explained all these things in his own extra-ordinarily eloquent manner. Something has got to be done in order to prevent recurrence of these things. It shows quite clearly that there is some kind of connection and conduct—may be wireless too between the leaders in different places, not of one community alone but of several communities. Something has got to be done by the Government in order to severe these connections and prevent a recurrence of such tragic events.

The President has asked the Members of this House to give special attention, vigilance and co-operation in respect of the many problems of our economic planning, our defence, world peace and the struggle of the still dependent peoples on the last page of his Address. I would like to take up this question—defence. Are we quite sure that we can feel quite satisfied or complacent about the manner in which our Defence Forces are being managed by this Ministry? Not so long ago,

there was that unseemly occurrence of the Prime Minister himself coming to this house and saying that there were temperamental differences between the Chiefs of Staff—or one of them—and his own Defence Minister. He was not able to make any change in the set up of our Defence in the light of that. A little later there was a furore raised in this House as well as outside by one of the newspapers which was castigated by the Prime Minister not so long ago as gutter press and yellow press, over the biography written about our Army Chief of Staff General Thimmayya. I have read it with very great care and I have found that there is nothing that could be objected to. Of course there are some interesting things, as it usual with American biographers, as to how some of the officers had drawn lots in order to exchange their household conveniences. But beyond that there is nothing else. Yet they made all that fuss and brought the Chief of Staff into so much trouble and worry and gave the impression to us also that there must be something wrong with the patriotic spirit of that great and eminent General. Not being satisfied with it, a unique thing has come to be done establishing a very bad and unwise precedent—of informing the whole of the country as to how soon and when the Chief of Staff is going to retire. Is it the right way to do so several months before he retires?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru: I am sorry to interrupt, Sir, but may I say that it is the fixed way of doing it; it has been done for years past, every time. There has been no exception.

Shri Ranga: If that is the fixed way of doing it, I can only say that my hon. friend does not seem to have become any wiser than his predecessors .

Shri Ansar Harvani (Fatehpur): Probably, you are not aware that our Prime Minister had no predecessor as Prime Minister.

Shri Ranga: Information of a special event is passed on to the aggressors on the other side. Are we going to make a present of this important information to them that the Chief of Staff who is one of the ablest living Generals anywhere in the world is going to be made to retire on a future date? I think it was a bad mistake....(*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I have no objection to his criticising the Government in any manner he likes. But he should take care that he does not bring in individuals or makes any representation on their behalf. It may rather give scope to others to criticise: it is opening ourselves to too much of criticism rather than serve any useful purpose.

Shri Ranga: We would like to be better informed than we had been of the manner in which the Defence Forces are being managed. Only yesterday, Shri Asoka Mehta has placed a very interesting proposal before the Government; it does not go far enough but it is good enough. In addition to that, there have been—we are told—some promotions and some changes. We would like to know, if not at this stage at some suitable stage, which of the senior officers are being promoted and why, which of the senior officers are not being promoted and why and whether there is any kind of a policy at all in regard to all these things and whether all these changes are being made and all these decisions are being taken not only with the full concurrence but with the full knowledge and understanding of the Prime Minister as well as the other members of the Cabinet and the Defence Sub-Committee of the Cabinet. If they have not done so, then they owe an explanation to the country and also an assurance that all these changes are being done with a view to ensure a greater efficiency and a more assured patriotic responsibility from our Defence Forces.

Then whose duty is it to keep a watch over our borders—Defence or

[Shri Ranga]

the External Affairs Ministry? It stands to the credit of my hon. friend, a socialist—at that time they were all together—to have brought to the notice of this House several times about what they learnt in regard to the incursions that the Chinese were making on our borders. Repeatedly, the other side, the Treasury Benches, were unwilling to give us any information. Years afterwards, the Prime Minister went to the other House and said: yes, it was a mistake that we have not been able to give timely information to both the Houses.

Shri Jawaharlal Nehru: I do not think I have ever said that.

Shri Ranga: If you have not said it, it makes it even worse for the Prime Minister.

Shri Jawaharlal Nehru: Maybe. I do not accept what is stated by this hon. Member or any other in regard to this matter.

Shri Ranga: It only makes his position much worse. At least now, any responsible Government should be prepared to apologise—

Shri Jawaharlal Nehru: What for?

Shri Ranga:——to the nation for having kept it in ignorance for such a long time over the incursions that were taking place. He would never agree. Otherwise, he would not be there! (*Intesruption*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri Ranga: If interruptions are made, that would waste my time. Now, in addition to that, encouraged by......

Shri Jawaharlal Nehru: Would the hon. Member repeat what he said, so that I may be able to understand him?

Shri Ranga: I am speaking, I think, plainly enough so that my hon. friend can understand. We have known each other for 30 years and he should be able to understand.

Shri Jawaharlal Nehru: I know. The hon. Member has been shifting from party to party in these 30 years. I do not know what he is after.

Shri Ranga: It is a cheap jibe: I had the courage to do that. My hon. friend never had the courage to do that. (*Interruption*).

Shri Jawaharlal Nehru: I should again want to know what he said. If the hon. Member makes charges, let him be precise and definite and I shall have my say. It is no good making insinuations of the kind the hon. Member is making.

Shri Ranga: There are no insinuations. We are making charges.

Shri Jawaharlal Nehru: Would he kindly repeat that charge so that I can deal with it?

Shri Ranga: I am coming to the next question. The report made by the officers is there. It shows that they have done a very good job, to which testimony has been given by the leaders of the two other Opposition parties, and I agree with it.

Mr. Deputy-Speaker: One thing. The hon. Member just now said that he is coming to the next question. If some charges are made against any hon. Member—and particularly now it was done against the Prime Minister—and if he wants them to be repeated as he had not followed them, and he wants that it might be done more precisely so that he might give an answer when he replies, where is the harm if the charges are made clearly, if really there are any?

Shri Ranga: It only means a waste of time. Anyhow, my hon. friends from the Socialist side informed the Prime Minister as well as the members on the Treasury Benches and

pointed out repeatedly that they were in the know of the repeated and growing incursions that the Chinese were making over our borders, and we were not given either definite information or satisfactory information. In the end, as my information goes,—if my hon. friend contradicts it, I stand corrected—after a long time, when the hon. Prime Minister was accosted about this in the other House, I understood he said that he should have given this information to the country much earlier but he did not do so. I thought he admitted his mistake. But now he says he has not admitted the mistake. That is all.

The next point is about Tibet. So many of us objected to the stand taken by the Prime Minister at that time, and yet he pursued that line; you know the results now. Over this long border of 2,000 miles and more, the enemy—I would like to call him so now—or the aggressor certainly has come up, and he has come on the other side of our border, and he is aggressing on our territory. This is the result of that early failure of our Government, and this report of the officers makes it very clear. Whether people would agree to consider Tibet to be a sovereign country or not, she was certainly enjoying such autonomy as to be able to send her plenipotentiaries on a par to the international conferences to discuss and decide and put her signature to questions and decisions or the borders between Tibet and ourselves. For over many years that has been going on, and yet, the Ministry of External Affairs was ignorant or indifferent to all those facts. They thought that they were or could be very liberal and therefore they have made a free gift of it, as it were, to China, and we are paying for it. That is another charge.

Thirdly, was it not the duty of the Defence Ministry at that time itself to have warned the Prime Minister and then strengthened themselves? Now, they say that progressive steps are being taken in order to built roads, and all sorts of dumps and other stations on those high altitudes. We have lost ten years with bitter results. They stand condemned. I do not know who will have to apologise to the future, but certainly the present Government has got to be held responsible for this. It might be said, "You were also then with us." But even though I was with them, I was then protesting against this, and my hon. friend used to be very, very angry with me over this Tibet. That question is not over so far as I am concerned. I do not want to talk about it any further.

The next question is about the Congo. Bitter things have happened; tragic things have happened. We are all unanimous in condenmning the murder of that national leader, Lumumba.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): So many others have also been killed now.

Shri Ranga: Yes; Lumumba was a national leader; there are others also. (*Interruption*). We would like the United Nations to take more effective action in order to prevent any more such tragedies. There, we are one with the Prime Minister. The Prime Minister had shown some consideration, and more than the Prime Minister, Shri Dange, the leader of the Communist Party, had shown the same indignation when Imre Nagy was done to death by the Hungarian Communists.

Shri Tangamani: You are justifying!

Shri Ranga: Recently, I was rather shocked at the alacrity with which the Prime Minister criticised what has happened in Nepal. We can hold our opinions. The Prime Minister is extremely anxious that the House should be very wise and should be very chary about expressing its views and yet, somehow or other, he thought it fit to go to the press. What are our relations in regard to

[Shri Ranga]

Nepal and in regard to Burma? Burma has been receiving a tremendous attention and a lot of assistance from us, and we have held them more than our brothers. And yet, when it came to settling the borders between Burma and China, she did not mind allowing a certain amount of uncertainty to remain over certain parts of the borders which are there between China, ourselves and Burma. I hope the hon. Prime Minister and his External Affairs Ministry have protested against it. They seem to have made some representation. How long are we to continue to consider the Chinese Government as a very friendly 'bhai-bhai-Government'? I would like an assurance to be given by the Government, if they can, and if they would like to, that we are not going to sponsor her application in the United Nations any longer.

Shri Jawaharlal Nehru: I can give an assurance that we will.

Shri Ranga: "We will." There you are. That is also another charge of mine. I can understand it, and I have understood it earlier, that they were making this proposal in order to bring her within the four corners of world order and world decency and all the rest of it, so that she might be made to behave.

Only yesterday, my hon. friend Shri Asoka Mehta drew the attention of the House to the impunity with which the callousness with which and the unscrupulousness with which Communist China set at naught any kind of document on which she puts its signature. What is the use of bringing her there. It may be said, "The whole world has brought South Africa also into the United Nations." We know the results, and can the other results be different? Of course, there would have been some justification for expecting or entertaining some hopes after all that they have done. We will forget all that. After the gentleman, Mr. Chou En-lai, had come over here and gone back, he has added an additional word "proper". In addition to this, the officers have met each other; and from time to time, they went on changing their maps and were bringing out and producing new maps as if from a magician's box. Are we to continue our attitude towards China in blissful faith in people's China's willingness to stand by any of those agreements or even the charter of the United Nations? Let us make it very clear now to the rest of the world. I think the time has come that we no longer consider peoples' China to be our friend.

My hon. friend Shri Dange was met effectively by my hon. friend Shri Asoka Mehta yesterday in regard to China. I need not add anything more than this. I am not quite sure whether the attitude that he has displayed is the presage of a kind of policy, or non-existent policy of the Government in the next one or two years—we must continue to negotiate, we must parley with those people, if not at official level at some other levels also. And in that way anyhow, let the Ravaneswara *kashta* go on burning! And that is exactly what is happening. Let us be careful.

An Hon. Member: What is your proposal?

Shri Ranga: My proposal is, do not recognise People's China, treat People's China as an aggressor and simply refuse to deal with her in the manner in which we have been dealing with her till now.

The next point is planning. In regard to planning I would like to say that God gave me the power or the moral courage to oppose the First Five Year Plan itself when we had to walk into the lobbies nearly eight years ago. And at that time the Communists also were not in favour of the plan. Now wisdom has dawned on them, but we have not achieved

that wisdom! Therefore they are now all in arms with the Government. Well, I wish all good luck to the Government with their two bed-fellows, whether they are straying or comfortable, or whatever it is. It is their own concern.

Shri Dange is all in favour of the plan. I wish to tell you that I am opposed to this very general approach of this plan. Their priorities are all wrong. There should have been the first priority for agriculture. It is not given that way. Secondly, they have upset the sense of security of our self-employed people in our country. They have been persistent in dealing with all th self-employed pople as a kind of a private sector and giving the impression as if, as my friend Shri Dange put it, these people are all profit-making people.

Shri Harish Chandra Mathur (Pali): My hon. friend is the only one Member representing a particular view in having no faith in the plan. So we would like to have a little clarification from him. When he says that the first priority should have been given to agriculture, that clearly indicates that he wants a plan. Priority means plan and nothing else.

Shri Ranga: My hon. friend should go to an elementary school to get himself educated. I will tell him why. It does not mean that I do not want any kind of planning. Mahatma Gandhi wanted a plan, he believed in plan. One of our friends who wrote a book on Gandhian Plan has gone over to the other side. I also wrote one book; Mahatma Gandhi approved of it.

Shri Harish Chandra Mathur: I think you are forgetting all that.

Shri Ranga: My hon. friend Acharya Kripalani also wrote one book on certain aspects of that plan, and Mahatma Gandhi approved of it. One of those books I may refer to my hon. friend for his better education, *The Latest Fad of Mahatma Gandhi*.

Shri Harish Chandra Mathur: I am always a student.

Shri Ranga: There was plan, we wanted a plan. But we do not want this plan. I was responsible like my hon. friend also—and he was the Chairman of the Standing Planning Committee of the Congress of those days—we wanted a plan, we wanted a Planning Commission also. Yes, but then unfortunately the plan came this way. I even warned at that time the other side of Parliament that this is a Soviet plan, it is not a Gandhian plan, it may be a socialist plan but it certainly is not a Gandhian plan. And I said, it might be given the stamp of Nehruite plan; but with that name also you cannot very well push it down like sugar-quoted quinine.

And therefore I say that all these tens of millions of self-employed peasants, for whom it is not necessary to exploit anybody, and most of whom work on their own farms, by their own labour and family labour and carry on their non-exploiting self-employment activities, those people should have been given the necessary assurances.

Now they have passed a Ceiling Bill in various legislatures, and here also. What is the consequence? Not only those few lakhs of people who would come somewhere near the ceiling but millions and millions of others would also have to be afraid now that possibly the ceiling would continue to be reduced stage by stage and when my hon. friends come into power, from the PSP or the Communist Party, or even the ginger group provides an overwhelming majority to Pandit Jawaharlal Nehru, then the ceiling would be reduced. Where is the guarantee that it is not going to be reduced? They have already fortified themselves by amending the Constitution, article 31, as the House knows, in regard to property. And therefore they have given themselves the power for the legislature as well as Parliament. And in this way they have created a sense of insecurity among

[Shri Ranga]

our peasants, the great bulk of our people. They are not profit-making people, they are not exploiters, they are small entrepreneurs, all in their own, independent, freedom-loving people. They are the people who should be cherished as forming the back-bone, the very base indeed of our national development and socialist economy. Unfortunately it is those people who have escaped the attention of the planners.

And at long last, now, after ten years of this bad planning they say that they are going to provide all these various facilities. Did we not suggest then? I myself sent a report to the hon. the Prime Minister—it was published too—that fertilizer, credit, soil conservancy, improved seeds, all these various things should be provided to our agriculturists. Now, in the Third Plan they are thinking of providing these things, and for that too they want to make an experiment by having what are called package plans in a few districts here and there. It has taken them ten years. If they had only gone about it the right way all these things could have been done and our peasants would have been able to produce very much more than what they are able to do today.

The hon. the Food Minister is taking pride in the fact that the conditions of the crops are very much better. But they were bad last year. They are better today, not because of the Minister but because of....

An Hon. Member: Swantantra Party.

Shri Ranga: .....the seasons. Yes, Swantantra, you may not believe in Him, but the swantantra of God is responsible for these things. There is no good taking any pride in it. What we have to do is to show the country the irrigation potential that has been developed. They themselves admit that 25 per cent has not been developed. If peasants have been able to make use of this water to some extent, they have not been supplied with the necessary credit, so much so that the land is not fully exploited and cultivated to the maximum possible extent with good crops and so on.

And then they say that they are going to increase employment. I warned them then, and I warn them here also now, it would not be possible for them, as they themselves admit, to provide employment for all the new entrants into the employment market either in the towns or the villages. They themselves admit it. And the unemployment problem is going to grow more and more. In spite of it, look at the fool-hardiness of the planning. They want to introduce power looms in place of handlooms, so that lakhs and lakhs of weavers can be thrown into unemployment! They want to do it in such a light-hearted manner. They talk in one breath at one moment and talk in another breath at another moment. They appear to be Adisesha with a thousand breaths!

I cannot congratulate or thank the President for having given us this Address in this manner only based upon the failures of the Government.

Shri Harish Chandra Mathur: I was really a little amused to find how my esteemed friend, the leader of the Swatantra Party has permitted himself to be swept off the rails like this. I have been his colleague in the Rajya Rajya Sabha for four years and we are now here together for another four years. Though I am prepared to read any books and volumes that he would suggest, I have always tried to understand him and tried to learn from him, and I would have no hesitation even further to have any suggestions from him for being considered. But I was simply surprised. What we expected from the leader of the Swatantra Party was that he would give us some of the basic ideas on which that party was built, where they differ, what they want and that

he would deal with the basic problems rather than to start with certain personal digs here and there by raking up old issues of an absolutely personal nature which the country had completely forgotten.

Shri Ranga: Question. There was nothing person, nor are they old issues.

Shri Harish Chandra Mathur: Now, as matter of fact, let us understand what are the important problems.

13 hrs.

The President's Address is of very great significance to us at this juncture both from the view-point of external affairs as well as from the view-point of the domestic affairs. We are living in a very crucial period. So far as external affairs are concerned, the entire world is in a very great ferment and certain situations have developed which call for momentous and bold decisions. In so far as our domestic affairs are concerned, we are now completing ten years of our planned economic development and are launching on the Third Plan which we consider to be of very great importance in shaping the future of this country. I thought my hon. friend would have dealt with these important basic problems. So far as external affairs are concerned, naturally the President has devoted considerable attention and time to it, because it affects vitally most of us in the world and even our domestic affairs are very much influenced by what is taking place all over the world.

Sir, as I see the situation, we find the cold war at its worst. The situation in the Congo is such that it demands real and serious consideration.

Mr. Deputy-Speaker: Hon. Members should not be seen standing in the passages.

Shri Harish Chandra Mathur: Every body would be deeply distressed at the shape events are taking in the Congo, and inspite of the world opinion being voiced so strongly, what is happening there is shocking. We cannot but condemn in the strongest possible terms the role played by the two power blocs. In the ultimate analysis, let us understand what it comes to. The whole situation boils down to this that all this is happening simply because we have two power blocs that mutually distrust each other. Because of these complications arising, the situation in the Congo is deteriorating like this. The only right course for these power blocs to follow would have been the one which had been suggested by our Prime Minister at the United Nations General Assembly. Now at least there is a better realisation of this position, and the United States of America is drawing towards the right course. But because of their past ties, it has not been possible for them to take a completely fresh stand to ease the world tension. In this situation, the only solution for the problems facing the world is our policy of non-alignment. If these tensions are to be eased, these power blocs will have to be liquidated and the Summit Conference which was summoned earlier was a big step in that direction. It is only through these conferences, by bringing the nations of the world together, we can reduce these tensions. I will not deal with this situation at any great length. We are very much concerned particularly with the problems which directly affect us.

Here, Sir, I would like to refer to what may be considered to be the smallest of the problems, that is the problem of Goa. I have not been able to appreciate why we here in India should not take a different attitude than the one we have taken so far. So far as Goa is concerned, it is recognised now—we were all the time very clear in our mind, except for certain suspicions which had been created—that it is a colony of Portugal, and those who have been holding on to this colony should be definitely thrown away. We have a right to throw them away, as we

[Shri Harish Chandra Mathur]

threw away the British rulers. I think every Indian living in this country has a right to throw away the Portuguese rule in this part of India. It is not merely the responsibility of those people who are living in Goa. The attitude of the Government will have to be revised in this particular context. Even the United Nations now recognise that Goa is a colony and that like all other colonies it must be freed. They want a report to be presented to the United Nations about the State of affairs in Goa. In the existing context, possibly our Government wanted to educate world opinion before it took any particular attitude; it wanted that the whole world opinion should go with it. It is now quite clear that the entire world opinion is with us on this point, that Goa is a colony of Portugal, that Portugal has no right to stay there, the people staying in Goa are Indians as we are Indians and Indians living in Goa have the right to self-determination. I, therefore, think that our Government should revise its attitude and go in support of any movement which is launched not only within that area but also from outside.

I now come to Pakistan. I think no country in the world could have paid greater tribute to our foreign policy than Pakistan has done. You must have read in the papers that of late there has been a change in the utterances of their leaders, though they are all against India. Let us realise what they say. They say that India has taken advantage of its foreign policy, that it has received aid and assistance from both the blocs and they are also going to follow the same policy and that they are not going to get themselves tied down to a bloc. That is the sort of utterances which one comes across from the various leaders and the President of Pakistan.

An Hon. Member: Do they mean that?

Shri Harish Chandra Mathur: That is the greatest tribute that could be paid to our foreign policy. They are smarting under a feeling of anger against the successful policy of this country. It is only out of that feeling that they say it, not that they believe in it. If they do believe in it, that would have been entirely different; we would have very much welcomed it. They say that they would like to follow this policy, not because they have any faith in it, but because they want to take advantage of it and want to have assistance from both the sides, which they are never likely to get until they have real and basic faith in that policy. Well, they have no faith in that policy. Their expressions are clear indications of the fact that our policy has been remarkably successful. All the African countries which have emerged independent during the last few years have with one voice followed this policy of non-alignment and they find that this is the only policy which could be adopted. I may mention also with certain pardonable pride that there is much better understanding of this policy all over the world. There may be certain vested interests, which may throttle their voice, but in spite of that there is much better under-standing of it in the United States of America. What the Kennedy Government ever since its taking over has done is that step by step they are coming closer to our policy. It might be mentioned that in his inaugural address the President has made a reference only to two great statesmen of the world, past and present. It was Mr. Churchill and our Prime Minister, Shri Nehru, from whom he says he is drawing inspiration.

So far as the China border is concerned, I am in cent per cent agreement with the policy followed by the Government. There could be no other policy that could have been followed. Certain objection was raised against the words used by the President in his Address that they have hopes that China will feel persuaded to do so. I think that is

the most dignified way of mentioning a thing. What else are you going to say? We do think that China will be left with no other alternative but to adopt that course. If China does not adopt that course. We are not entirely depending upon China adopting that course. We are all the time strengthning our defence and seeing that there is no further encroachment. We are not reconciling to any other policy, but to the one in which the entire aggression is vacated.

I think there can be no other policy. Let our friends suggest certain concrete steps that may be taken. We have an unequivocal statement regarding this position that this aggression must be vacated, that we will try to get it done through negotiations and we are getting more and more friends on our side; the entire world is raising its voice on this issue and China is completely isolated in this matter. But we are not just content with this; at the same time, we are fully strengthening our defence. That is the best that we can do in this matter.

Coming to domestic affairs, I will refer to the third Five Year Plan. We will first take an appraisal of what we have done during the first two Plans. During this decade, it can be said with definite satisfaction that we have truly laid down the foundation for a planned economy and development in this country. That is the surest way of going ahead. In matters of basic industries, we have steel which is important, coal which is no less important and oil and gas. We have given topmost priority to these basic things, so that our development goes ahead and our dependence on other countries is reduced to the minimum. We have also made remarkable progress in the manufacture of engineering goods and machine tools.

Our industrial production has gone up by 66 per cent, our food production by 42 per cent and our national income by 40 per cent. While we fully appreciate all these achievements and the basic soundness of the policy, let me say with absolute frankness that I am not satisfied with this on two accounts. This achievement is not to be viewed in isolation. Let us see how other comparable countries have fared in the world. There can be no better friend of India in this matter than Mr. Kennedy, who wants that this country should go ahead from success to success in material and developmental achievement. He took an appraisal of the entire situation and there is a whole article based on this under the heading "We want India to win the race". In his appraisal, he feels constrained to say:

"But the harsh facts of the matter are that in the last decade China has surged ahead of India in most sectors of its economy. Its gross national output has expanded about three times as fast. In terms of industrial capacity, investment, education and even household consumption, China has slowly pulled up and now moved ahead. Its food production has nearly doubled, while India's has increased by less than 50 per cent. By the most authoritative estimates, at present levels of agricultural growth, India will have by 1965 a food production deficit of over 25 million tons...." etc.

Experts have examined the facts and this appraisal has been given by a real and sincere friend of this country, who wants to help this country to go ahead. Let us not forget this.

The most important thing is our exports. I am not satisfied with our achievements in respect of our exports. During this decade, our exports have not gone up even by 20 per cent. When we examine it analytically, we find that our exports have fallen. To say that in 1950 we were exporting goods worth about Rs. 500 crores and now it is Rs. 600 crores does not give us the real picture. In the all-India context, let us examine the world

[Shri Harish Chandra Mathur]

trade figures. In 1950. In 1950, taking trade with the western countries India's percentage of the total world percentage was 2·6 per cent; it has now come down to 1·3 per cent. This is a very clear indication that our export trade with the western countries has not kept pace, although we might have made a certain progress. Not only it has not kept pace with the world trade, but rather it has gone down very much. That is a thing which needs examination by our Government.

About panchayat raj, the President has made a very deserved reference to the ushering in of panchayat raj. and has hoped that institutions of panchayat raj will be introduced in the various States. Rajasthan and Andhra have come for special mention. Rajasthan deserves particular attention in this matter. It has attracted a lot of attention, because it has gone the whole hog in this matter, because we have covered the entire area. There are certain people who felt that it is only because of our immaturity and backwardness that we have rushed into this scheme. They felt, fools come in where angels fear to tread. But our achievement during the last year has proved that it is not that way, but it is just the other way round.

Various observation teams which had been sent to Rajasthan have given commendable reports. Rajasthan has also got the fullest support of the Prime Minister, who is never tired of making reference to the panchayat raj and the achievements of Rajasthan. But certain doubts have been raised about our success because of the recent Panchayat elections that have taken place in Rajasthan. It has been stated that reactionary forces have come up, feudal forces have come up, communal feelings have been aroused and they have seized power. There is a certain amount of truth in this statement. But still, I am not in the least alarmed or worried about it. What has happened is not because the health of the people is not sound, but because of certain dirty noses poked in by those in authority and because of the abuse of administrative machinery.

It is absolutely necessary that a true assessment must be made of the whole situation. These recent elections have got certain lessons to teach not only to Rajasthan but to the entire country, at the cost of Rajasthan. Those lessons and problems which have been thrown up because of the recent elections will definitely have to be borne in mind.

I wanted to say another word about administration but, as my time is over, I will resume my seat.

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) उपाध्यक्ष जी, श्री भक्त दर्शन जी ने जो प्रस्ताव यहां उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे देश से सम्बन्ध रखने वाली भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की बातों पर सुन्दर प्रकाश डाला है ।

जहां तक बाहरी बातों का सम्बन्ध है, चीन का आक्रमण, काश्मीर और गोआ के सदृश प्रश्नों को भी कुछ पीछे ही डाल देता है । चीन और हमारे बीच की सीमा सम्बन्धी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार करने के लिए जो एक समिति मुकर्रर हुई थी उसमें हमारे सदस्यों ने परिश्रम कर जो बातें हमारे सामने रखी हैं वे एक प्रकार से अकाट्य हो जाती हैं । और जहां तक उन सदस्यों की इन बातों का सम्बन्ध है, मुझे इस बात पर बड़ा हर्ष होता है कि केवल कांग्रेस दल के सदस्यों ने ही नहीं, परन्तु राज्य सभा और इस सदन के करीब करीब सभी दलों के

सदस्यों ने उन लोगों की प्रशंसा की है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने कल राज्य सभा में यह बात स्पष्ट कर दी कि जब तक चीन हमारे भूखंड को नहीं छोड़ता, तब तक इस प्रश्न का हल हो ही नहीं सकता । मैं समझता हूं प्रधान मंत्री जी की इस घोषणा को देश में सर्वत्र समर्थन मिलेगा, और इसका स्वागत होगा ।

परन्तु यह बात निर्विवाद है कि हमारी भीतरी और बाहरी बातें, समस्याएं, प्रश्न, इन सब का निपटारा, इन सब का हल, एक बात पर निर्भर है, और वह है हमारी एकता । फूट हमारी राष्ट्रीय ऐतिहासिक कमजोरी रही है । सैकड़ों नहीं, दो ढाई हजार वर्ष के इतिहास को हम देखें तो भी हमें वह कमजोरी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । जब सिकन्दर का हमारे देश पर आक्रमण हुआ उस समय पश्चिमोत्तर में एक भारतीय नरेश आम्भीक मिल ही गया सिकन्दर का स्वागत करने के लिए । जब हूणों का हम पर आक्रमण हुआ उस समय क्योंकि गुप्तों का राज्य था और गुप्त वैष्णव थे, इसलिए बौद्धों ने हूणों को मदद दी । जब मुसलमान पहले पहल यहां आये, और वे उस समय विदेशी थे, उस समय जैचन्द ने उनका स्वागत किया, और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए भी मीर जाफर और अमी चन्द के सदृश व्यक्ति मिल गये ।

इस राष्ट्रीय कमजोरी के अभी भी अनेक बार दृश्य दिखायी दे जाते हैं । राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक ने और उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत में इसके निवारण करने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु अभी तक तो उसमें पूरी सफलता नहीं मिली है । कभी हिन्दू और मुसलमान लड़ते हैं, कभी सिखों और हिन्दुओं का झगड़ा होता है, कभी हिन्दू और जैन लड़ते हैं । अभी आसाम में कुछ दिन पहले जो झगड़ा हुआ वह दो राज्यों, बंगाल और आसाम, के निवासियों का झगड़ा था । ये संघर्ष कभी धर्म के नाम पर, कभी राज्य पुनर्गठन के नाम पर तो कभी भाषा के नाम पर होते हैं ।

हिन्दू सम्प्रदायवादी गांधी जी की हत्या के बाद दबे थे । उनका फिर उत्पकर्ष हो रहा है । उनके अनेक स्थानों से दैनिक पत्र तक निकलने लगे हैं और उनमें सम्प्रदायवादिता का बड़े जोरों से प्रचार होता है । मुस्लिम लीग से केरल में हमारा जो समझौता हुआ उसे यद्यपि मैं कोई गलत बात नहीं मानता, लेकिन उस समझौते ने हमारे पुराने सम्प्रदाय-वादी मुसलमानों को भी उभारा और उस समझौते का वे नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं । अभी उज्जैन में जमैयते उल उलेमा का एक जलसा हुआ । जमैयत ऐसी संस्था थी जिसने हमें गाढ़े वक्त पर मदद दी थी । वह राष्ट्रीय संस्था थी । लेकिन मैंने जमैयत के इस अधिवेशन के भाषणों को जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि जमैयत में इस प्रकार के भाषण कैसे होते हैं । कल स्वामी रामानन्द तीर्थ जी ने जो भाषण दिया उसको मैं पढ़ रहा था । उन्होंने मैसूर की एक घटना बतायी । उन्होंने बतलाया कि वहां के कुछ सम्प्रदायवादी मुसलमान किस प्रकार पाकिस्तानी नारे लगाते हुए एक जलूस में निकले थे । और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का भय है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे-वैसे वोट प्राप्त करने के लिए यह सम्प्रदाय-वादिता बढ़ रही है । न मालूम आगे आने वाले चुनावों तक इसका क्या नतीजा निकलेगा ।

अभी जबलपुर में जो कुछ हुआ, क्योंकि मैं जबलपुर से आता हूं, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है । जबलपुर के इस कांड पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि इस कांड की पूरी जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमीशन या कमेटी नियुक्त होगी । मैं इस लोक सभा के मंच से जबलपुर निवासियों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के निवासियों से कहना चाहता हूं और दूसरे लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक इस जांच कमेटी की रिपोर्ट न आ जाये तब तक वे

[डा० गोविन्द दास]

पूरा मौन धारण कर लें। इस जांच कमेटी के काम में वे पूरी पूरी सहायता दें और इस जांच कमेटी की जो भी रिपोर्ट हो उसको स्वीकार करना प्रत्येक देश निवासी का, कम से कम प्रत्येक राष्ट्र-भक्त का, कर्तव्य होना चाहिए।

परन्तु प्रश्न यथार्थ में किसका दोष है, यह नहीं है। साधारण जनता इन बातों में दोषी नहीं होती। इस प्रकार की राष्ट्रीय कमजोरी हमारे दिलों में है। प्रधान मंत्री जी ने बहुत ठीक कहा है कि अभी हमारे दिल साफ नहीं हैं इन मामलों में, उस कमजोरी का जो समाज विरोधी तत्व हैं वे फायदा उठाते हैं, और उससे हानि होती है, उसका फल भोगना पड़ता है निर्दोषों को।

हिन्दू देश में बहुमत में हैं। अतः एकता की स्थापना का सब से बड़ा उत्तरदायित्व मैं हिन्दुओं पर मानता हूं। यह उत्तरदायित्व हमारे सांस्कृतिक सिद्धान्तों के कारण और अधिक बढ़ जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तत्ववेत्ताओं ने, हमारे सन्तों ने, हमारे भक्तों ने, इस समस्त सृष्टि में एक ब्रह्म के दर्शन किये थे। हम अपने और समस्त सृष्टि के जीवों में कोई अन्तर नहीं मानते। हमारा मूल वाक्य रहा सदियों तक, युगों तक, वसुधैव कुटुम्बकम्। हमारे देश का बहुमत ईश्वरवादी रहते हुए चारवाक का निरीश्वर-वादी धर्म भी यहां पनपा। बौद्धों और जैनों का धर्म भी निरीश्वरवादी है। वह भी यहां पनपा। और ऐसी संस्कृति वाले यदि इस प्रकार के झगड़े करें, इस प्रकार के झगड़ों पर उतारू हो जांय तो मैं यह कहूंगा कि इस से ज्यादा लज्जा की बात कम से कम हिन्दुओं के लिए और नहीं हो सकती। हम जनता के नेता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम गुंडों के नेता नहीं हैं। जहां तक जनता का सम्बन्ध है जबलपुर नगर, जबलपुर जिला, समूचा मध्यप्रदेश, वहां की जनता राष्ट्रवादी जनता है। जबलपुर में जब चुनाव आते हैं तो हम हर एक चुनाव को जीतते हैं। उस समय सम्प्रदाय-वादिता हमारी जनता पर कोई असर नहीं करती। जहां तक ऐसे समाज विरोधी तत्वों का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि उस सम्बन्ध में हमारा एक कर्तव्य है और वह यह है कि हम जनता की भावना को बदलने का प्रयत्न करें। जनता से कहें कि कानून हाथ में लेना यह उस का काम नहीं है। कम से कम स्वतंत्र भारत में जब हमारी सरकार है तो जनता कानून हाथ में लेले और इक्की दुक्की इस तरह की घटनाओं पर जनता इस प्रकार के काम करे यह जनता का काम नहीं है। हमारा यह कर्तव्य अवश्य है कि हम जनता को इस सम्बन्ध में समझायें परन्तु उसी के साथ मैं फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जनता के नेता हैं हम गुंडों के नेता नहीं हैं। जहां तक गुंडों का सवाल है वहां तक गुंडों का दमन तो सरकार के द्वारा ही हो सकता है।

उस सम्बन्ध में जबलपुर में जो कुछ हुआ, जो कुछ मुझे वहां अनुभव हुआ उस के आधार पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। जबलपुर में यह दंगा शुरू हुआ ३ फरवरी को। ४ फरवरी को इधर उधर कुछ घटनाएं हुईं। २ दिन तक जबलपुर में पूरी शान्ति रही, बाजार खुल गये, कोई गड़बड़ वहां पर नहीं हुई। ७ तारीख को यकायक गड़बड़ शुरू हुई। ४ जगह यकायक झगड़े शुरू हुए। चार जगह यकायक इकट्ठे झगड़े तब तक नहीं हो सकते थे जब तक कि उसकी कोई पूर्व योजना न बनती और मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि यद्यपि ७ तारीख के बाद पुलिस ने बड़ी तंदेही के साथ काम किया लेकिन ४ जगहों पर इकट्ठा उभाड़ने वाले झगड़ों का पता जबलपुर की सी० आई० डी० को कैसे नहीं लगा। स्पष्ट चीज है कि यह उस की कमजोरी है। क्योंकि यकायक इकट्ठे झगड़े नहीं हो सकते थे जब तक कि उनके कोई तैयारी न हुई होती। इस प्रकार की तैयारी का सी० आई० डी० को पता

लगना चाहिए था । इसलिए जहां तक हमारी सी० आई० डी० का सम्बन्ध है जबलपुर, मध्यप्रदेश और दूसरे स्थानों में उसको कहीं ज्यादा तंदेही के साथ काम करना चाहिए ।

अब मैं पुलिस पर आता हूं । मैंने आप से निवेदन किया कि ७ तारीख के बाद जबलपुर में जो कुछ हुआ पुलिस ने बड़ी तंदेही के साथ काम किया । इस में कोई शक नहीं है कि अगर पुलिस इतनी तंदेही के साथ काम न करती तो वहां न जाने क्या हो जाता । लेकिन इस के पहले पुलिस को जबलपुर के पुलिस अफसरों को जबलपुर का अनुभव बहुत कम था । पुराना एक कायदा था कि कलक्टर, जिला मजिस्ट्रेट्स वह लोग होते थे जो बहुत दिन तक किसी जिले या किसी शहर में रह चुकते थे । पुलिस कप्तान वह लोग होते थे जो किसी जिले या किसी शहर में बहुत दिनों तक रह चुके होते थे और सिटी कोतवाल वह लोग होते थे जोकि उस शहर में किसी न किसी रूप में बहुत दिन तक रह चुकते थे । उन को एक एक बात का ज्ञान रहता था । एक एक बात का अनुभव रहता था और वे वहां के लोगों को जानते थे । यहां पर मैं किसी एक अफसर विशेष की निन्दा नहीं करना चाहता, सब अच्छे आदमी हैं लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि दुर्भाग्य से इस समय जबलपुर में जो अफसर थे वह जबलपुर के मुहल्लों तक को नहीं जानते थे वहां की जनता की बात तो अलग है । हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे अफसरान को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में या कलक्टर के रूप में या पुलिस कप्तान अथवा सिटी कोतवाल के रूप में रखें जोकि उस स्थान की अच्छी जानकारी रखते हों । एक एक मुहल्ले को एक एक मकान को और एक एक आदमी को जानते हों ।

पत्रों की स्वाधीनता के नाम पर आजकल न जाने क्या-क्या लिखा जा रहा है । यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, यह भाषण की स्वतन्त्रता और यह पत्रों की स्वाधीनता हमको कहां तक ले जायेगी मेरी समझ में नहीं आता । गाली-गलौज से देश के यहां से लेकर वहां तक के न जाने कितने पत्र भरे रहते हैं । यह गालीगलौज व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़कर बहुत उग्र रूप धारण कर रहा है । जबलपुर की छोटी-छोटी घटनाओं को इतने अधिक अतिरंजित रूप से पत्रों में छापा गया । सब पत्रों को मैं नहीं कहूंगा, कुछ पत्रों में छापा गया । उसका बहुत असर पड़ा और अफवाहें फैलीं । सात तारीख को जो कुछ वहां हुआ उन अफवाहों के कारण सागर में और आसपास के स्थानों में न जाने क्या-क्या हो गया । हमें ऐसी अनर्गल जो छपाई होती है पत्रों में और जो यह अफवाहें फैलाते हैं उसके लिए भी कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए । उस का पूरा निवारण तो उपाध्यक्ष महोदय नई पीढ़ी के ठीक निर्माण पर ही हो सकता है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें ।

डा० गोविन्द दास : बहुत अच्छा ।

हम जानते हैं कि नई पीढ़ी का निर्माण यह सब से अधिक आवश्यक बात है । जर्मनी और इटली में हिटलर और मुसोलिनी के समय नई पीढ़ी का इस प्रकार निर्माण किया गया था कि वहां की नई पीढ़ी नाजीवाद और फासिस्टवाद तक का भी समर्थन करने लगी थी । हमें अपनी नई पीढ़ी का इस प्रकार निर्माण करना चाहिए कि कोई यह न समझे कि हम हिन्दू हैं और हम मुसलमान हैं या हम सिक्ख हैं और ईसाई हैं बल्कि सब लोग समझें कि हम भारतीय हैं ।

एक बात मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है और दो घंटियां बज चुकी हैं ।

डा० गोविन्द दास : मैं आपकी आज्ञा से दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

मैं सदन् का ध्यान पाकिस्तान के प्रेसीडेंट श्री अय्यूब खां के उस भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में उन्होंने कहा कि जबलपुर की यह घटना कांगो की घटना के समान है, ऐसा उनका कथन हास्यास्पद है और इस प्रकार का मिलान मेरी तो समझ में नहीं आता । जनरल अय्यूब साहब किस तरीके से यह बात कह सके ? भारत में हमने एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है । बड़े से बड़े ओहदों पर यहां मुसलमान रहे हैं और आज भी हैं । हमारी सरकार हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं समझती । पाकिस्तान वाले इस प्रकार की बात हमारे लिये कहें । इससे बड़ी ज्यादती की बात और कोई नहीं हो सकती और इससे ज्यादा हमको बदनाम करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है । उन को खुद पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए । सैकड़ों, हजारों की संख्या में पाकिस्तान के हिन्दू हिन्दुस्तान में आ रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, इसके भी कारणों का क्या उन्होंने पता लगाया ? अय्यूब साहब का जो भाषण हुआ वह एक ऐसा भाषण हुआ जिससे हमारे देश को दुनिया में बदनाम करने का प्रयत्न तो किया ही गया साथ ही इस बात का भी प्रयत्न हुआ कि हमारे देश में भी हमारे मुख पर कालिख लगायें और मैं समझता हूं कि उन्हें अय्यूब साहब को खुद को इस पर अफसोस होना चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमारा प्रजातंत्र, हमारे समाज की समाजवादी रचना और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता आदि सब कुछ इस एकता पर निर्भर है । मैं ने अनेक बार पहले भी कहा है और अन्त में मैं फिर कहूंगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सब दल मिल कर कर सकते हैं । राष्ट्रीय एकता के लिए सब दलों का सहयोग आवश्यक है और सब दलों को मिल कर इस एकता का प्रयत्न करना चाहिए ।

श्री मु० हि० रहमान (अमरोहा) : जनाब डिप्टी स्पीकर, प्रेसीडेंट के ऐड्रेस पर कल से बातचीत हो रही है । मिली जुली चन्द बातें हैं जिन को अपने अपने खयाल के मुताबिक हर एक पेश कर रहा है ।

जहां तक चीन का मामला है मैं समझता हूं कि उस के मुताल्लिक मुख्तलिफ तरीकों से हाउस में दूसरे वक्त भी बहस हुई है । यह एक खुली हुई हकीकत है जिस में दो रायों की गुंजाइश नहीं है । यह चीन जिसके मुताल्लिक हिन्दुस्तान ने हर मौकिफ पर, हर ठहराव और हर मौके पर पूरे तरीके से उस का साथ दिया उस चीन ने, चीन की हुकूमत ने, मौजूदा चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत ने हिन्दुस्तान के साथ बहुत बेवफाई की और इंतिहाई शराफत से गिरी हुई जिन्दगी का सबूत दिया ।

जहां तक बार्डर का मसला है, हमारी हद एक लम्बी लकीर है मैकमाहन लाइन और इस तरफ़ काश्मीर की वे हुदूद हैं, जो कि इस मुल्क की सरहद तक हैं । चीन की तरफ़ से बार-बार उन के बारे में छेड़ की जाती है, ऐसे कदम उठाये जाते हैं, जिस से हिन्दुस्तान के मकसद और काज को नुक्सान पहुंचे । इन हुदूद को मुग़लों के ज़माने से आज तक बग़ैर किसी इख्तलाफ़ के हिन्दुस्तान की हुदूद माना गया है । आज उन के बारे में बहस करना और हिन्दुस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करना और जिस हिस्से पर उस ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, उस को अपने मुल्क का हिस्सा बताना, ये ऐसी चीजें हैं, जो यह ज़ाहिर करती हैं कि दुनिया में, ज़िन्दगी में जब अखलाक न हो, रूहानियत न हो, सिर्फ मादियत ही मादियत पेशे-नज़र हों, तो जितना भी कुछ हो, वह कम है ।

ऐसे मौके पर इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि इस मसले को हल करने के दो ही तरीके हैं—यातो हम जंग करें और या दूसरे तरीकों से अपना मकसद हासल करने की कोशिश करें। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर

और हर एक अक्लमन्द आदमी यह सोचता है कि आज के ज़माने में यह जंग सारी दुनिया की जंग हो सकती है और बड़ी बड़ी तहजीबें बरबाद हो सकती हैं। इसलिये एक दूसरे तरीके से उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट की इस पालिसी को हम सपोर्ट करते हैं और पूरे तरीके से इत्तिफाके-राय करते हैं कि वह इस तरज़ पर चल रही है कि एक तरफ वह मजबूत है कि वह एक इंच जमीन भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देंगे और दूसरी तरफ उसने इरादा कर रखा है कि अगर किसी मुल्क की तरफ से कोई जारहाना कार्रवाइयां हुईं, तो उसका सामना किया जायेगा और जो कार्रवाइयां इस सिलसिले में हो चुकी हैं, उनको हल करने की कोशिश की जायेगी। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ?

बाहर के मामलात के सिलसिले में कांगों पर बहस हुई है। बेशक वह एक मज़लूम कौम है और मज़लूमों का साथ देना हमारा शेवा, हमारा शिआर और हमारी आदत है। हम बराबर ऐसा करते रहे हैं और आज भी कांगो के मामले में हम उसी तरफ हैं, जहां पबलिक का रुजहान है। वहां पर बेलजियम की तरफ से कालोनियलिज्म का जो ग़लत, भयानक और घिनौना मजाहिरा किया जा रहा है, वह नाकाबिले-बर्दाश्त है। वहां पर एक फ़ारेन ताकत ने मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को तबाह करवाने की कोशिश की है और इसी सिलसिले में मि० लुमुम्बा और उनके कुछ साथियों को कत्ल कर दिया गया है।

इन बातों के मुताल्लिक, फ़ाइवयीअर प्लान के मुताल्लिक पंचायत राज के मुताल्लिक कहने के लिए बहुत से मौके हैं, कहा जाता रहा है और कहा जाता रहेगा। लेकिन एक बहस खुद-ब-खुद हाउस के सामने आ गई है और आनी चाहिए थी। मैं भी उस पर कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस बात को देख कर मायूसी हुई कि ३ तारीख से लेकर ९ तारीख तक जबलपुर, कटनी, सागर दमोह, नरसिंहपुर, सरोपा और कितने ही मुकामात पर फसाद हुए और बरबादी हुई, आगें लगीं, मकान बरबाद हुए और दुकानें जलाई गईं और जानो माल का नुकसान हुआ, लेकिन २४ तारीख को प्रेज़िडेंट साहब का जो एड्रेस आता है, उस में एक लाइन भी इस सिलसिले में हमारे सामने नहीं आई है। उसमें इस बात का कोई ज़िक्र नहीं किया गया कि इस बारे में क्या तरीका-ए-कार अख्तियार किया जायगा, जिससे इस किस्म के वाकयात फिर न हों, क्योंकि किसी सैकुलर स्टेट के लिये इससे ज्यादा नदामत और शरमिन्दगी की कोई बात नहीं हो सकती कि वहां साम्प्रदायिकता, फिरकापरस्ती, इस तरह मुंह खोले खड़ी रहे और शुरू से आखिर तक उसका सिलसिला कहीं न कहीं जारी रहे और हम उसको रोक न सकें।

जबलपुर में एक वाकया हुआ—एक इंडिविडुअल वाकया, एक इन्तहाई शर्मनाक वाकया हुआ, जिसकी सज़ा ज़िम्मेदार शख्स को मिलनी चाहिए, लेकिन एक्शन और रीएक्शन का यह मतलब कभी नहीं हो सकता कि एक इंडिविडुअल ने एक बात की हो, तो पूरी कम्युनिटी को तबाह और बरबाद कर दिया जाये। यह तरीका-ए-कार किसी तरीके से मुल्क के मफाद में नहीं है, बल्कि वह इन्तहाई नुक्सानदेह है। इसी बिना पर यह बात बहुत काबिले-तवज्जह है कि पिछले दिनों में इसी मध्य प्रदेश में भोपाल में जो फिसाद हुआ था, वहां पर किसी को सज़ा नहीं मिली, किसी मुजरिम को उसकी खता पर पकड़ा नहीं गया, किसी गुंडे और शरारतपसन्द को सज़ा नहीं दी गई। इस हालत में मुख्तलिफ मुकामात में फसादात हुए हैं और वे लोग समझते हैं कि हम खुले दिल से मनमानी कर सकते

[श्री मु० हि० रहमान]

हैं जो कुछ चाहे कर सकते हैं, हुकूमत हमारे मुकाबले में बेबस है और कुछ नहीं कर सकती है। इसके सिवा दूस ी कोई बात नहीं है।

मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इन फसादात को हिन्दू-मुस्लिम फसादात कहना हिन्दुओं और मुसलमानों की तौहीन करना है। ये फसाद हिन्दू और मुसलमान नहीं करते हैं। मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूं कि वहां की पब्लिक, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल हैं, आज भी कानों पर हाथ धर रही है कि यह बला, यह मुसीबत, यह अज़ाब कहां से नाजुल हुआ। ये हिन्दू-मुस्लिम फसाद नहीं हैं। इनको फिरका-वारना फसाद कहना भी गलत है। गुंडों और शरारतपसन्दों ने एक स्कीम बनाई है और उस स्कीम के मातहत वे जब चाहे तब फसाद करते हैं। दरहकीकत इसमें कोई शक नहीं है कि जब एन्कवायरी होगी, तो यह बात साफ हो जायेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जान-बूझ कर उसमें चशमपोशी की, या मातहत पुलिस के अफराद ने साथ देकर बरबादी कराने की कोशिश की। उस वक्त हुक्काम ने, लोकल हुक्काम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कमजोरी भी दिखाई और इस साजिश में उनका हिस्सा भी दिखाई देता है। बकौल सेठ जी के ३, ४ तारीख को यह वाकया पेश आया था और उसकी रोक थाम हो सकती थी, लेकिन समझ में नहीं आता कि स्पेशल पुलिस के जो दस्ते बुलाये गये थे, वे क्यों वापस चले गये, जिसके नतीजे में ७ तारीख और ८ तारीख की दरमियानी रात को इस कद्र हौलनाक बरबादी हुई। जान-बूझ कर एक साइड की इस तरीके से बरबादी कराई जाये, यह किसी तरीके से भी हिन्दुस्तान के लिये ज़ेबा नहीं है। हम पाकिस्तान और अयूब के खिलाफ ऐतराज़ करें। वह हमारा हक है। कोई हमारे मामले में दखल न दे। हम में इतनी ताकत है कि हम अपने हिन्दुस्तान में अपने मामलात को हल कर सकते हैं। जिन्होंने हिन्दुस्तान की आज़ादी की जद्दो-जहद में जान की बाज़ी लगा कर, साथ साथ शरीक होकर मुल्क को आज़ाद कराया है, जिन्होंने वन नेशन थ्योरी को मानने के लिये जान की बाजियां लगाई ह, अपनों से गालियां खाई हैं, जेलें भुगती हैं, चाकू खाये हैं, उनको आज इन बातों से कोई डर नहीं हो सकता कि जब भी कोई ऐसी फ़िसाद की मनमानी बात आय, मुस्लिम अक्लीयत की तकलीफ की बात आय, तो अखबारों या तकरीरों में, फ़ौरन पाकिस्तान के हवाले दे दिये जायें, पाकिस्तान रेडियो के हवाले दे दिये जायें और यह साबित करने की कोशिश की जाये कि इसका पाकिस्तान से जोड़ था, इसका फलां चीज़ से जोड़ था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से हकीकत को दबाया नहीं जा सकता है और अगर इस तरीके से हकीकत को दबाने की कोशिश की जायेगी, तो इससे मुल्क को कोई भी लाभ और फ़ायदा नहीं हो सकता, बल्कि मुल्क को इन्तहाई नुक्सान हो सकता है।

इस हालत में हमें इस बात का क्या खौफ़ है कि कोई क्या कहता है और पाकिस्तान के साथ जोड़ने का टैक्नीक क्यों अपनाया जाता है। हम इसके खिलाफ जरूर आवाज उठायेंगे। क्या हर जगह ज़ुल्म और बरबादी होती रहेगी और अगर उसके बारे में मुसलमान अक्लीयत किसी बात को कहेगी, तो यह कह कर उसका मुंह बन्द किर दिया जायेगा कि पाकिस्तान से जोड़ है, पाकिस्तान रेडियो से जोड़ है। इस तरह से हकीकत को दबाया नहीं जा सकता है। यह बात कोई मानी नहीं रखती कि इस तरीके से इस एक अक्लीयत को दबाने की कोशिश की जाये। यह देखने की बात है कि जबलपुर में एक साइड की इस तरह बरबादी क्यों हुई। जबलपुर में

दो जानिब से कोई बात हुई हो, मगर इसका कोई सबूत नहीं मिलता । लेकिन तो भी यह बताया जाये कि किस तरह ६ तारीख को सागर, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, सरोपा और तमाम दीगर मुकामात पर बारह से चार बजे तक साज़िश से सैंकड़ों मकान जला कर खाक कर दिये गये । क्या पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूद होते हुए कोई इस तरीके से बरबादी कर सकता है ? इत्मीनान के साथ पेट्रोल छिड़का गया, इत्मीनान के साथ आग लगाई गई और बड़ी बड़ी किलानुमा इमारतें खाक सियाह कर दी गईं । एक एक इन्सान का दस दस बारह बारह लाख का नुक्सान हुआ । कालेखां मुहमद हनीफ़ की फ़र्म कोई मामूली फ़र्म नहीं थी । दस बारह लाख का का उसका नुक्सान हो गया । उसकी बीड़ी की तिजारत थी । वह मुसलमानों के हाथ में थी । उसको इक्तसादी मार मार कर बरबाद कर दिया गया । फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियों की तिजारत थी । वहां मुसलमानों की सनअतो-हिरफ़त को तबाह किया । क्या कुछ फ़िरकापरस्त अनासर ने यह तय कर लिया है कि इस तरीके इस से मुसलमानों को, जो मौजूदा इकानोमिक्स और इक्तसादियत में खुद बदहाल हैं, इस मुल्क में बिल्कुल तबाह कर के भिखारी और फ़कीर बना कर छोड़ दें और यह हुकूमत बेबस हो, बेचारा हो, कुछ कर न सके, सब कुछ हो जाये, तो फिर उसकी एन्क्वायरी होती फिरे और उसके बाद यह करो, वह करो । आखिर इतना बड़ा वाकया हो कैसे गया ? तीन ज़िलों में बारह जगह ऐसे वाकयात कैसे हो गये ? हुकूमत को इस पर ग़ौर करना चाहिए ।

मुझे अब इस बात का अहसास हो रहा है कि इन मामलात में कब तक तसलसल जारी रहेगा । क्या पूरे हिन्दुस्तान को इस में लपेट दिया जायेगा । अभी दो तीन दिन पहले दिल्ली में भी यही टैक्नीक चली थी, लेकिन वहां के हिन्दू और मुसलमान, हम लोग, जो वहां रहते हैं, ११ बजे रात को वहां पहुंच कर तीन बजे तक रहे और हिन्दू लीडरों के साथ, जो वहां मौजूद थे, इस बात की कोशिश की कि इस वाकये को मामूली तौर पर खत्म करके इसको किसी तरीके से आगे न बढ़ने दिया जाये । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिनके पास ताकत, शक्ति और माइी पावर नहीं है, जब वे इस तरीके से मामले को हल कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत के अफ़राद, लोकल अथारिटीज़ अगर चाहें, तो क्या अमन कायम नहीं हो सकता ? हुकूमत बेबस नजर आती है और शरारत पसन्द लोग जो कुछ चाहते हैं कर गुजरते हैं । आज सब मामलों में उनकी मुख़ालिफत करने के बजाय उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाती है। जोर शोर के साथ पार्लिमेंट में यह तो कहा जाता है कि फिरकापरस्ती को किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं किया जायेगा । लेकिन हो क्या रहा है ? मुस्लिम अक्लीयत तबाह भी हो रही है और बरबाद भी हो रही है । एक्शन और रिएक्शन के नाम पर शरारतपसन्द लोग जो चाहते हैं करते जा रहे हैं । इस तरह की बातें होने देना किसी भी सैक्युलर स्टेट के लिए मुनासिब नहीं है और न हो सकता है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम अक्लियत का मुलाज़मतों में क्या हाल है ? क्या आप ने कभी इसकी तहकीकात की है कि इनमें अक्लियतों को क्यों नहीं लिया जा रहा है । क्या अक्लियतों के जितने भी बच्चे हैं, मुसलमानों के जितने भी बच्चे हैं, ईसाइयों व सिखों के जितने भी बच्चे हैं वे इतने ही नालायक हो गए हैं कि उनके लिए जगह ही नहीं है । स्टेट गवर्नमेंटस के गजट छपे हुए हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया के गजट छपे हुए हैं, बताया जाए कि इन पिछले चौदह सालों में अक्लियतों के कितने लड़के नौकरियों में लिए गए हैं । पहले तो इनको इंटरव्यू में ही नहीं बुलाया जाता है और अगर बुला भी लिया जाता है तो उनको जगह नसीब नहीं

[श्री मु० हि० रहमान]

होती है । वे तबाह और बरबाद हो रहे हैं । मैं मानता हूं कि यह रिजर्वेशन का सवाल नहीं है । लेकिन अगर कोई ऐसे हालात में रिजर्वेशन की बात कहता है, रिजर्वेशन की बात को उठाता है तो उसे फिरकापरस्त कहा जाता है और इसी बिना पर कहा जाता है कि उसने रिजर्वेशन का लफ्ज क्यों कह दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि सैक्युलर स्टेट के वे लोग क्या फिरकापरस्त नहीं हैं जो न यह चाहते हैं कि मुसलमानों को मुलाजिमत में लिया जाए, उनको तबाह और बरबाद किया जाए, उनकी इक्तसादयात, उनके तरीके जिन्दगी को खत्म किया जाए ? मुस्लिम अाक्लियत को यानी एक कम्युनिटी को दबाने के लिए न मुलाजिमत में लिया जाता है न तजारत करने दिया जाता है न उनको अपनी इक्तसादी जिन्दगी को जारी रखने का हक दिया जाता है, रोजमर्रा की जो शहरी जिन्दगी है, जो अमन की जिन्दगी है, उस तक को भी देने के लिए वे तैयार नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे ज्यादा भी कोई फिरकापरस्ती दूसरी हो सकती है ? इसका क्या मतलब है ? मैं यह नहीं कहता कि अकसरियत के सभी लोग बुरे हैं, उसमें से थोड़े बुरे हैं । इसमें हिन्दू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है, हिन्दू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है, दोनों गले मिलने के लिए तैयार हैं । लेकिन चन्द शरारत-पसन्द लोग अकसरियत में ऐसे हैं जो कि अक्लियतों को इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं । अगर उनकी हाउस में भी मुख्तलिफ तरीकों से हौसला अफजाई की जाए तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा ? कैसे हमारी स्टेट सैक्युलर स्टेट बन सकेगी ? आखिर सैक्युलर स्टेट का मतलब क्या है ? सिर्फ सैक्युलर स्टेट कह देने से वह सैक्युलर स्टेट नहीं बन जाती है ? इसका मतलब यह है कि रोजमर्रा की जो जिन्दगी है, उसको बसर करने का सभी को हक हासलि हो, मुलाजिमत सभी को पाने का हक हो, तजारत करने का सभी को हक हासलि हो । क्या वजह है कि आज अकलियतों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, मुल्क की इक्तसादियात में, तजारत में परमिट नहीं मिलते हैं, फाइव यीअर प्लान में कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ को जो जगह मिली हुई है, उनके बारे में इनको मायूसी का मुंह देखना पड़ता है ।

इसी तरह टैक्स्ट बुक्स की बात है । इसके बारे में हमने एक शिकायत की थी और वजीर तालीम को एक किताब दिखाई थी और उन्होंने हमारी शिकायत को सही तसलीम किया था और कहा था कि इस किस्म की किताबें नहीं पढ़ाई जानी चाहिये । सवाल यह नहीं है कि हे कि त्यौहारों का उनमें क्यों जिक्र किया गया है, दीवाली का क्यों जिक्र किया गया है, दशहरा का क्यों जिक्र किया गया । ये सब हिन्दुस्तान के त्यौहार हैं । किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता है । लेकिन जहां अकसरियत के त्यौहारों का जिक्र है वहां मुसलमानों के जो त्यौहार हैं, ईद है, बकरीद है, शब बरात है या मुहर्रम हैं, या सिखों के त्यौहार हैं, ईसाइयों के त्यौहार हैं, उनका भी उनमें जिक्र होना चाहिये था । अगर यह किया गया होता तो यह सैक्युलर स्टेट के उसूलों के एन मुताबिक होता । इस के बरखिलाफ उस तरह की बात उन किताबों में लिखी हुई मिलती है कि आओ बच्चों भगवान कृष्ण की पूजा करें । आप बतायें कि मुसलमानों के बच्चे यह कैसे करेंगे । भगवान कृष्ण की पूजा हिन्दू कर सकते हैं लेकिन मुसलमान, सिख, ईसाई कैसे कर सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें पढ़ाने का अकलियतों के बच्चों को आपको किस ने हक दिया है । मुसलमान अपने खुदा-वंद कुद्दूस की अदावत करते हैं, सिख अपने तरीके से करते हैं और ईसाई अपने तरीके से और उनको इसका पूरा हक हासिल है । आपको किस ने हक दिया है कि आप दूसरे मजहबों की तौहीन करें, खुदा व रसूल

की तौहीन करें और यह प्रचार करें कि वे सब इस तरह की चीज़ों को पढ़ें । आपको नहीं चाहिये था कि आप किताबों में इस तरह के मजामीन लिखवाते और इस तरह की क़िताबों को टैक्स्ट बुक्स में जगह देते । मगर टैक्स्ट बुक कमेटी ने यह किया और उसने इस तरह की किताबों को चुना । हमें मालूम है कि महज बाज़ रिश्तेदारों से, बाज़ अपने जानने वालों से इस तरह की चीजें लिखा दीं जो अगर्चे तासुब की बिना पर नहीं लिखी गई, तंग नज़री की बिना पर नहीं लिखी गई बल्कि ना-वाकफियत की वजह से लिखी गई हैं । मैंने एक लिखने वाले से इसके बारे में पूछा और उसने मुझे बताया कि मैं इसलाम के बारे में जानता नहीं था इसलिये ऐसा ही लिख दिया है । चूंकि टैक्स्ट-बुक कमेटी में किसी का कोई रिश्तेदार आ गया तो उसकी सिफारिश से यह किताब टैक्स्ट बुक में आ गई । ऐसी किताबें नहीं आनी चाहियें और इस तरह की चीज़ों को उसमें जगह नहीं मिलनी चाहिये । इस तरह की चीजों के खिलाफ हम बोलेंगे । सैक्युलर स्टेट के अन्दर इस किस्म की किताबें खास तौर पर बेसिक एजुकेशन के अन्दर और प्राइमरी तालीम के अन्दर हर्गिज हर्गिज नहीं लगनी चाहिये, नहीं पढ़ाई जानी चाहियें ।

सेठ जी ने जमीयत उलेमा के बारे में कहा कि वह बेहतरीन बाडी है और इसने हिन्दुस्तान की आज़ादी में नुमायां हिस्सा लिया है लेकिन उज्जैन में ऐसी तकरीरें की गई जिन को पढ़कर हैरानी होती है । मैं कहता हूं कि जो मैं आज कह रहा हूं वही कुछ वहां कहा गया है । मैं इस बाडी के लिए जिम्मेदार हूं, मैं इसकी तजवीजों और इसकी तकरीरों के लिए जिम्मेदार हूं । उन में कोई भी बात नैशनलेलिटी के खिलाफ, सैक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं कही गई है । वहां पर यह शिकायत की गई है कि मुस्लिम अक्लियत को दाबाया जा रहा है, फिरकापरस्ती उभरती जा रही है और हुकूमत बेबस होती जा रही है । मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें कहने में कौन सी एतराज़ की बात हो सकती है । जो कुछ कहा गया है ठीक कहा गया है । अगर आज इन बातों के लिए अक्लियत के हक में सेठ जी नहीं बोलते हैं, या रघुनाथ सिंह जी नहीं बोलते हैं, या दूसरे हिन्दू भाई नहीं बोलते हैं तो फिर मजबूर होकर हिफ़्जर्रहमान को बोलना पड़ता है । इसमें एतराज़ की क्या बात है । होना तो यह चाहिये था कि अकसरियत खुद इन चीज़ों को कहती । लेकिन अगर वह नहीं कहती है और हमें कहना पड़ता है कि अकलियतें तकलीफ़ में है, उनकी ये ये मजबूरियां हैं वे बेबस हैं, तो फिर इस पर क्यों एतराज होता है? बहरहाल इस तरह की चीज़ों को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । बेशक इसकी जरूरत है कि इनक्वायरी हो और हाई लेवेल इनक्वायरी हो । अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने कोताही की है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिये । आज मध्य प्रदेश की सरकार फेल्योर हुई है । भोपाल से ले कर अब तक के जो वाकयात हैं उनको देखते हुए यह कहना चाहिये कि उसे कोई हक हासिल नहीं है हुकूमत करने का । इस तरीके से तबाह और क़श करके, बरबाद करके हमें यहां रखा जाएगा तो यकीनी तौर पर इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे । मैं स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे कोई कानूनी पोजिशन ऐसी लायें जिससे असम और बंगाल के मामलात पर, लस्सानी फसादात की बिना पर जब यहां बहस हो सकती है पार्लियामेंटरी डेलीगेशन वहां जा सकता है, वैसे ही मध्य प्रदेश के फसादात के बारे में भी बहस हो । पी० एस० पी० ने, जमीयत उलउलेमा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के अफराद ने, सभी ने माना है कि बहुत बड़ी बरबादी आई है तीन जिलों के मुक्तलिफ हिस्सों में, और इस पर बहस होनी चाहिये और खुल कर बहस होनी चाहिये, इससे कोई नुक्सान नहीं होगा और अगर बहस हुई तो सफाई के साथ सारे मामलात सामने आयेंगे ।

[श्री मु० हि० रहमान]

तो तजवीज़ श्री भक्त दर्शन जी ने पेश की है, उसकी तो मैं ताईद करता हूं लेकिन जिन मामलात का मैंने जिक्र किया है उनके बारे में फिर से कहता हूं कि पाकिस्तान का हवाला दे कर आप बच नहीं सकते हैं, यह कह कर कि पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक, है, काम चल नहीं सकता है। यह कहा गया है कि नागपुर टाइम्स में रह लिखा है, मगर क्या आपने स्टेट्समैन में जो छपा है, उसको पढ़ा है, हिन्दुस्तान टाइम्स में जो छपा है, उसको पढ़ा है, टाइम्स आफ इंडिया में जो छपा है, उसको पढ़ा है? आपको चाहिये था कि आप उसको भी पढ़ते जिन्होंने कहा है कि सिर्फ एक साइड ही को बरबाद किया गया है। जो कुछ हुआ है उसका तकाज़ा था कि वहां कोलैक्टिव फाइंस लगते। जिस तरह की वारदातें हुई हैं, उनको कोई भी बरदाश्त नहीं कर सकता है। यह तरीका ज़िन्दगी का नहीं है। इस तरह के तरीकों को बदलना होगा और सही मानों में सैक्युलरिज्म को लाना होगा। गांधी जी के बताये हुए इखलाकी मैयार और नैशनलिज्म को लाना होगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि अकसरियत में सभी लोग बुरे हैं, कुछ बुरे हैं। अकसरियत में जो फिरकापरस्त हैं, वे जो कार्रवाई चाहें करें, मनमानी करें, खुश रहें और जो मुसलमान अकलियत में हैं, या दूसरी अकलियतें हैं, उनको हमेशा ही दबाने की कोशिश करें और पाकिस्तान का हवाला दे कर, उसको एक टैक्नीक के तौर पर इस्तेमाल करके, इस किस्म की हरकतें वे करते जायें, इसको कभी बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। इसको हम बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, हाउस बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, मैम्बर साहिबान बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। सभी को इसके खिलाफ आवाज़ बुलन्द करनी है और यह कोशिश करनी है कि सही मानों में यहां पर सैक्यूलरिज्म कायम हो।

[جناب ڈپٹی اسپیکر پریسیڈنٹ کے ایڈریس پر کل سے بات چیت ہو رہی ہے - ملی جلی چند باتیں ہیں جن کو اپنے اپنے خیال کے مطابق ہر ایک پیش کر رہا ہے -

جہاں تک چین کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق مختلف طریقوں سے ہاؤس میں دوسرے وقت میں بھی بحث ہوئی ہے - یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے جس میں دو رایوں کی گنجائش نہیں ہے - یہ چین جس کے متعلق ہندوستان نے ہر موقف پر ہر ٹھہراو اور ہر موقع پر پورے طریقے سے اس کا ساتھ دیا اس چین نے - چین کی حکومت نے - موجودہ چین کی کمیونسٹ حکومت نے ہندوستان کے ساتھ بہت بے وفائی کی اور انسانی شرافت سے گری ہوئی زندگی کا ثبوت دیا -

جہاں تک بارڈر کا مسئلہ ہے ہماری حد ایک لمبی لکیر ہے میکماہن لائن اور اس طرف کشمیر کی وہ حدود ہیں جو کہ اس ملک کی سرحد تک ہیں - چین کی طرف سے بار بار ان کے بارے میں چھیڑ کی جاتی ہے ایسے قدم اٹھائے جاتے ہیں جس سے ہندوستان کے مقصد اور کاز کو نقصان پہنچے - ان حدود کو مغلوں کے زمانے سے آج تک بغیر کسی اختلاف کے ہندوستان کی حدود مانا گیا ہے -

آج ان کے بارے میں بحث کرنا اور ہندوستان کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرنا اور جس حصہ پر اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اسکو اپنے ملک کا حصہ بتانا یہ ایسی چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دنیا میں زندگی میں جب اخلاق نہ ہو - روحانیت نہ ہو - صرف مادیت ہی مادیت پیش نظر ہو - تو جتنا بھی کچھہ ہو وہ کم ہے -

ایسے موقعہ پر اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں — یا تو ہم جنگ کریں اور یا دوسرے طریقوں سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں - آج ہمارے پرائم منسٹر اور ہر ایک عقلمند آدمی یہ سوچتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ جنگ ساری دنیا کی جنگ ہو سکتی ہے اور بڑی بڑی تہذیبیں برباد ہو سکتی ہیں - اس لئے ایک دوسرے طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے - گورنمنٹ کی اس پالیسی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور پورے طریقے سے اتفاق رائے کرتے ہیں کہ وہ اس طرز پر چل رہی ہے کہ ایک طرف وہ مضبوط ہے کہ ایک انچ زمین بھی کسی دوسرے کے ہاتھہ میں نہیں جانے دیگی اور دوسی طرف اس نے ارادہ کر رکھا ہے کہ اگر کسی ملک کی طرف سے کوئی جارحانہ کارروائیاں ہوئیں تو اس کا سامنا کیا جائیگا اور جو کارروائیاں اس سلسلے میں ہو چکی ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائیگی - اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے -

باہر کے معاملات کے سلسلے میں کانگو پر بحث ہوئی ہے - بیشک وہ ایک مظلوم قوم ہے اور مظلوموں کا ساتھہ دینا ہمارا شیوہ - ہمارا شعار اور ہماری عادت ہے - ہم برابر ایسا کرتے رہے ہیں اور آج بھی کانگو کے معاملے میں ہم اسی طرف ہیں جہاں پبلک کا رجحان ہے - وہاں پر بیلجیم کی طرف سے کالونیلزم کا جو غلط بھیانک اور گھنونا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے - وہاں پر ایک فارین طاقت نے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تباہ کروانے کی کوشش کی ہے اور اسی سلسلے میں مسٹر لممبا اور ان کے کچھہ ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے-

ان باتوں کے متعلق - فائیونو پلان کے متعلق - پنچایت راج کے متعلق کہنے کے لئے بہت سے موقعے ہیں - کہا جاتا رہا ہے اور کہا جاتا رہے گا - لیکن ایک بحث خود بخود ہاؤس کے سامنے آ گئی ہے اور آنی چاہئے تھی - میں بھی اس پر کچھہ کہنا چاہتا ہوں - مجھے اس بات کو دیکھہ کر مایوسی ہوئی کہ ۳ تاریخ

[شری م - ح - رحمان]

لیکر ۹ تاریخ تک جبلپور- کٹنی - ساگر - دموہ - نرسنگھ پور سرویا اور کتنے ہی مقامات پر فساد ہوئے اور بربادی ہوئی - آگیں لگیں - مکان برباد ہوئے اور دوکانیں جلائی گئیں اور جان و مال کا نقصان ہوا - لیکن ۱۴ تاریخ کو پریزیڈنٹ صاحب کا جو ایڈریس آتا ہے اس میں ایک لائن بھی اس سلسلے میں ہمارے سامنے نہیں آئی ہے - اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ اس بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائیگا جس سے اس قسم کے واقعات پھر نہ ہوں کیونکہ کسی سیکولر سٹیٹ کے لئے اس سے زیادہ ندامت اور شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہاں سامپردایکتا - فرقہ پرستی - اس طرح منہہ کھولے کھڑی رہے اور شروع سے آخر تک اس کا سلسلہ کہیں نہ کہیں جاری رہے اور ہم اس کو روک نہ سکیں -

جبلپور میں ایک واقعہ ہوا — ایک انڈیوجول واقعہ - ایک انتہائی شرمناک واقعہ ہوا - جسکی سزا ذمہ وار شخص کو ملنی چاہئے لیکن ایکشن اور ری ایکشن کا یہ مطلب کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انڈیوجول نے ایک بات کی ہو تو پوری کمیونیٹی کو تباہ اور برباد کو دیا جائے - یہ طریقہ کار کسی طریقے سے ملک کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی نقصان دہ ہے - اسی بنا پر یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ پچھلے دنوں میں اسی مدھیہ پردیش میں بھوپال میں جو فساد ہوا تھا وہاں پر کسی کو سزا نہیں ملی - کسی مجرم کو اسکی خطا پر پکڑا نہیں گیا - کسی غنڈے اور شرارت پسند کو سزا نہیں دی گئی - ان حالات میں مختلف مقامات میں فسادات ہوئے ہیں - اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کھلے دل سے من مانی کر سکتے ہیں جو کچھہ چاہے کر سکتے ہیں حکومت ہمارے مقابلے میں بےبس ہے اور کچھہ نہیں کر سکتی - اس کے سوا دوسری کوئی بات نہیں ہے -

میں ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ ان فسادات کو ہندو مسلم فسادات کہنا ہندوؤں اور مسلمانوں کی توہین کرنا ہے - یہ فساد ہندو اور مسلمان نہیں کرتے ہیں - میں آپ سے یقین کے ساتھہ کہتا ہوں کہ وہاں کی پبلک - جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں - آج بھی کانوں پر ہاتھہ دھر رہی ہے کہ یہ بلا - یہ مصیبت - یہ عذاب کہاں سے نازل ہوا - یہ ہندو مسلم فساد نہیں ہیں - ان کو فرقہ وارانہ فساد کہنا بھی غلط ہے - غنڈوں اور شرارت پسندوں نے ایک سکیم بنائی ہے اور اس سکیم کے ماتحت ہو جب چاہے تب فساد کرتے ہیں -

درحقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایلکوائری ہوگی - تو یہ بات صاف ہو جائیگی کہ ایڈمنسٹریشن نے جان بوجھہ کر اس میں چشم پوشی کی یا مداخلت پولیس کے افراد نے ساتھہ دے کر بربادی کرانے کی کوشش کی - اس وقت حکام نے لوکل حکام نے - ایڈمنسٹریشن نے اپنی کمزوری بھی دکھائی اور اس سازش میں ان کا حصہ بھی دکھائی دیتا ہے - بقول سیٹھہ جی کے ۴ - ۳ تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اسکی روک تھام ہو سکتی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ سپیشل پولیس کے جو دستے بلائے گئے تھے وہ کیوں واپس چلے گئے - جسکے نتیجہ میں ۷ تاریخ اور ۸ تاریخ کی درمیانی رات کو اس قدر ہولناک بربادی ہوئی - جان بوجھہ کر ایک سائڈ کی اس طریقے سے بربادی کرائی جائے - یہ کسی طریقے سے بھی هندوستان کے لئے زیبا نہیں ہے - ہم پاکستان اور ایوب کے خلاف اعتراض کریں - وہ ہمارا حق ہے - کوئی ہمارے معاملے میں دخل نہ دے - ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے هندوستان میں اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں - جنہوں نے هندوستان کی آزادی کی جدو جہد میں جان کی بازی لگا کر - ساتھ ساتھ شریک ہو کر ملک کو آزاد کرایا ہے - جنہوں نے ون نیشن تھیوری کو ماننے کے لئے جان کی بازی لگائی ہیں - اپنوں سے گالیاں کھائی ہیں - جوتیاں بھگتی ہیں - چاقو کھائے ہیں - ان کو آج ان باتوں سے کوئی ڈر نہیں ہوسکتا کہ جب بھی کوئی ایسی فساد کی من مانی بات کی جائے- مسلم اقلیت کی تکلیف کی بات آئے تو اخباروں یا تقریروں میں فوراً پاکستان کے حوالے دے دیئے جائیں- پاکستان ریڈیو کے حوالے دے دیئے جائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس کا پاکستان سے جوڑ تھا اس کا فلاں چیز سے جوڑ تھا - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے حقیقت کو دبایا نہیں جا سکتا ہے اور اگر اس طریقے سے حقیقت کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے ملک کو کوئی بھی لابھ اور فائدہ نہیں ہو سکتا - بلکہ ملک کو انتہائی نقصان ہو سکتا ہے -

اس حالت میں ہمیں اس بات کا کیا خوف ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ جوڑنے کا ٹھیکہ کیوں اپنایا جاتا ہے ہم اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے کیا ہر جگہہ ظلم اور بربادی ہوتی رہیگی اور اگر اس کے بارے میں مسلمان اقلیت کسی بات کو کہیگی تو یہ کہکر اس کا منہہ بند کر دیا جائیگا کہ پاکستان سے جوڑ ہے - پاکستان ریڈیو سے جوڑ ہے - اس طریقہ سے حقیقت کو دبایا نہیں جا سکتا ہے - یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اس طریقہ سے ایک اقلیت کو دبانے کی کوشش کی جائے - یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جبلپور میں ایک سائڈ کی اس طرح بربادی

[شی م - ح - رحمان]

کیوں ہوئی - جبلپور میں دو جانب سے کوئی بات ہوئی ہو مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن تو بھی یہ بتایا جائے کہ کس طرح و تاریخ کو ساگر - کٹنی- دموہ- نرسنگھپور- سرویا اور تمام دیگر مقامات پر بارہ سے چار بجے تک سازش سے سینکڑوں مکان جلا کر خاک کر دیئے گئے - کیا پولس اور ایڈمنسٹریشن کے موجود ہوتے ہوئے کوئی اس طریقے سے بربادی کر سکتا ہے - اطمینان کے ساتھ پیٹرول چھڑکا گیا- اطمینان کے ساتھ آگ لگائی گئی ا بڑی بڑی قلعہ نما عمارتیں خاک سیاہ کر دی گئیں - ایک ایک انسان کا دس دس - بارہ بارہ لاکھ کا نقصان ہوا - کالے خاں محمد حنیف کی کوئی معمولی فرم نہیں تھی - دس بارہ لاکھ کا اسکا نقصان ہو گیا - اس کی بیڑی کی تجارت تھی - وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی - اسکو اقتصادی مار مار کو برباد کر دیا گیا - فیروزآباد میں چوڑیوں کی تجارت تھی وہاں مسلمانوں کی صنعت و حرفت کو تباہ کیا گیا - کیا کچھ فرقہ پرست عناصر نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس طریقہ سے مسلمانوں کو - جو موجودہ اکانومکس اور اقتصادیت میں خود بد حال ہیں اس ملک میں بالکل تباہ کرکے بھکاری اور فقیر بناکر چھوڑدیں اور یہ حکومت بے بس ہو - بے چارہ ہو - اور کچھ کر نہ سکے - سب کچھ ہو جائے تو پھر اس کی ایکوائری ہوتی پھرے اور اس کے بعد

یہ کرو - وہ کرو - آخر اتنا بڑا واقعہ ہو کیسے گیا - تین ضلعوں میں بارہ جگہہ ایسے واقعات کیسے ہوگئے - حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیئے -

مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ان معاملات میں کب تک تسلسل جاری رہیگا - کیا پورے ہندوستان کو اس میں لپیٹ دیا جائیگا - ابھی دو تین دن پہلے دھلی میں بھی یہی ٹیکنیک چلی تھی - لیکن وہاں کے ہندو اور مسلمان- ہم لوگ جو وہاں رہتے ہیں ۱۱ بجے رات کو وہاں پہنچ کر تین بجے تک رہے اور ہندو لیڈروں کے ساتھ جو وہاں موجود تھے - اس بات کی کوشش کی کہ اس واقعہ کو معمولی طور پر ختم کرکے اس کو کسی طریقے سے آگے نہ بڑھنے دیاجائے - میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس - طاقت - شکتی اور مادی پاور نہیں ہے جب وہ اس طریقے سے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں تو ایڈمینسٹریشن - حکومت کے افراد - لوکل اتھارٹیز اگر چاہیں تو کیا امن قائم نہیں ہو سکتا -

مگر حکومت بے بس نظر آتی ہے اور شرارت پسند لوگ جو کچھ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں -

آج سب معاملوں میں ان کی مخالفت کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے - زور شور کے ساتھ پارلیمنٹ میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ

فرقہ پرستی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا - لیکن ہو کیا رہا ہے - مسلم اقلیت تباہ بھی ہو رہی ہے - اور برباد بھی ہو رہی ہے اور ایکشن اور ری ایکشن کے نام پر شرارت پسند لوگ جو چاہتے ہیں کرتے جا رہے ہیں - اس طرح کی باتیں ہونے دینا کسی بھی سیکولر اسٹیٹ کے لئے مناسب نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے -

میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم اقلیت کا ملازمتوں میں کیا حال ہے - کیا آپ نے کبھی اس کی انکوائری کی ہے کہ ان میں اقلیتوں کو کیوں نہیں لیا جا رہا ہے - کیا اقلیتوں کے جتنے بھی بچے ہیں - مسلمانوں کے جتنے بھی بچے ہیں عیسائیوں و سکھوں کے جتنے بھی بچے ہیں وہ اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ ان کے لئے کوئی جگہہ ہی نہیں ہے - اسٹیٹ گورنمنٹس کے گزٹ چھپے ہوئے ہیں - گورنمنٹ آف انڈیا کے گزٹ چھپے ہوئے ہیں - بتایا جائے کہ ان پچھلے چودہ سالوں میں اقلیتوں کے کتنے لوگ نوکریوں میں لئے گئے ہیں - پہلے تو ان کو انٹرویو میں ہی نہیں بلایا جاتا ہے اور اگر بلا بھی لیا جاتا ہے تو انکو جگہہ نصیب نہیں ہوتی ہے - وہ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں - میں مانتا ہوں کہ یہ رزرویشن کا سوال نہیں ہے - لیکن اگر کوئی ایسے حالات میں ریزرویشن کی بات کہتا ہے یا ریزرویشن کی بات کو اٹھاتا ہے تو اسے فرقہ پرست کہا جاتا ہے اور اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس نے ریزرویشن کا لفظ کیوں کہہ دیا - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیکولر اسٹیٹ کے وہ لوگ، کیا فرقہ پرست نہیں ہیں جو نہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ملازمت میں لیا جائے اور ان کو تباہ اور برباد کیا جائے - ان کی اقتصادیات اور ان کے طریقہ زندگی کو ختم کیا جائے - آج مسلم اقلیت کو بھی یعنی ایک کیمونٹی کو دبانے کے لئے نہ ملازمت میں لیا جاتا ہے نہ تجارت کرنے دیا جاتا ہے اور نہ ان کو اپنی اقتصادی زندگی کو جاری رکھنے کا حق دیا جاتا ہے - روز مرہ کی جو شہری زندگی ہے - جو امن کی زندگی ہے اس تک کو بھی دینے کے لئے وہ تیار نہیں ہیں - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ بھی کوئی فرقہ پرستی دوسری ہو سکتی ہے - اس کا کیا مطلب ہے - میں یہ نہیں کہتا کہ اکثریت کے سبھی لوگ برے ہیں - اس میں سے تھوڑے برے ہیں - اس میں ہندو مسلمان کا کوئی سوال نہیں ہے - ہندو مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے دونوں گلے ملنے کو تیار ہیں - لیکن چند شرارت پسند لوگ اکثریت میں ایسے ہیں جو کہ اقلیتوں کو اس طرح سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں - اگر ان کی ہاؤس میں بھی مختلف طریقوں سے حوصلہ افزائی کی جائے تو کیا ہوگا - کیسے کام چلے گا - کیسے ہماری اسٹیٹ سیکولر اسٹیٹ بن سکے گی - آخر سیکولر

شری م - ح - رحمان

اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے - صرف سیکولر اسٹیٹ کہہ دینے سے وہ سیکولر اسٹیٹ نہیں بن جاتی ہے - اس کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو بسر کرنے کا سبھی کو حق حاصل ہو - ملازمت سبھی کو پانے کا حق حاصل ہو - تجارت کرنے کا سبھی کو حق حاصل ہو - لیکن کیا وجہ ہے کہ اقلیتوں کو آج نوکریاں نہیں ملتی ہیں - ملک کی اقتصادیات میں - تجارت میں پرمٹ نہیں ملتے ہیں - فائیو ایر پلان میں کوآپریٹو سوسائٹیز کو جو جگہ ملی ہوئی ہے ان کے بارے میں ان کو مایوسی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے -

اسی طرح ٹیکسٹ بکس کی بات ہے - اس کے بارے میں ہم نے ایک شکایت کی تھی - اور وزیر تعلیم کو ایک کتاب دکھائی تھی اور انہوں نے ہماری بات کو صحیح تسلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ اس قسم کی کتابیں نہیں پڑھائی جانی چاہیں - سوال یہ نہیں ہے کہ تیوہاروں کا ان میں کیوں ذکر کیا گیا ہے - دیوالی کا کیوں ذکر کیا گیا ہے - دشہرہ کا کیوں ذکر کیا گیا ہے - یہ سب ہندوستان کے تیوہار ہیں - کسی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا - لیکن جہاں اکثریت کے تیوہار کا ذکر ہے وہاں مسلمانوں کے جو تیوہار ہیں عید ہے بقر عید ہے - شب برات کیا محرم ہے - یا سکھوں کے تیوہار ہیں عیسائیوں کے تیوہار ہیں - ان کا بھی ان میں ذکر ہونا چاہئیے تھا - اگر یہ کیا گیا ہوتا تو یہ سیکولر اسٹیٹ کے اصولوں کے عین مطابق ہوتا لیکن اس کے برخلاف اس طرح کی باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ آؤ بچو بھگوان کرشن کی پوجا کریں - آپ بتائیں کہ مسلمانوں کے بچے یہ کیسے کرینگے - بھگوان کرشن کی پوجا ہندو کر سکتے ہیں لیکن مسلمان - سکھ عیسائی کیسے کر سکتے ہیں - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں پڑھانے کا اقلیتوں کے بچوں کو آپ کو کس نے حق دیا ہے - مسلمان اپنے خداوند قدوس کی عبادت کرتے ہیں - سکھ اپنے طریقہ سے کرتے ہیں - عیسائی اپنے طریقہ سے اور ان کو اس کا پورا حق حاصل ہے - آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ دوسرے مذہبوں کی توہین کریں - خدا و رسول کی توہین کریں اور یہ پرچار کریں کہ وہ سب اس طرح کی چیزوں کو پڑھیں - آپ کو نہیں چاہئیے تھا کہ آپ کتابوں میں اس طرح کے مضامین لکھواتے اور اس طرح کی کتابوں کو ٹیکسٹ بکس میں جگہ دیتے مگر ٹیکسٹ بک کمیٹی نے یہ کیا اور اس نے اس طرح کی کتابوں کو چنا ہمیں معلوم ہے کہ مختص بعض رشتہ داروں

ہے - بعض جاننے والوں سے اس طرح کی چیزیں لکھوادیں - جو اگرچہ تعصب کی بنا پر نہیں لکھی گئیں - تنگ نظری کی بنا پر نہیں لکھی گئیں ہو بلکہ ناواقفیت کی وجہ سے لکھی گئی ہیں - میں نے ایک لکھنے والے سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس نے بتایا کہ میں اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تھا اس لئے ایسا ہی لکھ دیا ہے - چونکہ ٹیکسٹ بک کمیٹی میں کسی کا کوئی رشتہ‌دار آ گیا تو اس کی سفارش سے یہ کتاب ٹیکسٹ بک میں آ گئی - ایسی کتابیں نہیں آنی چاہئیں اور اس طرح کی چیزوں کو اس میں جگہ نہیں ملنی چاہئے اس طرح کی چیزوں کے خلاف ہم بولیں گے - سیکولر اسٹیٹ کے اندر اس قسم کی کتابیں خاص طور پر بیسک ایجوکیشن کے اندر اور پرائمری تعلیم کے اندر ہرگز ہرگز نہیں لگنی چاہیں نہیں پڑھائی جانی چاہیں -

سیٹھ جی نے جمعیت العلما کے بارے میں کہا کہ وہ بہترین باڈی ہے اور اس نے ہندوستان کی آزادی میں نمایاں حصہ لیا ہے - لیکن اجین میں ایسی تقریریں کی گئیں جن کو پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے - میں کہتا ہوں کہ جو کچھ میں آج یہاں کہہ رہا ہوں وہی کچھ وہاں کہا گیا ہے - میں اس باڈی کے لئے ذمہ‌وار ہوں - میں اس کی تجویزوں اور اس کی تقریروں کے لئے ذمہ‌وار ہوں ان میں کوئی بھی بات نیشنلیٹی کے خلاف سیکیولرزم کے خلاف نہیں کہی گئی ہے وہاں پر یہ شکایت کی گئی ہے کہ مسلم اقلیت کو دبایا جارہا ہے - فرقہ پرستی ابھرتی جا رہی ہے - اور حکومت بےبس ہوتی جا رہی ہے - میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کہنے میں کون سی اعتراض کی بات ہو سکتی ہے - جو کچھ کہا گیا ہے ٹھیک کہا گیا ہے - ان باتوں کے لئے اقلیت کے حق میں اگر آج سیٹھ جی نہیں بولتے ہیں یا رگھوناتھ سنگھ جی نہیں بولتے ہیں یا دوسرے ہندوستانی نہیں بولتے ہیں تو پھر مجبور ہوکر حفظ الرحمان کو بولنا پڑتا ہے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے - ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ اکثریت خود ان چیزوں کو کہتی - لیکن اگر وہ نہیں کہتی ہے اور ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اقلیتیں تکلیف میں ہیں - انکی یہ مجبوریاں ہیں - وہ بےبس ہیں تو پھر اس پر کیوں اعتراض ہوتا ہے - بہرحال اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے - بیشک اس کی ضرورت ہے کہ انکوائری ہو اور ہائی لیول انکوائری ہو - اگر ایڈمنسٹریشن میں کچھ لوگ اس کے لئے ذمہ‌وار ہیں - انہوں نے کوتاہی کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہئے - آج مدھیہ پردیش

[شری م - ح - رحمان]

کی سرکار فیلیور ہوئی ہے - بھوپال سے لے کر آج تک کے جو واقعات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا چاہئے کہ اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے حکومت کرنے کا - اس طریقے سے تباہ کرکے کرش کرکے - برباد کرکے ہمیں یہاں رکھا جائے گا تو یقینی طور پر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے - میں اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب سے درخواست کرونگا کہ وہ کوئی قانونی پوزیشن ایسی لائیں جس سے آسام اور بنگال کے معاملات پر لسانی فسادات کی بنا پر جب یہاں بحث ہو سکتی ہے - پارلمنٹری ڈیلیگیشن وہاں جاسکتا ہے - ویسے ہی مدھیہ پردیش کے فسادات کے بارے میں بھی بحث ہو - پی - ایس - پی نے جمعیت العلما - نے کمیونسٹ پارٹی نے - کانگریس کے افراد نے - سبھی نے مانا ہے کہ بہت بڑی بربادی آئی ہے تین ضلعوں کے مختلف حصوں میں - اور اس پر بحث ہونی چاہئے اور کھل کر بحث ہونی چاہئے - اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر بحث ہو تو صفائی کے ساتھ سارے معاملات سامنے آئیں گے -

جو تجویز بھکت درشن جی نے پیش کی ہے اس کی تو میں تائید کرتا ہوں لیکن جن معاملات کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں پھر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا حوالہ دے کر آپ بچ نہیں سکتے ہیں - یہ کہہ کر کہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے - کام چل نہیں سکتا ہے - یہ کہا گیا ہے کہ ناگپور ٹائمس میں یہ لکھا ہے - مگر کیا آپ اسٹیٹسمین میں جو چھپا ہے - اس کو پڑھا ہے - ہندوستان ٹائمس میں جو چھپا ہے اس کو پڑھا ہے - ٹائمس آف انڈیا میں جو چھپا ہے اس کو پڑھا ہے - آپ کو چاہئے تھا کہ آپ اس کو بھی پڑھتے جنہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک سائڈ ہی کو برباد کیا گیا ہے - جو کچھ ہوا ہے اس کا تقاضا تھا کہ وہاں کولیکٹیو فائنز لگتے - جس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں ان کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے - یہ طریقہ زندگی کا نہیں ہے - اس طرح کے طریقوں کو بدلنا ہوگا اور صحیح معنوں میں سیکولرزم کو لانا ہوگا - گاندھی جی کے بتائے ہوئے اخلاقی معیار اور نیشنلزم کو لانا ہوگا - میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اکثریت میں سبھی لوگ برے ہیں - اکثریت میں جو فرقہ پرست ہیں وہ جو کارروائی چاہے کریں - من مانی کریں - خوش رہیں اور جو مسلمان اقلیت میں ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں ان کو ہمیشہ ہی دبانے کی کوشش کریں اور پاکستان کا حوالہ دے کر - اسکو ایک ٹیکنیک کے طور پر

استعمال کرکے - اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے جائیں اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے -

اس کو ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں- ہاؤس برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے - ممبر صاحبان برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں - سبھی کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ صحیح معنوں میں یہاں پر سیکولرزم قائم ہو -

Shri A. K. Gopalan (Kasergod): I do not wish to refer to those points that have already been referred to by the leader of our group.

The President referred to the efforts of the Government to enable our democracy to share and participate at all levels in the great economic and social developments in this country. I want to point out that the experience is to the contrary. At least in some parts of the country, parliamentary democracy is functioning in such a way that the opposition is kept out of the important committees. In Kerala the Home Guards Committee has been formed for recruiting home guards, in which not even one opposition member has been included. If there are many opposition parties, and if at least one of them is represented, we can say that the opposition is included, but there is only one opposition party there, and not even one member is taken from the opposition in this important committee. I want to have an answer from the Government whether parliamentary democracy is functioning there and whether it is enabling our democracy to share and participate at all levels in the great economic and social developments. I could understand if this had been the case which only one committee, but in several committees, the Opposition has not been represented. For instance, the opposition is not represented on the Lok Sahayak Sena Committee and also on the Development Committees. Even if this be only in one part of the country, I want to know, since the President has expressed his desire that the Opposition should be taken into confidence why in the Development Committees and the other committees, not even one Member from the Opposition has been taken in. I want to have a clear answer from Government on this point, and I want to know whether they think that parliamentary democracy is developing and whether the spirit and essence of parliamentary democracy is being observed or is being violated at least in some parts of the country. I do not want to go into the other controversial questions, since I do not have much time.

14 hrs.

As far as appointments to Goveernment services are concerned, it is not the qualifications which are important but it is the police verification that has become important. If the police officer says that a certain person who is to be appointed is associated with certain ideas, then, certainly that man will not be appointed. Even if the public Service Commission recommends a person having the best qualifications, still, if the police officer gives some adverse report about him, he cannot be appointed in the services. This is continuing today. Though the Public Service Commission is there, it is the police officer's report that counts most.

I would also like to point out that the President has not given a true picture of the development in the country, because, after the two Five Year Plans, even though the production has increased, both industrial and agricultural, the national income has increased and the *per capita* income has also increased the gap between those who hold the means of production and those who produce has widened. The goal of our planning is a socialist pattern of society.

[Shri A. K. Gopalan]

In a socialist pattern of siciety, if there is more production, then there should not be more profits but the consumer must be able to get his good at lesser prices and the producers also must get some benefit, and there should be less of profits. I would give just two or three instances to prove how even though the national income has increased, the disparities have widened. Actually, there are two kinds of disparities, namely class disparities and regional disparities.

Take, for example, the case of the handloom industry. In the report, it is said that the production has increased. But what has been the result? The prices of goods have gone up; the prices of yarn also have gone up; and unemployment has increased. But, as far as the wages of the handloom workers are concerned, they have come down. So the result of this has been industrial unrest. In some places, due to the increase in the price of yarn, there is also unemployment. In Kerala and in Tamilnad and also Andhra Pradesh where there is concentration of handloom weavers, huge stocks are lying there, and they must be acquired especially the 'Bleeding Madras' variety. If arrangements are not made to supply yarn at reduced prices then the handloom owners will be in difficulties, and the workers will have to be sent out.

As regards the rebate of 10 nP which is given, it should be given for three weeks instead of 5 nP and 10 nP for two weeks. Unless the rebate is increased and the yarn is supplied at reduced prices, the worker will not be benefited though there is increase in production.

Then, I come to the conditions of agricultural labour, that is the agricultural labourers and the small peasants. It has been stated in the Report of the Second Enquiry into the conditions of Agricultural Labour in India that 69 per cent of the population, according to the 1950-51 census belong to this category. They have included also those who cultivate about 2 acres of land in this category of agricultural labour. The report of the enquiy shows that the condition of this rural population of 69 percent has not improved from 1950-51 to 1956-57; on the other hand, it has deteriorated. Since we shall be discussing this report, I do not want to go into details, but I want only to point out that the percentage of agricultural labour households with land in 1950-51 was 49·93 and 42·8 in 1956-57, while that of those without land was 50·07 in 1950-51 and 57·13 in 1956-57. That means that the number of the agricultural labourers and the small peasant's who have got households without land has increased, while that of those with land has come down.

In regard to the wages, at page 135 of the report, it has been stated:

> "The broad conclusions that emerge from a comparative study of the agrarian wage structure in 1950-51 and 1956-57 are: a general decline in the wages of the agricultudal labourers, a shift in the emphasis, payment of wages entirely in kind or partly in cash and partly of kind, greater dependence of agricultural labour families for wage income, a tendency towards widening of wage differentials as between the wages of men and women and a pronounced decline in the wages received for ploughing, transplanting and harvest operations. While the agricultural wages in 1950-51 were generally higher than non-agricultural wages, it was observed that in 1956-57 the position was the reverse."

This is the conclusion to which they have arrived at, as far as the wages are concerned.

As far as the debt position is concerned, while the percentage was 43

in 1950-51, it has increased to 63 per cent in 1956-57. The average debt for indebted households was Rs. 138 in 1956-57, as against Rs. 105 in 1950-51.

Therefore, I would point out that as far as the 69 per cent of the population in the rural areas is concerned, though the national income and the *per capita* income have increased, the report has come to the conclusion that not only have the wages not increased but, on the contrary, their debts have increased. Further, as a result of the land reform legislation and distribution of waste land what has happened is that 7 per cent out of this 69 per cent have lost their lands and they have not got any land today. I want Government to take note of these things and see that something is done to ameliorate their conditions.

The President has also referred to the Government servants. About 700 Government servants are even today victimised, and new notices are being given, though there is a definite order of Government that absence from duty without authority during the strike period, organising and leading a procession, addressing a meeting, instigating the staff to join the strike, not of a coercive type, using of slogans, issue and circulation of leaflets etc. do not come under gross misbehaviour and no action should be taken against such persons; in spite of this order, we find that even today, for saying Ordinance *murdabad*' or saying 'Change the vanity of Government', notices are given saying that the employees must show cause why they must not be dismissed from service. I would suggest that a committee must be set up to go into this question and see whether the orders have been implemented properly. In spite of the fact that there is a definite order that certain things will not be considered as gross misbehaviour, even today so many are being victimised, and new show-cause-notices are also being given. This will not certainly help in the smooth functioning of Government. I would repeat that a committee should be set up to go into this question and examine how the orders have been implemented.

Then I come to agricultural production. The President has spoken about increase in agricultural production. He has said that there is already an increase and we want more insrease. But as regards land reforms, how is it that they are implemented? What about ceiling? What about security to the ryot and the tenant? What about the laws which were passed on this? As far as these pieces of legislation are concerned, they have not helped. I also say that the matter of ceiling has become a farce—in many states this has become a farce. Not only that. has become a farce. Not only that. The Kerala Legislature passed a law saying that after December, 1957, that is, after the passing of the legislation, no land above the celling could be transferred and no land should be sold. But in 1960, the President issues an order saying that all those lands that had been transferred or sold would not come within the purview of this. Those who obeyed the law which put a ceiling on land and also prevented the sale or transfer of lands above the ceiling are punished and those who did not abide by the law are helped. That is what has become of the recommendation of the President himself as far as this legislation is concerned. In many places where a ceiling has been prescribed, there are loopholes. There is no restrictiton put that land over and above the ceiling should not be sold or transferred. So it has become a farce.

As far as the stoppage of eviction is concerned, legislation is there. But our experience and reports are to the effect that even though legislation is there even today in so many States the peasants are evicted with the help of the police. So unless Government are very careful and see that the legislation is implemented and the rightful owner who is in possession of the land is not evicted—unless he is protected, not the landlord—certainly this legislation will not help.

[Shri A. K. Gopalan]

As regards increase in production, there are certain other things that have got to be considered. In Kerala, about one lakh coconut trees are to be cut because of the root and stem disease. For the last three or four years, they had been told to use some pesticides etc., but now the Central Coconut Committee has said that one lakh trees should be cut and there should be new plantings. On the one side, they are cutting down the existing trees; on the other, they are told to plant new trees. I want to say that this is a national wealth. If no research can be done here to find out the disease and treat it, then some help must be got from outside.

This is not only with regards to coconut. Arecanut, pepper and all those agricultural products are affected and there is destruction of production due to certain diseases. This has been happening not yesterday or but for the last so many years. When lakhs of trees have been affected, the growers are told to cut down those trees and plant new ones. If this is the position with regard to agricultural production, the position will not improve and we will not have increased production.

Next I come to prices. If the cultivators do not get even the cost of production—the expenses of cultivation—how can they continue cultivation? Take for example tapioca. About two lakhs of agriculturists are cultivating it. They say that they do not get even the cost of production. Such is the price that they get for their produce. Starch is exported outside India also and we get some foreign exchange. But if a starch factory is established there, starch can be made here out of tapioca and they may also get some minimum price. Also more tapioca can be produced. I hope Government will see to it that as far as this is concerned, something is done so that we can earn foreign exchange as well as give a higher price to the cultivators.

Then I come to the queston of regional disparity. There is increase in the national income, but there is disparity between one zone and another, between one region and another and even between one part of a State and another part of the same State. For example in Kerala there is an agitation in which all parties have joined. There is disparity between the Malabar part and the other part. The agitation has come as a movement.

So this must be looked into. We have to see that development takes places on all sides. If one part of the country becomes less and less developed and the other goes up, certainly that will give rise to all sorts of tendencies and troubles. Those troubles are there in many places.

As regards unemployment, this subject has already been dealt with. I do not want to go further into it. But it is increasing. The internal and external debts also are increasing. As regards wages, at least in some industries, the wage level is that of 1939.

There is a defect in our planning. There is more production of coal and steel and also wagons. Here so many questions have been asked almost everyday. The Minister in charge of production of steel says that production is there, but wagons are not there. The Railways say that wagons are there but steel and coal are not available to be transported. As far as industries are concerned, at least in some States they are not getting steel or coal. In places where they have them, wagons are not available. The result is that they have to stop work for 15 days, one month and soon and then continue. In that way, they are suffering. When the production of steel, coal and wagons is increasing, there is this situation; it affects the working of industries and so affects the workers also. There is unemployment at least for some days. In some States, some factories in industrial estates have been closed for two or three months because

of no planning or defective planning with regard to the procurement of steel or coal or availability of wagons.

Then there is another point. The President has forgotten about a most important thing. This is about the linguistic and religious minorities. So far as the linguistic minorities are con:erned, I have no time to go into detail for want of time, into what happened in Assam and West Bengal. What has happened in Punjab? The movement for the formation of a State on a linguistic basis cannot be crushed because that is the feeling of the people. When in all other parts of India there are linguistic States, you cannot deny such a State to people living in one part of the State. That is why the trouble has come.

Then again, in several parts of a State there are minorities. In my own constituencies, there are linguistic minorities. They have got certain difficulties. This is as far as education and appointments, are concerned. There can only be two solutions to this problem: either you solve all the difficulties of the linguistic minorities, or in places where they are in a majority and in a contiguous area allow them to leave that State and join the other State. If there is discontent, if the linguistic minorities feel that their education is neglected, there will be quarrel between the linguistic minorities and the majority. That is what is happening.

So this problem of linguistic minorities in all the States has certainly to be looked into. The more the delay in looking into it and solving it, the more bitter will be the feeling of these linguistic minorities, and that will only create trouble, as there have been so many troubles.

As regards the religious minorities, the latest incident is that of Jabalpure. What has happened there? If there are anti-social elements in certain communities does it mean that the whole community must suffer for it? Why is it that the police did not interfere? Why is it that certain communal papers wrote articles and instigated certain communities? Why is it that quick action was not taken? I want to have an answer to these questions.

This question of the protection of religious minorities, in Jabalpur, in Bhopal and also in some other parts of India, must be taken up. A Committee must be appointed to go into the question. They should study the problem and report. We should see that protection is given to these religious minorities.

Whenever some such incidents takes place, due to certain anti-social elements, how is it that they turn into communal clashes? All patriotic elements and communities should be called out immediately to stop that. The anti-social elements in all communities should be isolated; then only will we be able to check this. This is a very important question, the right of the religious minorities—their protection. I hope Government will look into this.

I also come to the question of reservation for backward communities. That has also come out in the clashes in some places. As far as Kerala is concerned, I can say, there is an agitation by all the backward classes together. In the matter of appointments they had been given certain rights. By changing section 11 of the Education Act they have been affected. They are really backward; and some reservation is really necessary for some time to come. All of them have joined together and they agitate and there are likely to be communal clashes between these backward communities and other communities.

Another point I want to make is about the long-term prisoners. There are so many long-term prisoners in

[Shri A. K. Gopalan]

the different jails in India, in Andhra, in Bengal and in Tamil Nad, political prisoners whose cases have not been considered for 10 or 15 years. Their cases must be considered.

The other point that I want to bring up, because the Finance Minister is here, is about the moratorium to banks. The other day when I said that there was a serious situation the Finance Minister said that there was no serious situation. But I have seen so many Malayalam newspapers and other papers which say that the situation is really serious. Why is it serious? Because things are lying there in naval dockyards and at railway stations. Merchants and traders are not able to lift them because it is only through banks that they can do so. Due to that so many people are unemployed. So, there is a crisis so far as the merchants and small businessmen are concerned. The Finance Minister said that he does not know what to do; the State Ministers do not know what to do. Something at least must be done so that there are not these difficulties.

When the Palai Bank liquidation question came up—and that is over now—during the last session, we asked a question whether any action had been taken against the directors of the Bank. The Finance Minister said that he would see to it that action is taken against them. But no action has been taken against them. Why is it? It is as a result of that the banks are coming up, one after the other, for moratorium. The depositors and the business public suffer. So, what I say is that there are certain things which could be avoided. We must see the reason behind them.

Now, there is an agitation in Madras to name Madras as Tamil Nad. Why should there be an opposition to this when the majority of the people want to call it Tamil Nad? Why should you insist that 'Madras' should be there? This is unnecessarily creating trouble. What is the harm in calling it Tamil Nad when the majority want it? So, I say they are creating trouble where there is no trouble. There are already so many troubles facing us, the linguistic minorities, the regional minorities, the disparties as far as incomes are concerned and all that. Why should there be a new thing, about calling Madras as Tamil Nad?

Mr. Deputy-Speaker: No new thing need be said now.

Shri A. K. Gopalan: Sir, I do not want to say more. I only want to say that these things that have been pointed out may be considered by Government. And, regarding the two or three things which I mentioned first I want also an answer from Government.

श्री दुबलिश (सरघना) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमने अपने देश के शासन कार्य का भार सम्हाला है तब से लेकर अब तक जो काम हम कर पाये हैं और जिस का कि राष्ट्रपति महोदय के सम्बोधन में भी जिक्र है, उस को देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे, लेकिन एक मुस्तैदी की तौर पर, अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं और जो काम अभी तक हमारे मुल्क में हुआ है उस के लिये हमें कोई शरमिंदा होने की जरूरत नहीं है। दूसरे मुल्कों ने भी जो इस तरह के कामों से वाकिफ हैं हमारे काम को सराहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा काम उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से कि होना चाहिये। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हम चीन की तरह एक डिक्टेटोरियल मुल्क नहीं हैं और हम को अपने सोशलिस्टिक पैटर्न के ध्येय तक पहुंचने के लिये इस तरह से चलना पड़ेगा कि हम देश के अधिक से अधिक आदमियों को अपने साथ ले सकें। ज्यादा जल्दी करने में लीप फौरवर्ड की जो पालिसी हम ने चीन में देखी है उसका भी नतीजा देख रहे हैं। उसको अपनी उस पालिसी

को बदलना पड़ा । वहां क्या-क्या हो रहा है क्या क्या रुकावटें उन में आई हैं यह छन-छन कर हमारे सामने आ रहा है । उनकी एग्रीकलचर और दूसरी चीजें सब फेल हो गई । उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रौ-ग्राम तेजी से बनाया था उस को वह धीरे-धीरे पीछे कर रहे हैं ।

एक बात मुझे इस में कहनी है और वह यह है कि जो हमारी प्लानिंग का काम हो रहा है उसमें हमको कुछ विजिलेंस की देखभाल की आवश्यकता है । मेरा अपना यह अनुभव है कि बहुत सी चीजों में जितना हमारा खर्चा हो रहा है उस से कम में काम चल सकता था और कहीं-कहीं पर हमारा रुपया बर्बाद भी हो रहा है । मेरी अपनी राय इस विषय में यह है कि हमारे जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को राज्य के स्तर पर अगर जिलों के स्थान पर नान-अफिशियल्स की हर एक जगह में अलग अलग विजिलेंस कमेटीज बननी चाहिये। उन विजिलेंस कमेटीज का इम्पलीमेंटेशन से उनको पूरा करने और उन को कार्यान्वित करने से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । वह सिर्फ हर एक प्रोजेक्ट को देखें और देख करके प्लानिंग कमीशन को रिपोर्ट करें कि इस में यह कमी हो रही है और इस तरीके से यह काम किये जाने चाहिये ।

14.27 hrs.

[SHRI MULCHAND DUBE *in the Chair.*]

उदाहरणार्थ मैं आप को बताऊं कि छोटी-छोटी दस्तकारियां के लिये हम स्टेट लेविल पर जिला लेविल पर और मुल्क के लेविल पर कर्जा दे रहे हैं । मेरा अनुभव है कि बहुत से लोग धोखा देकर के कर्जा ले लेते हैं अगर जिन इंडस्ट्रीज के लिये कर्जा लिया गया वह इंडस्ट्रीज बिलकुल कायम ही नहीं हैं और उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है और वह इंडस्ट्रीज बनी भी हैं या नहीं यह भी कोई नहीं जानता ।

इसी तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट के और जो हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्टस हैं उन में नान-आफिशियेल विजिलेंस कमेटीज अलग से बननी चाहियें । ग्राम प्रोजेक्ट्स के लिये जिलों में और स्टेट्स लेविल पर जो विजिलैंस कमेटीज बनें वह बहुत बड़ी कमेटियां नहीं होनी चाहियें । उन का काम रिपोर्ट करना होना चाहिये ।

जहां तक चीन द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण किये जाने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि चीन द्वारा हमारे मुल्क के ऊपर एग्रेसन किये जाने के बारे में कोई दो रायें नहीं हैं । वे लोग भी जो पहले चीन के बड़े दोस्त थे और जो उस एग्रेशन के प्वाइंट को कुछ दाब कर दूसरे शब्दों में उसको कहते थे और अभी तक उस से इंकार भी करते थे उन्होंने भी यह बात मान ली है । इस हाउस में भी और राज्य-सभा में भी जो उनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने यह खुल कर कहा है । एग्रेशन लफ्ज तो अभी भी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन यह खुल कर कहा है कि जो इंडियन आफिशियल्स ने रिपोर्ट तैयार की हैं उसमें उन्होंने इंडिया का एक बहुत ही स्ट्रोंग केस बना लिया है और दूसरे लफ्जों में वह भी इस चीज को मानते हैं कि इंडिया का केस स्ट्रांग है । अब इंडिया का केस यह है कि हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ है तो वह भी दूसरे अल्फाज में बंधे हुए अल्फाज में यह मानते हैं कि यह एग्रेशन का केस है । ऐसी हालत में, इस हाउस में मुख्तलिफ विचारों के जितने भी माननोय सदस्य हैं, उनमें से किसी हैं भी यह सलाह नहीं दी है कि इस एग्रेशन को वैकेट कराने के लिये हमें फौजी कार्य-वाही करानी चाहिये । फिर प्रश्न उठता है कि एग्रेशन को वैकेट कराने के लिये हम क्या करें। कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल ही में जो प्रस्ताव पास किया है, या उसके प्रतिनिधियों ने अपने जो विचार हाउस में रखें हैं, अगर वे महज इलैक्शन के टक्टिक्स नहीं हैं, अगर वेईमान दारी से मानतें हैं कि चाइना ने इंडिया पर

[श्री दुबलिश]

एग्रेशन किया है, तो मैं उनको सलाह दूं कि कि वे सारी दुनिया की अपनी फ्रैटर्नल पार्टीज को खत लिखें, इस तरह का मैमोरेंडम भेजें कि वे सब पार्टीज चाइना पर प्रेशर डालें, दबाव डालें कि उसने हिन्दुस्तान की जमीन पर जो कब्जा किया है, वह उस को खाली करे ।

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) : मंजूर है ।

श्री दुबलिश : अगर उनके दबाव के बावजूद भी चाइना अपने कदम को वापस न ले और एग्रेसन को वैकेट न करे, तो हमारे साथियों को सोचना चाहिये कि ऐसी इन्टरनैशनल आरगनाइजेशन से कोई खास फायदा नहीं है । अगर वे अपनी बिरादरी के लोगों से, अपनी एक फ्रैटर्नल पार्टी से उसके एक गलत कदम को वापस नहीं करवा सकते तो उनको चाहिये कि वे अपना कम्युनिस्ट पार्टी के इन्टरनेशनलपन को खत्म कर दें । कम्यूनिस्ट लफ्ज जहां भी आयगा, वहीं उस की इन्टरनेशनल इम्पलीकेशन्ज आयेंगी । इस लिये उनको इस पार्टी को तोड़ देना चाहिये और कोई समाजवादी पार्टी बना कर, या जहां की समाज वादी संस्थाओं में शामिल हो कर देश की आजादी को बनाये रखने के लिये काम करना चाहिये । यह उन के लिये हमारी सलाह है । अगर वे सिंसीरली मानते हैं कि मुल्क पर एग्रेशन हुआ है और वे इस मूल्क को "अवर कन्ट्री" और "अवर साइड" कर कहते हैं, तो उनका यह कम से कम कर्तव्य हो जाता है ।

हम देखते हैं कि कश्मीर के बारे में रशा और चाइना ने अपनी यह राय जाहिर की थी कि वह हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन अब चाइना अपनी राय को बदल रहा है और अपनी पहली पोजीशन से हट कर आकुपाइड कश्मीर की सीमा के बारे में पाकिस्तान से संधि करने जा रहा है । ऐसी हालत में हमको लड़ाई को छोड़ कर और कोई भी कदम उठाने से चूकना नहीं चाहिये । मैं समझता हूं कि तिब्बत हमेशा से स्वतंत्र देश रहा है । अगर चाइना का उस पर कुछ दिनों के लिये कब्जा हो गया, तो वह उसी तरह, जिस तरह कि अंग्रेजों को हमारे मुल्क पर कब्जा हुआ था । अगर हिन्दुस्तान की आजादी से पहले कोई मुल्क हिन्दुस्तान से संधि करते, तो वे वहां पर अंग्रेजों की सुजिरेन्टी जरूर मानते । लेकिन सुजिरेन्टी के मायने ये नहीं हैं कि तिब्बत एक अलग नेशन नहीं है । चाइना का उस पर राजनैतिक अधिकार है, यह हमने मान लिया है । अब हमें चाहिये कि तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लें और चाइना की सुजिरेन्टी के सवाल को छोड़ दें, जैसे कि चाइना ने पहले कश्मीर पर हमारा हक माना था और अब वह पाकिस्तान से सीधी बातचीत करने जा रहा है । अगर वह क पाकिस्तान से बार्डर का सैटलमेंट करे, तो हमको भी चाहिये कि हम दलाई लामा की गवर्नमेंट को तिब्बत की सही गवर्नमेंट मान कर उस से सैटलमेंट करें ।

इस के अलावा यह भी जरूरी है कि बार्डर्ज के उन हिस्सों को, जिनको चाइना क्लेम करता है, मजबूत करें और वहा पर पूरी तरह से फौजी तैयारियां करें । इस के साथ ही मुल्क के लोगों को भी हर हालत का सामना करने के लिये तैयार करना चाहिये यह सही है कि हम ने नेगोसियेशन्ज का रास्ता अख्तियार किया है, लेकिन अगर हर तरह की नेगोसियेशन्ज और दुनिया के दबाव से काम नहीं चलता, तो हमें यह कहने में हिचकना नहीं चाहिये कि हिन्दुस्तान के अपने इस हिस्से को आजाद कराने के लिये अगर जरूरत पड़ी तो हम हथियार भी उठायेंगे । ऐसी सूरत में मुल्क के हर हिस्से में, हर किस्म के लोगों का लड़ाई की वजह से जो परेशानियां होंगीं, उन का मुकाबला करने के लिये हमें लोगों को तैयार करना चाहिये ।

जहां तक कांगो के मसले का सवाल हैं, छः सात महीने पहले युनाइटिड नेशन्ज ने इस मामले को अपने हाथों में लिया था। लोगों को इस से बड़ी बड़ी आशायें बंधी थीं और वे समझते थे कि यूनाइटेड नेशन्ज ने ऐसा कदम उठाया है, जिस से वह आगे चल कर बड़ा प्रभावशाली हो जायेगा और उसकी तरफ से दुनिया में शांति कायम करने में बड़ी मदद मिलेगी। सभी ने युनाइटेड नेशन्ज के इस कदम का स्वागत किया था। लेकिन हुआ सह कि बेलजियम ने कांगो को आजाद तो किया, लेकिन वह अपने निहित स्वार्थी, वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स, को जरा भी छोड़ना नहीं चाहता था। इस लिये दुनिया के जनमत की वजह से, वर्ल्ड ओपीनियन प्रेशर, की वजह से उस ने कांगो को सिर्फ नामिनली आज़ाद करना चाहा और साथ ही उस पर अपना पूरा कब्जा रखना चाहा। बदकिस्मती से युनाइटिड नेशन्ज की स्थिति हाउस डिवाइडिड की सी है और न तो युनाइइटिड नेशन्ज़ और न सिक्योरिटी कौंसिल एक कैबिनेट की तरह टीम स्पिरिट से काम करते हैं। इस का नतीजा यह हुआ कि बलजियम अपने इस उद्देश्य में किसी हद तक सफल हो गया कि वह कांगो पर अपना अधिकार रख। वहां का राष्ट्रीय एलिमेंट नहीं चाहता था बेलजियम से हम को सिर्फ एक थोथी आज़ादी मिले और पूरी ताकत उस के पास रहे। इसलिए वहां बलजियम-विरोधी भावनायें उठ खडी हुई। युनाइटिड नेशन्ज दो गुटो में बंटा हुआ है और इसलिए अधिकतर राष्ट्र वहां अपनी ईमानदाराना राय नहीं देते हैं। अगर उन के किसी साथी के स्वार्थ का सवाल आता है, तो व उस का साथ देते हैं, क्योंकि अगर व एसा न करेंग, तो वह भी समय पर उन का साथ नहीं देगा। हम ने वहां पर इस सम्बन्ध में कुछ तजवीजें रखी हुई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वे काम याब होंगी। हिन्दुस्तान ने शुरू से वहां पर यह तजवीज़ रखी थी कि कांगो की पार्लिमेंट को बुलाया जाये। श्री लुमुम्बा के हत्यारे जानते हैं कि यदि वह तजवीज़ कामयाब हो गई और पार्लिमेंट बुलाई गई, तो उस में हमारा बहुमत नहीं होगा। इसलिये जब तक वहां पार्लिमेंट बुलाई जाये—और अब तो अमरीका और कुछ दूसरे राष्ट्र भी वहां पार्लिमेंट का बुलाना अनिवार्य समझने लगे हैं—तब तक लुमुम्बा के साथियों को लिक्विडेट करने का उन का विचार है। लुमुम्बा को भी मारने का उन का मंशा था। और अभी जो खबर आई है कि लुमुम्बा के बहुत से साथी मार दिए गए हैं, वह भी आप के सामने है। मेरी राय में जहां तक पार्लिमेंट को बुलाने का सम्बन्ध है, इस काम में अगर देर की गई तो उस का जो आबजैक्टिव है वह ही खत्म हो जायगा। कांगो का झगड़ा मेरे विचार में एक ही तरीके से निपट सकता है। कोल्ड-वार से अगर कांगो को बचाना है तो उस का एक ही रास्ता है कि यू० एन० ओ० में जितनी भी अन-कोमिटिड कंट्रीज़ हैं, वे अपने में से तीन को चुन लें और वे तीन मेम्बर कंट्रीज़ एक ट्रस्ट के रूप में काम करने के लिए अपने नुमाइंदे वहां भेज दें। खास तौर पर जो लोग लुमुम्बा के मर्डर के लिए जिम्मेदार थे, जिनका इस में हाथ था वे चाहे जितने बड़े से बड़े लोग ही क्यों न हों, उन्हें कांगो से एग्ज़ाइल कर दिया जाय। उन को हटा कर के अगर पार्लिमेंट को बुलाने से काम चले तब तो ठीक है और अगर पार्लिमेंट को बुलाने से काम नहीं चलता है तो जो ट्रस्टी हैं तीन वे एक नई इलैक्शन करा कर पार्लिमेंट बनायें। साथ ही साथ दूसरे जो और लोग हैं जो दोनों गुटों में से किसी से भी ताल्लुक रखते हैं तथा जिन के साथियों के कांगो में कुछ स्वार्थ हैं, उन लोगों का उस मुल्क से बिल्कुल भी किसी किस्म का ताल्लुक न रहने दिया जाय। ये तीन ट्रस्टी यू० एन० की एक सब-कमेटी के रूप में काम करें और जितने भी काम वहां पर हों, वे सभी इन के थ्रू होने चाहियें। अगर ऐसा किया गया तो इस का एक अच्छा नतीजा यह निकलेगा कि जितने भी अफ्रीका के नये

] श्री दुबलिश]

मुल्क आज़ाद होने वाले हैं या जो अभी पिछले दिनों आज़ाद हुए हैं वहां के हालात बेहतर बनेंगे। अगर कोल्डवार में वे फंस गये या वहां वैसे ही हालात पैदा हुए जैसे कांगो में हुए हैं तो वे नष्ट हो जायेंगे और एसी सूरत में व आज़ाद होने के बजाय गुलाम रहें तो ही अच्छा था, यह व चाहेंग। जो तजवीज मैं ने पेश की है, वह एक पैटर्न बन जायगा हमेशा के लिए कि जो कोई नया मुल्क आज़ाद होगा अफ्रीका में, वह इस तरह से अनकोमिटिड कंट्रीज के चुने हुए तीन रिप्रिजन्टटिव्ज के सुपुर्द कर दिया जायगा और वे जिम्मेदार रहेंग यू० एन० के, तो कोई गड़बड़ी होने का अंदेशा नहीं रहेगा। अगर ऐसा किया गया तो अफ्रीका के लोग अपनी आजादी का पूरी तरह से उपभोग कर सकेंगे।

Shri Maniyangadan (Kottayam): **Mr.** Chairman, Sir, I am happy to associate myself with the Motion of Thanks to the President for his Address to both Houses of Parliament. One of the most burning and important problems that faces us today is the Chinese aggression on our borders. Almost all hon. Members who have taken part in this debate have referred to that, and I do not want to deal with that in detail. Anyhow, the intransigent attitude, as expressed by the President, of China, has caused a lot of confusion in different parts of the country. I may say that the people were looking forward to the President's Address to see what steps are being taken to vacate the aggression. There is no specific mention about that in the Address. I may say that all steps possible are being taken and, as one of my hon. friends said, there is no other possible policy that can be adopted. The President says:

> "....my Government is well alert to them and to all their implications. Defensive arrangements, including the opening up of areas by better communications and development, receive their continuous and careful attion."

So, it is gratifying that the Government is doing all that is possible for making our defence stronger and stronger and to get the aggression vacated.

Coming to the internal matters, we are now on he threshold of the third Five Year Plan, and the President in his Address has given the achievements that we were able to make during the past years, and specially in the last year, as a result of the working of the five year Plan. In several respects we can be proud of the achievements. Especially in the industrial sector, production has gone up and now, we can say safely that we have created the basis for our industrial development. In that sphere also, of course, much remains to be done, but having in view the difficulties that we have to face, my submission is that our achievements are creditable, and in a democratic set-up that we are having, there cannot be a parallel in any other country of nation, where, in so short a time, such great achievements are attained.

In the agricultural sector, of course, we have not yet reached the stage where we can say that we have got over the difficulties. Still, there are difficulties and we have to depend on the vagaries of Nature at times. Yet, it is gratifying that there also steps are being taken to improve the condition and there is every hope for a better future. It has also been mentioned in the Address thus:

> "Under the third Five Year Plan, agricultural development is being given a high priority, so as to provide a strong base for the economic development of the country. The aim is to achieve self-sufficiency in foodgrains, and to increase considerably other forms of agricultural production."

So, every step is being taken, and we have to be thankful to the Government for the steps that they take.

In this connection, I may refer to the second Five Year Plan and the third Five Year Plan and try to impress on the Government the necessity of removing the regional disparities that now exist. I may be pardoned if I refer to Kerala, the problems of which are known to everybody. Unemployment problem is the most acute in Kerala. The intensity of population is another thing which faces Kerala. There is no other part of India where the density of poulation is so high as in Kerela. Several Ministers and other eminent persons who come to Kerala say that they do understand the problem, and recently also it has been stated that the problems of Kerala are national problems which have to be tackled on a national basis. But apart from this pious platitude, I may submit that nothing much has been done to retrieve these difficulties.

If we look to the second Five Year Plan it is seen that in the industrial sector nothing has been done for the improvement of Kerala. In the third Five Year Plan—of course it has not yet been finalised and even if it is finalised it is not made known to the public—I hope the Planning Commission and the Government will give due consideration to this factor. Some heavy industries, I believe, will be started in Kerala in the third Plan period. Unless that is done, it is not possible to have an industrial base and the development of Kerala on a scientific basis. These things must be looked into, as I submitted earlier, on a national basis.

Another thing which I want to bring to the notice of this House is the necessity of giving facilities for the migration of people from Kerala to other parts of India. There are areas in India where large vacant spaces are available for cultivation and other purposes. If the people of Kerala where the density of population, as I mentioned earlier, is the highest in India and is perhaps one of the highest in any part of the world, could be given facilities to occupy those areas, I am sure this problem could be solved to some extent. I don not think anybody would object to that. Before the formation of the present Kerala, people from Tranvancore-Cochin migrated to Malabar, now a part of Kerala, and the Government of Madras—Malabar being a part of Madras at that time—and also the people of Madras were welcoming that. So if such a thing could be done I am sure the result would be very good.

Another thing which I want to refer to at this time is regarding the crisis that has recently arisen in Kerala as a result of the crash in banks.

Shri Tyagi: Anybody would welcome him if he wants to come out of Kerala, but we cannot have communist friends in our States.

Shri Maniyangadan: I am not a communist and I do not subscribe to the policies of the communist party, but I would like to say this. To say to any Keralite, "here is a communist, you cannot have a place in any other part of India", is not a correct outlook on things. Maybe in India any citizen has a right to hold communist views, but he cannot be denied a right to go and occupy any place. Because there happened to be a communist government in Kerala, to say that all Keralites are communists is ignoring facts. My friend has the audacity to say, "you are wlecome but not the communists". It is not a question of communist or Congress or PSP. It is the people of Kerala, it is a part of India which fights for its existence. We have to face realities.

I was referring to the crisis as a result of the mortorium given to the banks. The Finance Minister said the other day that there is no serious crisis in Kerala as a result of the closure of the banks. Coming from Kerala I will not be exaggerating if I say that the whole financial structure of that State is now at a standstill. Think of six or seven important banks, perhaps the only important banks in Kerala, being closed for

[Shrei Maniyangadan]

a period of three months. Practically all business has stopped. Several business concerns have thrown out their workers. The Kerala Government is also facing difficulties in realising revenue. Development works are being stopped. So there is a very serious situation there. If the Finance Minister is made to understand that there is no serious situation there, I am afraid his advisers have not made the facts clear to him. At the time of the liquidation of the Palai Central Bank it was stated by us that it is going to lead to a crisis. It was not very much heeded. The question of the liquidation of the Palai Bank is not a point to be agitated now: it has been justified by the judgment of the Kerala High Court. But I may submit that the people of Kerala believe that they were let down.

It is reported in the papers that according to the Liquidator's report to the Kerala High Court there are assets, realisable assets, and according to the valuation of the Reserve Bank about twelve annas in the rupee could be paid now. If that is possible, in the interests of the depositors I must submit that steps should be taken to see that the liquidation expenses are avoided and the Palai Bank is either amalgamated with any other bigger unit or with the new bank that is said to be coming into existence as a result of amalgamation. Some such thing must be done. Otherwise, people who are in the know of the financial aspects in the State say that if the Palai Bank is allowed to go into liquidation, then whatever steps are taken by the Government will not create in the public mind a confidence in the banking structure there.

It is true that the Reserve Bank and the Government have it in mind to make the banking structure there stronger. But the steps hitherto taken by them have created newer and newer problems. I submit that the banking system in Kerala was under special circumstances where small banks were in existence there for a long time, and they were doing a lot of good to the public, to the businessmen and to the industrialists there. If that is going to be stopped in order to bring some better system into existence, I must submit that it must be done with caution. That caution was lacking and the result is this most disastrous one.

It was only the other day, after the Finance Minister's speech, that one of the State Ministers stated that specific suggestions were given to the Central Government and to the Reserve Bank regarding the revival of the banks there. The Finance Minister stated that the State Ministers had nothing to say as to what should be done. But one of the Ministers has stated yesterday or day before yesterday—I read it in the papers—that specific suggestions were given and that they were not heeded.

My submission is that without standing on the question of prestige the question must be gone into thoroughly and the banking structure there must be allowed to stand on a firm ground. Otherwise none of our plans would succeed there. This aspect must be borne in mind and I hope Government will take serious note of this.

As I submitted, if the depositor's interests are the most important thing, then the avoidance of the liquidation expenses as regards the Palai Bank will go to the interests of the depositors. All the amount that is available there could be paid to them if it is merged into a bigger unit or allowed to amalgamate with one of the units. I cannot say what should be done; it is for the financial experts. But the expert action must be to the good of the people and the State. That is all that I have to submit.

Acharya Kripalani (Sitamarhi): Mr. Chairman, it is good that our Rashtrapathi, our comrade in the freedom fight, gives us his darshan once every year. Unfortunately in this land everything becomes ceremonial and symbolical. The President's inaugurating the

Parliament is an elaborate ceremony. To that there could be no objection. Even his address to the Parliament, which should be factual, has become ceremonial and symbolical. From year to year the pattern is the same. We are told how in the last year, in spite of the great strains and stresses of the times, we have progressed very well.

15.00 hrs.

We are also told as usual the great tasks that would be accomplished the next year. The Address is full of cliches and general propositions. There is nothing which one could grasp and nothing that would inspire the people. The picture that is given is very rosy. The Government are sitting on the heights of Himalayas and they think that everything is all right with the people of the country. But the picture that is presented to us, the optimism that is breathed by the Government is not shared by the masses of our people. They feel that everything is not all right and they express it wherever they meet, whether in their homes, clubs, kacheris, buses, trams and trains, in the market-place and in the bazaar. Everybody thinks that there is something wrong with the management of affairs.

There is no class of our population which does not complain that everything is not all right. Wherever people meet, they talk of the things that are happening. They talk of corruption, favouritism, napotism, etc. that exist in the administration. They talk of high prices and increasing unemployment. Yet, we are told that our national income is increasing by leaps and bounds every year. I am glad my colleague, Shri Asoka, Mehta, analysed the increase in the national income. He pointed out that the rich are becoming richer, but he did not say that the poor are becoming poorer, That was left to a former President of the Congress to say.

In a sense, both the Government and the people are right. The Government are looking at one section of the population, a small section, that has become rich and that indulges in conspicuous consumption. The people are looking to themselves and to their starving stomachs and bare bodies. It is certain that a section of our people have gained very much in these years when we have been spending large sums of money on our Plans, and it is quite natural that they should gain. But who are these people who are gaining? Generally they are the contractors, the manufacturers, the merchants, who have made tax-dodging into a fine art. They are also the administrators who are corrupt. Beyond that, the condition of the people is no better than what it used to be and with soaring prices any every-increasing unemployment, it would be difficult to see, how the condition of the poor can improve. It would be a wonder if this were so.

It is officially admitted that so far as the masses are concerned, the real income of those living in the villages and those who have no economic holdings of their own has decreased and their unemployment has increased. Also, their indebtedness has increased. This is given out by the figures that are supplied by Government itself. After all, the condition of the masses can improve only when they get some gainful employment. This is diminishing. Every completed Five Year Plan leaves a larger back-log of unemployment. Official figures state that 21 millions of people in India work only for one hour a day. When I was in America, I asked some of the Labour leaders what they are going to do if automation comes. They said, "We will work for one or two hours a day". I said that millennium has already been achieved by our people. Forty-five million people are working not more than 4 hours a day.

It is said that the wearer knows where the shoe pinches. But our Batas hold that not the wearer, but those who have made the shoe know where the shoe pinches. They also tell us that if the shoe they have made pinches, the fault is not with them, but the fault is with our feet.

[Acharya Kripalani]

We are always reminded of the gigantic river valley schemes, the steel plants, etc. However, here too the President's Address is clear that the distance between conception and execution is great. The President has said:

"My Government will constantly endeavour to initiate and promote efforts and schemes to shorten the time between their decisions on policies and the implementation thereof."

So far as the drawing up of the Plans and their execution is concerned, there is a great deal of difference. There is a kind of dichotomy between conception of plans, drawing up of plans and their execution. Our Plans, as they are presented to us, read very well. The accounting is perfect. The two sides of the ledger square beautifully. The fulfilment also, so far as the monetary part of it is concerned, is quite complete. But the physical targets lag far behind.

To give one instance only, it was said that we would produce at the end of the present Plan about 4 million tons of steel. But our accomplishment, after the completion of this Plan, I am told, will not be half that amount. It will be vrey much less. A few months ago, the furnaces in the three steel plants were ready, but they could not go into production. Why? Because iron ore which we sometimes export to other countries was in short supply; coal was in short supply and transport was in short supply. In some places, even water was in short supply. There are dams and canals made. They are ready, but something or other is wanting and they cannot go into action. Those who are charged with drawing up and executing our Plans fail to realise that every day's delay in these plants costs the nation more than Rs. 10 lakhs. It is much more than that. It is about Rs. 15 lakhs a day.

Our failures are, in my opinion, due to the miscalculation of our planners. They are due to our inability to create an adequate, honest and efficient administration and our deficiency in the know-how and the proper discipline and the necessary co-operation and coordination among the departments charged with the execution of our Plans. That our plans are not properly made and there is no proper coordination between the departments that are charged with the function of carrying out our plans are clear from the coal position now. The Minister for Coal, Mines and Fuel says that the coal is lying at the pit-head but there is no transport. Our Railway Minister says that he has supplied all the transport asked for and even more. The people are, in such circumstances, inclined to believe both the parties when they blame each other.

Shri Tyagi: Because it is convenient.

Acharya Kripalani: It is more inconvenient for the Government.

But supposing we are able to fulfil the physical targets, with the amounts of money that we have budgeted for will this solve the question of our colossal unemployment? In the 19th century in Europe production went on increasing apace but unemployment was also increasing and wages were falling. This was the phenomenon observed by Marx. He described the capitalist system in the 19th century and he said that under the capitalist system, as he saw it then, the poor will get poorer. So, even if we fulfil our plan there is no guarantee that our unemployment position will become easy. A Plan that makes no claim to catch up with the new labour force that arises after every five years is, in my opinion, defective in some essentials. It is not meeting the requirements of the situation and the unemployment continues. We were told sometime back that our future plans will be labour-intensive but we are not able to make them labour-

intensive. We could encourage decentralised industry in a scientific and a systematic manner and, in addition to that, we could take up schemes of road construction, irrigation, flood control, land reclamation, afforestation, soil preservation and such other things. We would have liked to hear from our President as to what his Government are going to do in these directions.

In agriculture let us see what has been the result of our efforts. Has it increased due to planned economy or has it increased merely because of the kindness and mercy of nature? I know that I would be told that production of foodgrains has increased by so many million tons per year. But the question still remains whether that is due to our planned production. I know that about a couple of years back monsoons did not favour us and our food position became critical. Year before last our cotton production went down to the level of pre-Plan era. The question, therefore, is whether we have insulated agriculture against the vagaries of nature and the uncertainty of the monsoons or are we still to depend upon these uncertain factors? Have we worked out and carried into effect any scheme of crop insurance done in other modern countries? Many agencies created for helping agriculture—community projects, intensive areas, co-operatives and village panchayats do not co-operate with each other and they are not coordinated.

The outlook, as the people and not the Government see it, is none too rosy. But supposing that all our Plans are fulfilled and we become a rich and prosperous nation, what will it avail us if we are divided among ourselves as at present? In the 18th century before the country fell a prey to the imperial rule of England, our country was the most industrialised country in the world. It was also the richest country in the world. After 100 years of foreign rule, what was our condition? We dissipated all our accumulated wealth through the centuries. It disappeared. Not only that, the very source of our income and our wealth, the industrial apparatus which gave us gainful employment was destroyed and we could not replace it. The increased population, therefore, had to live upon an impoverished agriculture. There was pressure on the land from the early days.

The conquest of India by foreigners has been made possible only through internal divisions. It was so when the Rajput rule fell. Individual Rajputs were no worse fighters than the Pathans and the Moghuls. If anything, they were more reckless and desperate fighters. It was again on account of the divisions in the ruling classes that brought about the fall of the Pathan and the Moghul empires. There was a kingdom in the north which had been created by the Sikhs. What happened to it? Sardar fought against Sardar and betrayed his country to the British and that kingdom fell. Again, there was an empire built by the Marathas which had almost replaced the Moghul empire. But the princes and the Peshwas fought against each other. They betrayed the country and their empire fell.

India has never fallen a prey to foreign rule except when it was divided. It always lay prostrate before foreigners self-defeated. We, as it were, handed over our country on a platter to the foreigners. The men were ours, the materials were ours, the fighting forces were ours but because of our disunity our country fell into the hands of foreigners. Today also history seems to be repeating itself. Would it be said of us, as it has been said of many decadent dynasties and kingdoms that they neither learnt anything nor they forget anything? We seem to be forgetting even our recent past. It was our disunity that brought about the vivisection of our country. But, at that time, we could conveniently blame the foreigner. Now we cannot blame anybody but ourselves. We are divided into castes, into classes, into communities. We are divided province by province.

[Acharya Kripalani]

We fight about river waters that each State should get. We fight about where a particular industrial scheme is to be located. We fight about a few villages which have no importance at all and the language that we use in fighting for these few villages is the language that is used in international disputes when one country takes possession of another country. We do not use same language against those who have invaded our country, namely, the Chinese. All these divisions have been increasing as years have rolled on. Even the enemies on our borders do not seem to give us wisdom. We are not united. We even forget that there are sections of our population which are friendly to the foreign aggressor and those who dispute our claims on our own territory. There are yet, I am sorry to say, in this land plenty of Jaichands and Mir Jaffars against whom we have to be careful.

To cap it all, the ruling party is a house divided against itself. Not belonging to that great party, I have no right to criticise what goes on in the Congress. But in the absence of an opposition which can replace the party in power it becomes the duty of every patriotic citizen to see that the party in power maintains its health and vigour. Moreover, I had the good fortune to serve in my humble way for many years, almost for half a century, this great organisation and I claim in its ranks many friends who have a sneaking regard and love for me.

Shri Harish Chandra Mathur: Nobody here denies you that right.

Acharya Kripalani: It is very kind of friends to say this. Therefore I think I am justified in pointing out the signs that are written by the times. They are written on the wall and anybody who runs may read them. If the organisation only remained true to its traditions before independence and remained united, it will not have to seek money from capitalist sources or strike doubtful alliances with caste communal and linguistic groups to win the elections.

If India is to advance in any direction, if its borders are to be effectively defended, if the large territory occupied is to be vacated, it can only be done by a united India. If that unity is not there, we shall not only fail at home but in the international field also depite our high-sounding principles of peace, justice, disarmament, co-existence, *panchsheel* and the talk of defending all the lost causes the world over.

In this the greatest responsibility lies with the Congress organisation and the Central Government. Wherever there is corruption, wherever there is sectional injustice owing to caste, community, language or locality, wherever minority rights are violated, the Central Government must act quickly, firmly and efficiently. It must not be misdirected from its straight path by considerations of power, prestige or the necessity of winning the next election. It will gain more in prestige if it executes justice impartially and punishes crimes committed in the name of caste, community, language or province. Its impartiality, service and patriotism will be a greater guarantee of success than any expendiency and short-sighted and shortlived advantages. Let Assam and Jabalpur open the eyes of the Central Government. It is many months and yet even now there has been no enquiry in what happened in Assam. In Jabalpur, I am glad to say, some kind of an enquiry will be held.

Shri Hem Barua (Gauhati): May I point out that one enquiry is over about the Gauhati incident. It has completed its report. And another is in progress.

Acharya Kripalani: Government had thought in some other terms than my hon. friend is willing to admit. I thought that this controdiction will

come from the Government and not from the Opposition.

Shri Hem Barua: But truth is truth and I have to point it out.

Shri Tyagi: How many time does he want it to be enquired into?

Acharya Kripalani: I do not know when the Government Benches are silent, why Opposition should......

Shri Hem Barua: They might be silent. But that does not mean that I too should be silent.

Acharya Kripalani: Sinners need not talk.

About Chinese aggression I completely endorse what my hon. colleague, Shri Asoka Mehta, has emphatically stated yesterday. I do not know whether 'I agree with him or he agrees with me in what I have been saying since 1950. Along with others I congratulate the officials who have drawn up this report. But this report, I submit, should have been prepared just after 1950 when the Chinese invaded Tibet and swallowed it. If that had been done even our Communist friends at least some of them, would have been convinced about the rightness of our cause and also neutral people would have had the opportunity to know that our cause was just. I do not know if there were any difficulties in preparing this report earlier. There could not have been any difficulties because what our officers could produce today they could have produced it ten years back also. But ten years lost is a great loss to the country.

Another point that the report has made clear and on which I had been clear even in 1950 is that Tibet was a free country. It was a free country not only internally but also internationally. It participated in international treaties along with China without any protest from that country. Whatever nominal suzerainty China claimed but could not exercise was finally repudiated by Tibet in 1911 as is powerfully brought out in this report.

It is all very well to speak in heroic terms today. But the taste of the pudding lies in the eating. We were told a few months back that Longju had been vacated by the Chinese. We would like to know whether it has been re-occupied by us or whether our own territory has been occupied again by the aggressor. If we could not occupy even a vacated portion of our own territory, nobody will take our heroic talks seriously. The President says that we will be firm and will be peaceful. May I humbly submit that those who mean business in international affairs cannot be firm and always peaceful? A time will come when their firmness must drive them to action. We see no possibility of action. We see no signs of action. The Prime Minister was very generous to offer to the U.N.O. armed combatants for fighting in the Congo. But, here, we say that we are not prepared. We say, everything must be settled peacefully except in the Congo. In the Congo, war will solve many problems. But, here it will not solve any problem. This is something which passes one's comprehension. It lacks at least logic and sense.

Shri Manabendra Shah (Tehri Garhwal): Mr. Chairman, the debate that I have been hearing today has been primarily about China. I would not like to take up its international aspect, but I would like to take up its home front aspect, and in the home front, primarily the area which is concerned with the border disputes. Specially it is important because the Prime Minister holds and rightly holds that the real defence that a country can put up does not lie in the armed forces only, but it lies in having a happy, prosperous and contented population. This, unfortunately, is lacking in the border districts of the Himalayas. It is not because the people are not patriotic; it is not because they do not want to live up to the traditions and integrity of the

[Shri Manabendra Shah]

country; it is because planning and development of these areas have been lopsided.

15.32 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I would like to refresh the memory of the House of what I have been trying to persuade the Government and this House for the last four years. I would like to go back right to 1957 when eleven Members of this House who represented or are representing the border districts of Mid-Himalayas sent a resolution to the Prime Minister and the Planning Commission. The Resolution reads as follows:

> "Having regard to the peculiar economic and geographical conditions of the Hills of the Himalayas, particularly of the hill tracts of the Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh, we the Members of Parliament representing these areas suggest to the Prime Minister and the Planning Commission that a separate Hill Planning Committee under the Planning Commission with Members of Parliament representing the above Hill areas and financial and planning experts be formed to formulate and implement the Second Five Year Plan for the Hill areas."

This resolution of ours was preceded by a resolution which M.Ps. M.L.As. and Gaon Pradhans of Tehri Grahwal had passed on the same subject. Both these resolutions had been sent to the Prime Minister who, in his trun, sent them to the Planning Commission. The Planning Commission called us to a meeting which was held in April, 1958. It was recognised then that each State should give adequate attention to the needs of the different areas which had special problems. They further mentioned that, for the Hill Dirtricts, the plan should be prepared on the basis of local conditions.

I have also been raising this issue from time to time on the floor of the House. Three years have passed, in fact, very important three years. Our meeting with the Planning Commission and the outcome of that meeting are still, I am afraid, in the form of paper recommendation. The Draft of the Third Five Year Plan is ready and the final Plan will be submitted, I understand, during this session the plan, I hope, is what we expect. Until we see what the Plan is, we are not in a position to say anything. But, what I can say is that whereas we expected the Government to actively associate us Members of Parliament in the framing of the Third Five Year Plan, they have not done so. I think all the Members of this Parliament would agree with this.

I would say that it is not only at this level that Members of Parliament have not been consulted. They have not been consulted even at the district level or at the Commissioner level. As an example, I would like to point out that a meeting had been convened on 5th January, 1961 by the Commissioner of Kumaon to discuss plans for the Third Five Year Plan. We four Members of Parliament representing four districts of the Kumaon division objected to it. We sent a written objection that we are boycotting this meeting because they had not sent us any literature for the Third Five Year Plan and we are not prepared to be mere rubber stamps. In fact, I had sent a copy of this to Shri Nanda because we received a letter from the Convener of the Standing Committee on Planning that if we have any proposals to make regarding the Third Five Year Plan, they should be sent to Shri Nanda. I sent a copy of that letter. Unfortunately, we have not heard as to what he has done about it.

Co-operation is emphasised by the President in his speech. He says:

> "Your understanding, vigilance and co-operation in respect of the many problems of our economic planning, our defence, world peace and the struggle of still dependent

peoples, will, I feel sure, be available to my Government and help to reassure our people."

He further went on to advise us,

"I am confident that wisdom and tolerance and the spirit of co-operative endeavour will be your guide."

Co-operation is there from our side. But, I am sorry, from the Government side, there does not seem to be much co-operation. Even in such fundamental things as the creation of border districts, we Member of Parliament were never consulted. According to us, the creation of border districts has been done in a very artificial manner, and probably with no proper appreciation of the situation. I have been again and again bringing to the notice of the Government the undesirable reactions of this move and the repercussions it has created and the potentialities it has to create in the future in these areas which have been removed from the border areas.

In this respect, I had written a letter to the Prime Minister and a meticulous man like him replied, "I do not quite know how we can go about changing districts or refashioning for every short while". This was a reply which greatly disappointed me. In a recent tour of my area, I found that though re-fashioning was not no easy as the Prime Minister says, they are considering the adding of some more areas to the border districts. If that is the position, I might again suggest to the Government that if re-fashioning has to be done, let it be re-fashioned in a manner that the whole of the district becomes a border district.

I also crave the indulgence of the House to refer to another aspect of this situation. The purpose of creating border districts was with a view to administer them, launch proper development schemes and to give them adequate defence. That is a multi-purpose work. The way it is being worked today is the same as it is worked all over and therefore it is bound not to succeed. It is not possible to have dual control of the State and the Centre, and it is not possible or proper to have control of various departments which run the various schemes. Therefore, I am to suggest that a warlike basis should be adopted and for that purpose, a Ministry of Border Affairs should be created. If we could create a Ministry for Kashmir Affairs, I think the China problem is a much more serious and the Government should have really no objection to creating a Border Affairs Ministry.

I would now like to touch briefly the position of Pakistan. In this, I would like to point out that Pakistan was getting arms aid from America. At that time, it was said that it is being given to help them in facing the communist onslaught from the borders. This position, according to me, has slightly changed, because the Pakistan Government is now trying to court the Communist countries, by entering into an oil agreement with Russia and probably for having some discussions about the border with China. In this situation it has become necessary for us to find out from the American Government—and I hope our Government will take the necessary steps in this connection—why the necessity of continuing their arms aid to Pakistan. If they say it is for balance of power, with whom is this balance of power going to be? If it is to defend the border, which border are they supposed to defend? The indications are that this continued arms aid to Pakistan will be more to the disadvantage of India, and therefore I hope the Government will seek a clarification from the American Government as to why now they are continuing the arms aid.

It is very clear to us that the tone of the Pakistan Government is changing considerably in their propaganda. We have heard before also their anti-Indian feelings, but the last that has come up before me is with regard to the case of Jabalpur. This is what the press report says as to what Gen. Ayub Khan said in Dacca on February 16:

"He drew a parallel between the murder of Mr. Patrice

[Shri Manabendra Shah]

Lumumba and his two associates and the recent disturbances in Jabalpur. 'Why go to the Congo, Why not look nearer home?", he asked, during a chat with reporters at the airport here on arrival from Karachi. 'Look at the tragedy in Madhya Pradesh' he added, 'Innocent people are being killed and wounded. One does not know how these things happen. These things occur now and again in that country.' He said: 'What can a poor minority of 8 per cent do in that country? They are politically completely neutralised, economically they are almost finished. I do not know what more they are required to do.'"

The Jabalpur incident has been agitating the mind of the House from one aspect, it has been exploited by Pakistan; it may also be exploited internationally, and probably it may be said that we have some ulterior motives in creating a Jabalpur incident. Whatever motives may be ascribed to us, I would not blame Gen. Ayub for having made such a statement, when a person who is supposed to have allergy for irresponsible speeches, a person whose advice is supposed to be very sound, whose advice is accepted by the Central Government, gives a statement to the press which, by itself, is very dangerous. Our Dr. Katju was reported by the press as under:

"Today the killing and destruction of property in Jabalpur had made him very sad. The city, Dr. Katju said, looked like a shamsan (cremation ground), and this made him extremely unhappy. 'I want to bring it back to humming life', he said."

This he said on the 9th, and the Pakistan President took advantage of it and gave his statement on the 16th. Therefore, this sort of irresponsible speeches should also be taken cognizance of, whether they be from Ministers or leaders.

Shri Oza (Zalawad): I have been hearing the speeches of the great Acharya Kripalani ever since I came to this House. I have been hearing him with great attention and admiration—attention because he is one of our great leaders, a great patriot, admiration because he has always spoken in this House for the downtrodden and he has always exhibited a deep sense of patriotism. But I must also frankly confess that at the end of his speech I have also always become sad. He has to my mind developed a very cynical approach to problems. He accused the Government of painting a very rosy picture in the President's Address. It is true that it is in a way rosy. I may point out that at some places the President has also asked the people to get prepared to bear some extra strains. But is he free from this allegation? He has painted a very dark picture.

An Hon. Member: You have painted.

Shri Oza: Wait till I have painted and you have a full glimpse of the picture.

It seems nowadays he carries a very bad brush, a tarred brush. He had no good word for the hundreds of panchayats in this country which are functioning today. He had no good word for the co-operative effort that we are making in this country for the very poor and backward classes. He had no good word for our community projects. Maybe we are erring at some places, but it has created a leadership in the rural areas. One has got to move round to find out what these village panchayat and co-operative movements and the community development programmes have done to the country. We do not claim that everything is perfect, there are some faults here and there. We have got to correct them, and we are vigilant. The President has said that we have got to be vigilant, but it does not mean that it has not done any good or brought

any benefit to this country. I think we should drop this cynical approach to our national problems. This is a national platform and he is heard with great admiration inside the House and outside, and when the country has to march forward, put up with many strains with a smile, I do not think he is serving the country, for which he has suffered so much and laid down so many things in his life, for which we all admire him so much and hold him in high estimation, by creating an atmosphere of despondency, an atmosphere of dejection.

Almost all Members have started their speeches with a reference to Chinese aggression and incursions on our borders, and rightly so. The President has also started his Address with a reference to the aggression of China. Everybody feels aggrieved, agitated about this incursion. I am no exception to it. I also feel deeply hurt that somebody should take liberties with our frontiers, our independence in a way. We feel very sore over it, but what is to be done. When a man trespasses on our land, we do not immediately take up a lathi. We point out: Look here, there is some mistake on your part, you have trespassed on my land, this is my land. We start negotiations.

Shri Braj Raj Singh: Negotiations?

Shri Oza: That is the civilised way. We do not take up a lathi immediately. That shows immaturity. (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: In this House at least, lathis should not be taken up immediately.

Shri Oza: Therefore, like mature people, we are moving with the banner of peace in international matters. We have adopted a particular line, and we advise countries to adopt peaceful methods of negotiation to settle their disputes and not to take to arms immediately there is a question.

An Hon. Member: A country whose areas have been occupied?

Shri Oza: I am with you that everything should be done, but there are stages. We want to make it known to the world that we are not in the wrong. Now that this voluminous report is out, we speak with a firmer tone. Look at the language that has been used. There is a departure from the previous language, as I shall point out for the benefit of hon. friends here. What else do you expect Government to say, in what other language can we speak? We have talked in very firm language. The President has said:

> "Defensive arrangements, including the opening up of areas by better communications and development receive their continuous and careful attention."

Not that we are complacent. Further on, the Address proceeds to state:

> "My Government will, however, seek to adhere firmly to the principles which this Nation regards as basic in our relations with nations. They cannot accept the results of unilateral action or decisions taken by China."

Then comes the operative part. I am sure the Chinese people will also understand this language. This is almost a very stern warning that has been administered. The operative part reads thus:

> "In spite of present unwillingness, or even intransigence, my Government hope that, sooner rather than later, China will persuade herself to come to a satisfactory agreement with our country in regard to our common frontiers."

When we ask a man to quit our room, we say 'You persuade yourself to quit'. Before we throw him out, this is the last language that is used in a civilised society. I think no harsher words can be used by any nation.

Acharya Kripalani: Why do you not do that in the Congo?

Mr. Deputy-Speaker: Let not that language be used here.

Shri Oza: There are stages We cannot jump suddenly. We have got to pass through certain processes, and I am sure that by this process, we have gained world opinion; it is with us today. Tomorrow, if we have to take any action, I am sure the world will stand with us. We have proved our case conclusively. We have not closed our doors for negotiations. That shows our strength. We have got to exhibit to the world that we are strong, but, at the same time, we want to see that all peaceful methods are exhausted. I do not think it is a sign of any weakness. We do not shout. We speak with a mild language but with a very firm language. I am sure the international world and the Chinese people particularly will follow the warning that is contained in this sentence that sooner rather than later, they will realise that they have to quit.

I would only suggest that our hon. friends should not become impatient. After all, in whose hands is this matter? It is in the hands of a man whose sense of pride is no less than that of anybody else. Shri Jawaharlal Nehru is in charge of External Affairs. His sense of pride and nationalism and patriotism is no less than those of any of us, and he is in charge of these affairs. Let us strengthen his hands. What has he been saying? He has been saying, you can strengthen my hands not only on the borders by sending some people on the border or some jeeps or some ammunitions, but also in every field and factory by doing work and creating the atmosphere that we are prepared. That is the way of preparing the nation for any emergency. When a man with such a high sense of pride is saying this to us, I am sure he will be heard much more by everyone. Though I am very much irritated and agitated over this Chinese aggression, and as I said, it hurts our national pride that somebody should take liberty with our frontiers, at the same time, I do not worry because the problem is in very safe hands. That is what I wish about this. I am sure the Chinese people will also take note of the cautious warning that has been administered in this Address.

Coming nearer home, Shri Asoka Mehta said that this Address is insipid, colourless, odourless and tasteless. I am afraid we are accustomed to spicy words and superlatives. We must also acquire maturity. What is there colourless in this Address? You may read the address of Queen Elizabeth to the British Parliament or, for that matter, the speech of any President who delivers such message. One could understand such a language being used by a President when he urges the whole nation to be prepared for any emergency or to face any task. But this is not a Republican message. This is an Address to both Houses of Parliament in regard to the task that they have to face during the year and what Government have been doing during the previous year. Therefore, why should one expect spicy words and superlatives in this Address? It is a matter-of-fact and realistic Address. If you read it carefully, you will see that there is maturity, and a sense of realism in every paragraph that is contained therein. We must come out of the habit for going in for all these spicy words and superlatives.

Coming to the Third Five Year Plan, the Plan-frame has been discussed fully and at length in this House, and we shall be discussing the final Plan also when it is ready. But, I would ask 'What is there new in the Third Five Year Plan?' What is going to be a new feature in the Third Five Year Plan? When we laid the foundation of the First Five Year Plan, we had adopted a perspective planning, in this country. Our First Five Year Plan was just part of perspective planning, running into the

Second, Third, Fourth and Fifth Five Year Plans and so on. So, I do not find anything new in the Third Five Year Plan. Only, there is a shift in the emphasis in details here and there.

If we have to make this Plan successful, then we have to create the proper atmosphere in this country. We have created Plan-mindedness already. As Acharya Kripalani has said, and rightly, everybody is asking and grabbing for that scheme in that State or this scheme in this State and so on, saying 'Give us a fertiliser plan', give us a steel plant, and so on.". But that Plan-mindedness alone is not sufficient. At the same time, among the public at large we have got to create an atmosphere, because, especially in a democracy, unless we enthuse the people and sense of willing participation in the great task that is before us is aroused, I shudderd to think how we are going to implement a Plan of this gigantic size. We have to raise about Rs. 1600 crores of new taxation by way of resources. This is not a small thing. Unless we create the proper atmosphere, I am afraid we shall not be able to create that sense of participation and enthusiasm in this country. How are we going to do it? We can do that only if we take the people into confidence and make the people feel that we are also participating in the same hardships which they have to undergo, and that their sacrifices do not go in vain and that every naya paisa that is spent is well taken care of by Government. Gandhiji took ultra-care for every pie of public funds that he spent; he exercised great thrift and great vigilance. In the same way, this Government should also create an impression in the country that every naya paisa that is being collected from the people and which they are paying by tightening their belts, because there are excise duties on oil, on sugar, on cloth and everything else, and the poor people are bearing all these indirect taxes by tightening their belts, is well taken care of and that it is not wasted and that there is neither any inefficiency nor any corruption. Unless we do that I am afraid we shall not be able to enthuse the people to pay higher and higher taxes for resources for the Third Plan.

At the same time, as has been rightly pointed out by my hon. friend Shri Harish Chandra Mathur and also Shri Asoka Mehta who spoke yesterday, we have got to gear up our administrative machinery. Of course, there are very good officers, and they are doing very good and hard work. But at the same time, we should not forget that by and large, the administrative services require to be cleansed and geared up, because there is the feeling today—I am saying this because I am closely associated in so many activities with the administrative systems—among the subordinate officers that even if they do good work, nobody is going to appreciate and if they are going to do bad work, nobody is going to put his feet down on it. This kind of feeling is very bad in any administrative system. It not only leads to sullenness but also to insubordination and sabotage ultimately. Therefore, my hon. friend Shri Asoka Mehta has rightly placed ample stress on gearing up the administrative system.

The Jabalpur affair has also come in for some reference. I completely agree with my hon. friends who have shown their anxiety. Some hon. friends have said that the Muslim League is emerging again. But, who is to be blamed for this?

Shri Braj Raj Singh: You.

An. Hon Member. The Congress *Raj*.

Shri Oza: I am very sorry for the emergence of the Muslim League but I am very sorry also for the situation which has given rise to this emergence. When all other communities are organising themselves, like *Kayasthas* and *Bhoomidars*, Brahimns and non-Brahmins, the Mahrattas and non-Mahrattas and so on, how do you expect the Muslims not to organise

[Shri Oza]

themselves?

An Hon. Member: Question.

Shri Oza: You may go to any State, and you will find that communalism, casteism and sectarianism are rampant. In such an atmosphere, unless we are vigilant, all of us, including the major communities, I do not think we can discourage movements like the Muslim League. When people organise themselves on sectarian lines, and responsible persons, particularly those in power or out of power are organised on those lines, then that feeling is there, and people think that this is the only way to organise themselves to protect their rights or to get some benefits. So, all of us have got to tackle this problem from a national front. We should not look at this problem from a party point of view, but all the parties should put their heads together. If we not merely pay lip sympathy to our Constitution but we owe allegiance to it and that ours is a secular State, then, it is the duty of every citizen of India to see that people rise above these narrow lines and behave just like nationals of this country. Only by setting an example, and not by precepts not by showing anger, can we weed out the Muslim League in the future.

14 hrs.

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है मैं उस का स्वागत करता हूं साथ ही श्री भक्त दर्शन ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस का मैं समर्थन करता हूं ।

मैं कल से यहां पर होने वाले भाषणों को सुन रहा हूं और पहले भी जो हमारे विरोधी दल के भाई समय समय पर हमारी सरकार की वैदेशिक नीति पर समालोचना किया करते हैं उन को सुनता रहा हूं। मैं इस अवसर पर अपने उन विरोधी दलों के भाइयों को कांग्रेस के पुराने इतिहास का स्मरण कराना चाहता हूं । सन् १९२०, ३०, ३२ और सन् १९४२ और उस के बीच में जो इंडिविजुएल सत्याग्रह हुआ, उन के जमाने में जब जब कांग्रेस आन्दोलन छेड़ने में देर करती थी तो हमारे विरोधी लोग कहा करते थे कि कांग्रेस चुप बैठी हुई है और आंदोलन नही छेड़ती है । सन् १९४२ में तो हमारे इन विरोधियों ने खास तौर से कहा कि गांधी जी बुड्ढे हो गय हैं और वह लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं । मैं अपने उन विरोधी भाइयों से कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस बराबर अंग्रेज़ों से भारत की स्वाधीनता के लिए जूझती रही और हमारी कांग्रेस सरकार जब भी मुनासिब मौका आयगा तो वह चीन से अपनी धरती खाली कराने के लिए जरूर लड़ेगी । चीन ने जो हमारी जमीन को दबा रक्खा है उस से उन को खदेड़ भगायगी लेकिन लड़ाई करने का उपयुक्त अवसर आने पर ही वह चीन से लड़ाई करेगी । सन् १९४२ में गांधी जी ने कहा था "डू ऑर डाई", तो हमारे वे समालोचक भाई सब लोग इधर उधर भाग गये थे जबकि हम लोग जेलखाने गये । बहुत जगह गोलियां चलीं .

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : जी हम नहीं भागे थे बल्कि हम ने उस स्वाधीनता संग्राम में आप से ज्यादा हिस्सा लिया था । हम लोग भी जेलखानों में गये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है आप भी थे लेकिन अभी आप मत कहिए आप को अभी बुलाया जायगा ।

श्री विभूति मिश्र: सन् ४२ के स्वाधीनता संग्राम में हम ने अनेकों यातनाएं सहीं, हमारी सम्पत्ति लूटी गई और हम ने मार भी खाई । हमारे विरोधी दल के भाई यह समझते हैं कि देशभक्ति का ठेका उन्हीं को केवल मिला हुआ है . . . .

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : जी नहीं वह तो आप को मिला हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र : बहुत से हमारे उन भाइयों को सन् १६२० से ले कर सन् १६६१ तक का अर्थात् ४१ वर्ष का कांग्रेस का इतिहास पता नहीं होगा । वे आज हमारे प्रधान मंत्री जी के लिए कहते हैं कि वे लड़ना नहीं चाहते । मेरा कहना है कि प्रधान मंत्री जी के मुकाबले हिन्दुस्तान में लड़ने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है । यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्हों ने सन् ४२ के आंदोलन के बाद जब वह जेल से बाहर निकले तो उन्होंने खुले रूप में उस सन् ४२ के जन आंदोलन का समर्थन किया था ।

अभी हमारे श्री कृपलानी और श्री अशोक मेहता ने जो हमारे आफिशिएल्स की रिपोर्ट निकली है उस का समर्थन किया है और दूसरी तरफ जब यह कहते हैं कि हमारी सरकार कुछ करती नहीं है तब बड़ा अजीब सा लगता है । हमारी सरकार ने एक रिपोर्ट एक सबूत दुनिया के सामने रख दिया कि चीन ने भारत भूमि पर नाजायज तौर से कब्जा कर रक्खा है । सूर्य की रोशनी की तरह सारे संसार पर उन्हों ने अपनी रिपोर्ट में यह सिद्ध कर दिया है कि चीन आक्रान्ता है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार चीनी खतरे से पूरी तरह सावधान है और जिस दिन हमारी सरकार चीन से लड़ाई करना उपयुक्त समझेगी और लड़ाई का ऐलान कर देगी उस दिन हमारे यह विरोधी भाई जो आज सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं भाग जायेंगे जबकि हम कंधे से कंधा मिला कर अपनी सरकार का साथ देंगे ।

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया : हमारी ईमानदारी के ऊपर हमला किया जा रहा है . . . .

श्री विभूति मिश्र : जी ईमानदारी पर हमला नहीं है बल्कि पुराना अनुभव हमें बतलाता है कि वे इधर उधर हो जायेंगे ।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उन की नीति हमारी समझ में नहीं आती है । कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक ओर तो चीनी से दोस्ती रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के प्रति भी वफादार बने रहने का दावा करते हैं । मैं अपने उन मित्रों को कहना चाहूंगा कि भाई अब ऐसा अवसर आ गया है जबकि आप को एक तरफ रहना पड़ेगा यह दुतरफा मामला अब नहीं चलने वाला है । या तो हिन्दुस्तान की सुरक्षा के हेतु पूरी तरह से भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रीय सरकार के साथ रहिए और हिन्दुस्तान में जिस तरीके से गरीबी का मसला हल करना हो उस में यहां की सरकार का साथ दीजिये और उन से पूर्ण सहयोग कीजिये और नहीं तो साफ साफ कहिए कि हम आप के साथ नहीं हैं । अब इस में भी आप देखेंगे कि हमारे प्रधान मंत्री जी नौन वाएलेंस की नीति पर मजबूती से जमे हुए हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी आप के साथ कितने नौन वाएलैंट हैं । अगर चीन और रूस में इस तरह के लोग होते तो वहां पर उन को गोली से उड़ा दिया गया होगा । इस में भी आप को गांधी जी को अहिंसा का प्रभाव देखने को मिलेगा । अब इसी सदन में हम लोग ३७५ के लगभग हैं तब भी हम और हमारे प्रधान मंत्री जी कितने नौन वाएलैंट हैं और पूर्ण रूप से सत्य और अहिंसा का बर्त्ताव आप के साथ करते हैं .

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे साथ तो माननीय सदस्य बर्त्ताव का जिक्र नहीं कर रहे हैं ?

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, जी आप का जिक्र में कतई नहीं कर रहा हूं । आप के साथ तो एकदम हमारा आदर-निष्ठा और सत्य अहिंसा का बर्त्ताव है । मैं तो यह बर्त्ताव की बात अपने विरोधी सदस्यों के लिए कह रहा था । उन को तो हिन्दुस्तान का और कांग्रेस के इतिहास का पता नहीं है कि

[श्री विभूति मिश्र]

कांग्रेस ने भारत की स्वाधीनता के लिये कैसी कैसी लड़ाइयां लड़ीं और यातनायें झेलीं। अलबत्ता कुछ भाई हैं जिन को कि इस बारे में पता है जैसेकि कृपलानी जी। अब वे हमारे अपने घर के आदमी रहे हैं जोकि अभाग्यवश आजकल हम से बिछुड़ गये हैं उन को कांग्रेस का इतिहास भली भांति मालूम है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जिन को कि इस के बारे में पता भी नहीं है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार से एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो शुगरकेन इण्डस्ट्री की है। अगर और किसी इण्स्डट्री के कारखाने में हड़ताल हो जाये तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर शुगरकेन की फैक्टरी में हड़ताल हो जाय तो उसमें शुगरकेन ग्रोअर्स का बड़ा नुकसान होता है। यह शुगरकेन इतना कच्चा सौदा है कि अगर गन्ना मिल में हड़ताल हो जाये तो किसान तबाह हो जाता है। अभी हमारे क्षेत्र में हरिनगर शुगर मिल में एक हड़ताल हुई थी, वैसे मिल तो चल रही है लेकिन मजदूर और मालिकों का मामला अभी तक तय नहीं हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार को विशेष कर इस शुगरकेन व्यवसाय के बारे में कौटेन की तरह से खास तौर से कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि गन्ना मिलों में हड़ताल न हो। लोहे के कारखानों की बात जुदा है लेकिन यह शुगर केन का बड़ा कच्चे सौदे वाला व्यापार है जो और एक रोज की देर हो जाय तो शुगर केन का मामला ऐसा है कि लोग और उसकी जीव जन्तु खा जायेंगे और उसमें किसान को बड़ा नुकसान होता है और हमारे प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचता है। अभी प्रश्नोत्तर काल में सुना था कि ५ लाख टन हम बाहर भेजेंगे। हम कहते हैं कि हिन्दुस्तान का किसान जिन चीजों को पैदा करता है उनकी कीमत जो कारखानों से चीजें पैदा होती हैं उनके साथ जोड़ी जाय। इसमें कंज्यूमर्स की भी रक्षा को जाये। मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर्स का भी ख्याल किया जाये। जो फैक्टरी गुड्स हैं उनका भी ख्याल किया जाय और जो चीजें किसान पैदा करता र उनका भी ख्याल किया जाय। जब तक आप इसका खयाल नहीं करेंगे किसानों को बड़ा घाटा रहने वाला है। हमारी सरकार ने ८२ करोड़ का गल्ला बाहर से मंगाया। उसका नतीजा हुआ कि हिन्दुस्तान में जो गल्ला था उसके दाम गिर गये और किसानों को घाटा हुआ।

मैं समझता हूं कि इस सदन में करीब ८५ फीसदी सदस्य किसानों के वोट पर चुन कर आये होंगे बाकी १५ फीसदी ऐसे होंगे जो कि शहर वालों के वोटों से चुन कर आये होंगे। लेकिन आज उन किसानों की हालत देखिए कि कैसी शोचनीय है। यह फैक्टरी वाले बहुत पैसा खींच ले जाते हैं मार ले जाते हैं और किसानों को बहुत कम मुनाफा मिलता है। आज तो जूट के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। इसके लिए मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं लेकिन एक मन जूट में जितने बोरे बनते हैं उतने बोरों की कीमत लगाई जाये तो उसके मुकाबले में किसान को एक मन जूट के दाम बहुत कम मिलते हैं और हम देखते हैं कि फैक्टरी ओनर्स को जूट की प्राइस बढ़ने से किसानों की अपेक्षा बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक इंटैगरेट्ड प्राइस पालिसी होनी चाहिये, प्राइस बोर्ड नहीं क्योंकि प्राइस बोर्ड में तो एक चीज के दाम रक्खेंगे। कंज्यूमर्स का ख्याल करते हुए, फैक्टरी गुड्स जो पैदा होते हैं उनका ख्याल करते हुए, जो चीजें पैदा होती हैं उनका खयाल करते हुए और किसान का ख्याल करते हुए कि उसका कैसा स्टैण्डर्ड आफ लिविंग होना चाहिये उसका ख्याल रखते हुए एक इंटैगरेट्रेड प्राइस

बोर्ड होना चाहिये जो सब को जोड़ कर ले कर ले चलें और ऐसा करना बहुत जरूरी है । मैंने भावनगर कांग्रेस में भी इसके बारे में कहा था ।

हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि कोग्रापरेटिव्स बनाइये । कोग्रापरेटिव्स बनाने के लिए मैं सचेष्ट हूं लेकिन हालत यह है कि उन्होंने कहा कि एक हजार की आबादी के ऊपर कोग्रापरेटिव्स बननी चाहियें लेकिन आज जितनी कोग्रापरेटिव्स हैं वह ४००० की पापुलेशन पर हैं और एक हजार की पापुलेशन पर कोग्रापरेटिव्स नहीं बनी हैं । ४००० की आबादी पर चलाना मुश्किल होता हैं । १००० पर बनने से ठीक हो जायगा । इसलिये मैं कहूंगा कि चूंकि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय वाद-विवाद का जवाब देंगे, यह बेहतर हो कि अगर वह स्टेट गवर्नमेंट को इसकी सूचना दें कि १००० की आबादी पर कोग्रापरेटिव सोसाइटीज बनाई जायें ।

अब उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का मैं और अपनी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं । हमारे हरिजन भाइयों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनमें हमें कोई ऐतराज नहीं है । बैकवर्ड क्लासेज को दी जाती हैं उनमें हमें कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन मेरा कहना है कि उनके अलावा कुछ अन्य जातियां भी हैं जिनमें कि बहुत गरीब विद्यार्थी रहते हैं और सरकार को उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए । आप कहते हैं कि हम उनको मैरिट पर देंगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक ओर तो एक सेठ का लड़का है जिसको कि पढ़ाने के वास्ते मास्टर लगा हुआ है और दूसरी तरफ उस गरीब का लड़का है जिसको कि खाने और पहनने को कपड़ा नहीं है और जो स्कूल में जाता है वह उस सेठ के लड़के के मुकाबले में मैरिट में कैसे आगे आ पायेगा ? उसकी मैरिट कैसे तेज होगी ? पहले तो हमारे यहां पर गुरुकुल का रिवाज था जहां पर कि राजा और रंक के लड़के एक साथ गुरू के चरणों में बैठ कर विद्या सीखते थे और वहां पर अलबत्ता दोनों को समान रूप से विद्या मिलती थीऔर उस हालत में मैरिट की बात सोचनी ठीक भी थी लेकिन आजकल की शिक्षा प्रणाली में तो वह सम्भव नहीं है और होगा यह कि उन गरीब लोगों के लड़के जिनको कि छात्रवृत्ति नहीं देते हैं वे पीछे रह जायेंगे और एकदम बैकवर्ड क्लास के हो जायेंगे । इसलिये मेरा खयाल है कि जैसे आप हरिजन आदि लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं वैसे ही जो और जातियां हैं जो कि वास्तव में बहुत गरीब हैं उनके लड़कों को भी छात्रवृत्ति दें और उनके साथ भी आप न्याय करें ।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में विषमता बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है । एक शुगर फैक्टरी वाले ने मुझ से कहा कि आखिर साल में उस को क्या बचता है ? सिर्फ १५ लाख रु० बचता है । कुछ नहीं बचता है । अब आप सोचिये कि जो काम करे, इतनी तरद्दुद उठाता है, उसका तो पेट नहीं भरता है, हलांकि वह शुगर केन पैदा करता है । मिल मालिक की फैक्ट्री में कोई खूबी नहीं है, अगर कोई खूबी है तो यही कि उसने रिजर्व बैंक से पैसा लिया, कुछ और लोगों से पैसा लिया और बैठ कर कारखाना चलाने लगा । इसके अलावा और कोई खूबी नहीं । कारखाने की टक्नीकलोजी को जिसने पैदा किया, खूबी उसकी है न कि मिल मालिक की । मिल मालिक का काम केवल मैनेजमेंट करना है और फैक्ट्री चला देना है, फिर भी उनका इतना कायदा हो और जो आदमी कारखाने को सामान देता है, उसका कोई फायदा नहीं । जो हमारे भाई एकानामिक्स पढ़े हुए हैं वे कहते हैं कि टैक्स लगाओ । लेकिन टैक्सेशन की पालिसी फेल कर गई । इतने टैक्सेशन के बावजूद आप के पास कितना पैसा जमा हुआ है ? कहा है कि मिल मालिकों के पास सेविंग होना चाहिये ताकि आगे

[श्री विभूति मिश्र]

डेवलपमेंट हो । मैं यह भी मान लेता हूं कि यह व्यवस्था रहे, लेकिन जो सेठ हैं, जो धनी हैं, जो सरकारी नौकर हैं, उनका और जो गरीब आदमी हैं, उनका जीवन का मापदण्ड एक होना चाहिये । अगर वे लोग बीमार पड़ जायें, तो आप उनको अच्छी दवा दीजिये, दूध दीजिये, मक्खन दीजिये, लेकिन बीमार न हों तो सब के लिये एक सी चीज होनी चाहिये । जिस तरह से गांधी जी सर्वोदय और अन्तोदय की बात कहते थे उसी तरह से आप को करना चाहिये था, लेकिन आप सर्वोदय और अन्तोदय के आधार को नहीं मानते हों फल यह हो रहा है कि डिस्पैरिटी बढ़ती जाती है । इस विषमता के बढ़ने का जो नतीजा होगा वह मुल्क के लिये अच्छा नहीं होगा । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि विषमता आगे न बढ़ाये । जो आप की टैक्सेशन वगैरह की नीति है उस सब के बावजूद अगर एक जगह माल जमा हो जाता है तो उससे एक तरफ अमीरी बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जाती है । आज अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटाने की जरूरत है ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा राजतन्त्र चल रहा है वह खाली अंग्रेजी वालों का राजतन्त्र है । चाहे आप स्टेट्स को ले लें चाहे सेन्टर को ले लें, वहां से यहां तक अंग्रेजी जानने वाले ही या तो मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या और पदों पर हैं । मैं जानना चाहता हूं कि स्वराज्य की लड़ाई में उन्होंने कितना त्याग किया ? और अगर यही समाजवाद है तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जो हमारे बहुत से दूसरे लोग हैं, भले ही वे अंग्रेजी न जानते हों लेकिन वे बहुत से अंग्रेजी भाषा जानने वालों से ज्यादा होशियार हैं और राजतन्त्र को अच्छा चलाने वाले हैं । मैं नहीं कहता कि यहां पर हिन्दी ही हो, और भाषाओं के जानने वाले भी बहुत योग्य लोग हैं । हमारे श्री कामराज नाडार मद्रास के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और उसकी प्रशंसा भी हुई है न कि अंग्रेजी जानने वालों की । मैं नहीं जानता कि हमारे यहां अंग्रेजी का इम्पीरियललिज्म कब तक चलता रहेगा । अंग्रेजी जानने वालों का यह इम्पीरियलिज्म जो है उसे खत्म होना चाहिये हमारे मौलाना साहब तो स्वर्गवासी हो गये, उन के बाद अब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी भाषा को जानते हुए ही सरकार का काम चलाये । आज यू० एन० ओ० में भी होता है कि विभिन्न भाषाओं का इस्तैमाल होता है । वहां पर आये प्रतिनिधि अपनी भाषाओं में भाषण देते हैं और तुरन्त उनका ट्रांस्लेशन हो जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे आज लोकसभा का मेम्बर रहते दस वर्ष हो गये, लेकिन इन दस वर्षों में केवल इसी बार मुझे प्रेजिडट के ऐड्रेस पर बोलने का मौका मिला है, जबकि हमारे संविधान में लिखा है "ईक्वेलिटी, फ्रैटनिटी और जस्टिस ।" यह सारी चीजें लिखी हुई हैं । लेकिन हमारे साथ क्या हुआ । संविधान में लिखा होने पर भी जस्टिस होगी, ईक्वलैटी होगी दस वर्षों में मुझे आज पहली बार प्रेजिडेंट ऐड्रेस पर बोलने का मौका मिला है । जो हमारे विरोधी दल के भाई हैं उन को आप २० मिनट देते हैं लेकिन हम को बहुत कम देते हैं । मेम्बर तो सब बराबर हैं । उनका वोट डेढ़ नहीं गिना जायेगा, सब का एक ही वोट गिना जायेगा, लेकिन उन को आप 20 मिनट देते हैं और हमें १५ मिनट देते हैं । सदस्यों में कोई फर्क नहीं है, सब को वोट एक ही है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है वह बराबर फारेन एक्सचेंज के चक्कर में है । मैं चाहता हूं कि

हमारे देश में जो सहूलियतें हैं, जो साधन हैं, उनको खर्च करने में पूरी आस्टेरिटी का खयाल रक्खा जाय । हमारे देश में जितना सामान है उसको ठीक से इस्तैमाल करने के बाद जो कमी हो उसी को पूरा करने के लिये हम बाहर से कर्ज लें । हम देख रहे हैं कि हमारी कर्ज खाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है । जब एक आदमी कर्ज खाने लगता है तो उसकी आदत बिगड़ती जाती है । मैं इसके खिलाफ हूं कि बाहर से कर्ज लिया जाय वैसे न लिया जाय हम केवल अपनी आवश्यकता को देख कर ही कर्ज लें, सिर्फ कर्ज खाने के लिये बाहर से पैसा न लें । जितने हमारे साधन हों हम उन से ही काम लेने का प्रयत्न करें ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से लगातार शासक दल के लोगों के मुख से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रशंसा के गीत सुनता चला आ रहा हूं । मैंने भी प्रथम दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना, लेकिन निराशा के अलावा कोई दूसरी चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ी । पूरे का पूरा अभिभाषण बिल्कुल निर्जीव, निष्प्राण और निराशाजनक था । इस तरह के अभिभाषण को कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की संज्ञा नहीं दी जा सकती है ? जिस समय मैं राष्ट्रपति का अभिभाषण सुन रहा था तो मैं यह फर्क नहीं कर पा रहा था कि मेरे कानों में जो शब्द आ रहे थे वे किसी व्यक्ति या मानव के बोल हैं या कहीं मशीन से कोई ध्वनि निकल रही है । जिस भाषण के अन्दर देश की जनता की आकांक्षायें और उसकी आशायें व्यक्त न हों, उसको कैसे अभिभाषण कहा जा सकता है । राष्ट्रपति का अभिभाषण तो वह हो सकता है जिस में किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की आशा हो ।

बहुत सी बातें सीमा के सिलसिले में भी ही गई है, लेकिन एक बात भी स्पष्ट तौर से ही कहती गयी । अगर उस पूरे के पूरे भाषण को बांटा जांय तो उस को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है : पहला विदेश नीति, दूसरा गृह-नीति और तीसरा हिन्दुस्तान में आने वाले विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी, उन पर होने वाला खर्च और उन का स्वागत और सत्कार । अगर मैं सब से पहले विदेश नीति को लूं और अभी तक जो कुछ भी सरकार ने किया है उस के कामों को लूं तो कहा जा सकता है कि पूरे का पूरा अभिभाषण किसी भी असफल सरकार की असफलताओं की दुःखभरी कहानी है और अपनी सीमाओं पर होने वाली हलचलों के बारे में कहा गया है कि वह चीन की दुराग्रह नीति है । मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान की सीमाओं पर चीनी अजगर फुफकार रहा है, उस चीनी अजगर ने लम्बी सांसें खींच कर हमारे मुल्क ी १३,००० वर्ग मील धरती को निगल लिया है या उस पर कब्जा कर लिया है । सरकार कहती है कि मौका पड़ेगा तो तलवार उठायेगा । हमारे मिश्र जी कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेज हुकूमत से जबर्दस्त लड़ाई लड़ी है । लेकिन मैं उस को बतलाना चाहता हूं कि उस लड़ाई में जितना हिस्सा उन्होंने लिया है, उस से अधिक हिस्सा विरोधी दल में बैठने वालों ने किया है । अगर आप को किसी समय दस वर्ष की सजा हुई थी तो मैं बतलाना चाहता हूं कि मुझे भी सन् १९४२ में ४२ सालों की सजा हुई थी । इसलिये यह उन्हीं के लिये कोई गर्व की बात नहीं है । मुल्क सब का है । भले ही कुछ लोग मुल्क की आजादी की लड़ाई में अभी तक हिस्सेदार न रहे हों, लेकिन हम यह कैसे कह सकते हैं कि आगे आने वाली लड़ाई में भी वे हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं । अगर मुल्क को बचाना है तो सारे मुल्क को साथ ले कर चलना होगा लोगों की तरफ उंगली उठा कर किसी मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह लोग जिन्होंने सारी जिन्दगी अंग्रेजी राज की जड़ों में हिन्दुस्तान के गरीबों का खून दिया वही लोग आज आपके साथ शामिल

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

हैं, हमारे साथ नहीं हैं । इन्हीं लोगों ने अंग्रेजी फौजों में हिन्दुस्तान के गरीबों को जरमनी और जापान के मोर्चों पर भिजवाया । जूझने वाले गरीबों के बेटे थे, जिन्होंने दुश्मनों की गरम गोलियों को अपनी छाती के खून से ठंडा किया, लेकिन कौन उनको पूछता है ? जिन्होंने सन् १८३७ की आजादी की लड़ाई में अंग्रेज का साथ दिया वह आज आपकी बगल में बैठे हैं । आज आप उनको बड़ी बड़ी पेंशनें दे रहे हैं और उनको इस प्रकार उनकी गद्दारी का इनाम दे रहे हैं । और इस तरफ वह लोग बैठे हैं जिन्होंने सारी जिन्दगी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनकी तरफ आप इशारा करते हैं । मैं चाहता हूं कि इस तरह की बहस यहां इस सदन में अब न हो । इससे बदमगजी बढ़ती है, इससे प्रेम और मुहब्बत की गंगा नहीं बह सकती । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मौका आएगा चीनी पलटनों को हिन्दुस्तान से धक्का देकर बाहर निकालने का, तो हमी लोग होंगे जो अपने हाथ से चमचमाती शमशीर लेकर, जिस तरह से हमने ब्रिटिश शाहनशाहियत का मुकाबला किया, उसी तरह से इन चीनी पलटनों को हिन्दुस्तान से निकाल कर रहेंगे ।

सज्जनो---

एक माननीय सदस्य : अभी चुनाव बहुत दूर हैं, एक साल दूर हैं ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर अनेकों दल और अनेकों पार्टियां हैं । मैंने यह अनुमान किया था कि हिन्दुस्तान की सीमाओं पर हमला होने के बाद हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी कुछ अपनी नीति को बदलेगी, उनके मन में भी अपनी भारत माता की मुहब्बत का जज्बा उठेगा । लेकिन मुझे कामरेड डांगे की स्पीच को सुन कर गम्भीर निराशा हुई । लेकिन उससे भी अधिक निराशा मुझे उन लोगों से हुई जो हमेशा अखंड भारत का नारा लगाते हैं और जिनके नेता खंडित भारत के भागीदार रहे हैं । आज वही दिया वाली पार्टी जन संघ. और उसके नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कांग्रेस के कूंड में कूंड करके उनकी हां में हां मिला रहे हैं । वह धर्म की बात करते हैं और हिन्दुस्तान की तहजीब की बात करते हैं । मैं उनसे पूछता हूं कि आज वह किस तरह खामोश हैं ? जो स्थान हमारे धर्म का हमारी सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र था, जहां पर शिव ने तपास्या की, जहां पर पार्वती ने अराधना की, जिस मानसरोवर में और जिन हिमालय की पहाड़ों और चोटियों पर हिन्दुस्तान के ऋषयों और मुनियों ने अपने लिये नहीं देश के लिये भी नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिये उसाधना की, आज वह कैलाश हमारे हाथों से निकल गया है इसी कांग्रेस सरकार की नीति से जो कि मानती है कि यही हमारी मैकमोहन रेखा है । लेकिन जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है, मैं आप के द्वारा इस सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर तिब्बत को आजाद किया जाय और तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में माना जाये, तब तो हम लोग इस मैकमोहन लाइन को अपनी सीमा रेखा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर तिब्बत चीन के हाथों में रहता है तो यह मैकमोहन रेखा हमारे देश की सीमा रेखा नहीं हो सकती । उस दशा में अगर हमारे देश की चीन के साथ कोई भी सीमा रेखा हो सकती है तो वह उत्तर पूर्व वाहिनी ब्रहमपुत्र नदी ही हो सकती है । मानसरोवर के ऊपर का हिससा चीन का हो और मानसरोवर के नीचे का हिस्सा हिन्दुस्तान का हिस्सा माना जाय । अगर तिब्बत को स्वतन्त्र किया जाय तब

तो मेकमाहन रेखा हमारे देश की सीमा रेखा स्वीकार की जा सकती है लेकिन अगर तिब्बत चीन के कब्जे में रहेगा तो फिर यह मैकमोहन रेखा हमारी सीमा रेखा नहीं हो सकती । उस दशा में तो हमारी सीमा रेखा उत्तर पूर्व वाहिनी ब्रह्मपुत्र नदी है और वही हिन्दुस्तान की प्राकृतिक सीमा रेखा हो सकती है ।

अभी कहा गया है कि एक मौका आयेगा तब हम चीनी पलटनों को निकालेंगे । लेकिन यह तभी होगा जब आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान सबल और शान्ति प्रिय होगा और वह सबल और शान्तिप्रिय हिन्दुस्तान ही अपनी सीमा रेखा को स्थिर करेगा और वहां जा कर अपने राष्ट्र का झंडा गाड़ेगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हिन्दुस्तान में आने वाले मेहमानों का जिक्र है जो कि विदेशों से हमारे देश में आयें । अगर उन के स्वागत सत्कार पर किये गये खर्च पर गौर किया जाये तो बड़ी विडम्बना होती है । इस के अतिरिक्त आप देखें कि हमारे देश में लंका की प्रधान मंत्री श्रीमती बंडारनायके रूस के प्रधान मंत्री श्री रू, इचेव आये, संयुक्त अरब गणराज्य के करनल नासिर और इसी तरह से दूसरे अनेक मेहमान आये और ब्रिटेन की महारानी भी आयीं । लेकिन उस अभिभाषण को आप पढ़ें तो सब से पहले ब्रिटेन की महारानी का नाम आता है । अगर आप रेल का टिकट लेनें जायें तो वहां पर क्यू लगता है और जो पहले आता है उस को पहले टिकट दिया जाता है, लेकिन यहां पर पक्षापात बरता गया है । जो मेहमान महरानी से पहले आये थे उन का नाम बाद में लिखा गया है । श्रीमती बंडारनायक और करनल नासिर महारानी से दो चार महीने पहले आये थे, लेकिन महारानी का नाम सब से पहले लिखा गया । इस प्रकार कैसे दूसरे मुल्कों के साथ हिन्दुस्तान अपनी दोस्ती बढ़ायेगा, मुझे तो बड़ा ताज्जुब और अचरज होता है ।

एक माननीय सदस्य : महारानी एक लेडी हैं ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : और अगर आप लेडी की बात करते हैं तो श्रीमती भंडारनायके भी एक लेडी थीं, उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए था । लेकिन यहां लेडी का सवाल नहीं है । यहां सवाल है जार्ज पंजुम की पोती का जो कि हिन्दुस्तान में यह देखने आई हैं कि यहां पर अब ये गुलाम लोग किस प्रकार रहते हैं । इसीलिये अब उनका इतना शानदार स्वागत सत्कार किया गया । सन् १८५७ के गदर के समय के दिल्ली के कोतवाल के पोते ने विलायत के बादशाह जार्ज पंजुम की पोती का शानदार स्वागत किया और उस पर हिन्दुस्तन का तीस करोड़ रुपया खर्च हो गया है या खर्च होने जा रहा है । हमें यह देख कर निहायत अफसोस होता है । इस साल जब हमारे देश में भयंकर बाढ़ आयी तो देश में दस लाख मकान गिर गये और करोड़ों लोग बेघरबार और बेरोजगार हो गए । उन दस लाख मकानों के लिए सरकार ने दस लाख रुपये भी नहीं दिये लेकिन विलायत से आने वाली महारानी के स्वागत पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है । आज वे सारे के सारे गांव जहां से यह रुपया खिंच खिंच कर आ रहा है मरघट बनते चले जा रहे हैं और इस नई दिल्ली को महारानी को दिखाने के लिए नई दुलहन की तरह सजाया गया है, और गरीब बच्चों की नसों से खून निकाल कर यहां शानदार और आसमान चूमने वाले बंगले रंगे गये । मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आज जो देहातों में मरघट की सी खामोशी है उसको वास्तव में मरघट की खामोशी न समझ लिया जाए । वहां एक बहुत बड़ा खतरा है । वह एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जो अगर धधका और फूट पड़ा तो सरकार तो जाएगी ही—सरकारें तो आती जाती रहती हैं—लेकिन डर है कि कहीं उस ज्वालामुखी के कारण हमारी जम्हूरियत, हमारा जनतंत्र ही न चला जाए । अगर ऐसा हो गया तो हमने जो अंग्रेज से

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

लगातार ६० साल तक लड़ाई लड़ी और अपने मुल्क के लिए आजादी हासिल की उसकी सुरक्षा करने में हम सफल नहीं हो सकेंगे ।

(कुछ आवाजें)

यह बीच में क्या बकवास है । सुनो, सुनो, गम्भीरतापूर्वक सुनो । अगर मुल्क को बचाना है .....

उपाध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब के भाषण से पहले भी कुछ ऐसा ही मालूम पड़ा था कि जैसे वह समझते हैं कि वह किसी पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे हैं । उन्होंने जो भी कहा है कि "यह क्या बकवास है" यह नामुनासिब है । यहां जब दूसरे लोग बोलते हैं तो माननीय सदस्य ही सब से ज्यादा इंटरप्शन करते हैं । अगर कोई मेम्बर उनके भाषण में इंटरप्शन करता है तो उस के लिये यह कहना कि यह क्या बकवास है, निहायत नामुनासिब है । इस लिये इन अल्फाज को वापस लीजिये ।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : मैं विदड्रा करता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सफा ७ पैराग्राफ नम्बर ३४ में दिया गया है कि गत वर्ष कुल ६७ विधेयक पारित हुये तथा अधिनियम बने । इसी तरह प्रत्येक वर्ष बिल पारित होते हैं और कानून बनते हैं । पर इन कानूनों पर अमल कितना होता है जरा इस पर ध्यान दीजिये और संजीदगी तथा गम्भीरता से गौर कीजिये ।

डाक वर्कर्स रग्यूलेशन आफ एम्पलायमेंट ऐक्ट सन् १९५८ में पार्लियामेंट ने पास किया था । उसी ऐक्ट के मातहत एक स्कीम भारत सरकार ने गजट की । उस स्कीम के अनुसार सन् १९५३ से कलकत्ता तथा समुद्री जहाजों पर काम करने वाले डाक मजदूरों को न्यूनतम वेतन (मिनीमम गारंटी) और हाजिरी भत्ता मिलता था । परन्तु अब सन् १९५८ के नवम्बर से कलकत्ता बन्दरगाह के मजदूरों को कानून के अनुसार जो न्यूनतम वेतन और हाजिरी भत्ता दिया जाता था, उस से अब उनको वंचित किया जा रहा है ।

इसी तरह आप देखें कि पैराग्राफ नम्बर २९ सफा नम्बर ६ पर लिखा है कि कामगर सम्बन्धों में सुधार हुआ है और गैरहाजिरी के दिनों में काफी कमी हुई है । इसका सब से अच्छा सबूत यह है कि अकेले कलकत्ता बन्दरगाह के चीपिंग और पेंटिंग विभाग के पांच हजार मजदूर आज भी हड़ताल पर हैं और उनको हड़ताल करते हुये लगातार बीस दिन हो गये हैं ; लेकिन इस सरकार को और लेबर मिनिस्टर को इस बात की कोई भी चिन्ता नहीं है कि ये पांच हजार मजदूर किस तरह से जिन्दा हैं और अभिभाषण में लिखा यह जा रहा है कि कामगर सम्बन्धों में सुधार हुआ है और अनुशासन नियमावली के लागू करने का अच्छा असर पड़ा है । इन पांच हजार गरीब मजदूरों की यह मांग है कि उन सभी को बम्बई की भांति ही कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के मातहत काम और वेतन मिलना चाहिये, तथा जो मध्यवर्ती या बीच के दलाल या मिडिलमैन जो सारा धन या मजदूर की मेहनत डकार जाते हैं वह समाप्त होना चाहिये । सरप्लस लेबर या सरप्लस वैल्यू (अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त धन) जो कुछ ही बीच के लोगों के हाथ में चली जाती है वह बंद होनी चाहिये । वह बीच के हाथों में न जा कर मजदूरों को मिलनी चाहिये ।

केन्द्रीय कर्मचारियों की गत हड़ताल के पूर्व रेलवे विभाग ने गजट किया था

कि ट्रेन एग्जामिनर अर्थात् टी० एफ० आर० का प्रारम्भिक वेतन १८० रुपया मासिक किया जायेगा । इसके साथ ही साथ हड़ताल के दौरान में प्रतिदिन आल इंडिया रेडियो भी चिल्लाता रहा कि रेलवे ट्रेन परीक्षकों को प्रतिमास १८० रुपया दिया जायेगा, फिर भी वह हड़ताल क्यों करते हैं ? परन्तु हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् अब इनको १८० रुपये के बजाय १५० रुपया ही दिया जा रहा है । यह है इस सरकार की घोषणाओं की ईमानदारी और उसके प्रति वफादारी ।

सफा नम्बर ४ पैराग्राफ नम्बर १७ में विदेशी मेहमानों की मेहमान निवाजी और उनके स्वागत सत्कार की काफी चर्चा है । इस सिलसिले में मैंने अभी यह निवेदन किया कि बाहर के मेहमानों पर जो कुछ भी खर्चा हो वह अपनी जेब को देखकर होना चाहिये । एक तरफ तो हम विदेशों से कर्ज लेते हैं और दूसरी तरफ विदेशों से गल्ला लेते हैं । अब जो मुल्क विदेशों से गल्ला और कर्जा लेकर जिंदा रहे उस मुल्क की सरकार अगर इतनी लम्बी रकम मेहमानों पर खर्च करे तो यह मुल्क किस तरीके से जिंदा रहेगा यह एक बहुत विचारणीय प्रश्न है ?

पैराग्राफ नम्बर २८ और सफा ६ पर बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं की बहुत चर्चा है । इन योजनाओं का अर्थ है कि पानी का स्रोत बढ़े तथा मुल्क में अधिक बिजली बनें परन्तु विडम्बना यह है कि युग युग की बनी हुई भागीरथी नदी जो भगीरथ प्रयत्नों से धरती पर उतरी, जिसे डलहौजी और डायर की भाषा में या फिर गला लंगोट भाषा में हुगली कहते हैं, उसमें २० बड़े बड़े जहाज डूबे पड़े हैं जिन पर कि दिन रात बालू जमती जाती है और वह जहाज पहाड़ का रूप धारण करते जाते हैं । उन को नष्ट करने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है । पहले उस नदी में १६००० टन एक जहाज माल लेकर चलता था और उस भगीरथी की छाती पर चढ़ करके कलकत्ता में आकर माल उतारा जाता था । अब हालत यह है कि जो जहाज १६००० टन बोझा लाद करके जाते थे अब वही जहाज सिर्फ ६००० टन माल ही ले जा पाते हैं । रोज खबरें आती हैं और रोजाना सवालात पूछे जाते हैं लेकिन सरकार का इधर ध्यान नहीं जाता है ।

16.33 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

जबलपुर की घटना के सिलसिले में बहुत कुछ कहा गया है । यह किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही लज्जा की बात है । लेकिन सरकार ने क्या किया ? इस सम्बन्ध में अगर नागपुर टाइम्स अखबार देखा जाय तो नागपुर टाइम्स ने लिखा है कि ३ तारीख से ले कर ८ तारीख तक कोई भी कांग्रेसी नेता और कोई भी मिनिस्टर जबलपुर में नहीं पहुंचा . .

एक माननीय सदस्य : आप क्यों नहीं पंहुचे ?

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : जी अगर सोशलिस्टनेता पहुंचते तो उन्हीं के साथ में उन को भी पकड़ा देते इसलिये वे नहीं गये । लेकिन जिम्मेदारी तो आप की है, तनख्वाहें लें आप, मोटरों में बैठें आप, शानदार बंगलों में रहें आप, गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर्स बनें आप लोग और जायें वहां पर विरोधी दल के नेता यह खूब रही ? जाना चाहिये था आप को चूंकि आप की जिम्मेदारी है । आप हम से क्या कहते हैं । नागपुर टाइम्स ने जो अग्रलेख लिखा है उस से जा कर कहिए कि उस ने कितनी शर्मिंदगी जाहिर की है कि इस तरीके की घटनाएं घटें और यह सरकार खामोश रहे । लेकिन सरकार को कानपुर की घटना का तो तुरन्त ही पता चल गया था जब वहां पर एक बहिन की अस्मत लूटी गयी थी । जब एक का विरोध किया गया था तो उस वक्त मिनिस्टर्स वहां पर हाजिर थे और पार्टी के

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

कार्यालय के अन्दर मौजूद थे। वहां पर होने वाले प्रदर्शनों को दबाने के लिये पुलिस ने गोलियां चलाईं और वहां पर १६ लोग गोलियों के शिकार हुए। एक बहिन की इज्जत लुटे, उस पर पुलिस गोली चलाये और १६ लोग मारे जायें लेकिन सरकार वहां पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है।

यहां पर एक घटना घटी। मैं जानता हूं कि वह बहुत ही अपमानजनक घटना है लेकिन उस का यह बदला नहीं दिया जा सकता है कि हजारों लोगों के घरों को जला दिया जाय और लाखों रुपये की सम्पत्ति जला दी जाय। एक जिले में नहीं लगातार तीन जिलों में यह घटनायें हुईं और यह सरकार कुछ नहीं कर सकी है। अब इस से अधिक शर्म और लज्जा की बात मध्यप्रदेश सरकार के लिए दूसरी क्या हो सकती है?

इस के साथ साथ जरा सरकार के आदेशों के ऊपर गौर किया जाय। सन् १९५८ में उत्तर प्रदेश के लिए खंडसारी के बनाने के लिए जिले में केन्द्र द्वारा जो आदेश दी पंजाब शुगरकेन आर्डर १९५९ जारी किया गया वह आदेश ही अवैध साबित हुआ और कमेटी आफ सुबौर्डिनेट लेजिसलेशन ने २३ दिसम्बर सन् १९६० को यह कहा है:—

"Since the order has been rescinded, the Committee do not consider it necessary to pursue the matter further. However, the Committee hope that an 'order' of this nature will not be repeated in the future."

इस तरीके के आदेश दिये जाते हैं जोकि आगे चल कर सभी गलत साबित होते हैं।

मैं श्रीमान्, एक मिनट और ले कर थोड़ी सी रोशनी बनारस विश्वविद्यालय के विषय में डालना चाहता हूं। सन् १९१६ में पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू और सप्रू साहब की सहायता से विश्वविद्यालय की एक कमेटी बनाई और एक कोर्ट बनाया जिसको कि कुछ समय के बाद लार्ड हार्डिंग ने सन् १९१६ में हूबहू उस को उसी तरीके से पास किया। सन् १९१६ से ले कर बराबर राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में वहां पर विद्यार्थियों ने काम किया, शिक्षकों ने काम किया लेकिन केन्द्र ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया

Mr. Speaker: Already, the hon. Member has taken 22 or 23 minutes. A number of other hon. Member are waiting.

Shri Bhadauria: Only one minute more.

Mr. Speaker: But he is going into the whole history.

श्री भदौरिया: श्रीमान्, नई हिस्ट्री को बतलाने के लिए पुरानी हिस्ट्री को भी बतलाना जरूरी है।

मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि सन् १९४२ के तूफानी दिनों में भी अंग्रेजों ने कभी अपनी पुलिस युनिवर्सिटी एरिया के अन्दर नहीं भेजी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय पी० ओ० सी० के सैंटर्स बने हुए हैं। वहां पर बनारस विश्वविद्यालय में १० अध्यापक निकाले गये। पहले हाई कोर्ट में और फिर उस के बाद सुप्रीम कोर्ट में उस के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रूलिंग दी है उस रूलिंग में से मैं कुछ अंश यहां पर पढ़ देना चाहता हूं।

"The words do not give a discretion to take action outside the Statute. We are, therefore, of the opinion that the impugned Resolutions were ultra vires and should be quashed. In the results the appeals are allowed."

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बावजूद भी जो १० अध्यापक निकाले गये और

जोकि गैरकानूनी तरीके पर निकाले गये थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस को गैर कानूनी बताया लेकिन हम देखते हैं कि आज उन दस अध्यापकों की जगह पर नये अध्यापक नियुक्त किये जाने वाले हैं। मैं श्रीमान्, आप के द्वारा इस सरकार से और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री महोदय से खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अनादर होगा तो फिर यह मुल्क कहां जायगा? यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न आज सरकार के सामने मौजूद है और हिन्दुस्तान की लोकसभा के सामने उपस्थित है। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यह पहला मौका है जब अध्यक्ष महोदय की सदारत में मुझ को बोलने का मौका मिला।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा मिलेगा।

Shrimati Mafida Ahmed (Jorhat): Mr. Speaker, Sir, I take this opportunity to welcome the President's Address which was a realistic appraisal of the events and achievements of the past year and an illustrative document of the Government's policies and programmes for the ensuing year. The hon. President's timely call to the Members of Parliament to work for national reconstruction and world peace is doubly welcome.

It is really unfortunate that the hon. President had to refer first in his Address to the Chinese aggression and incursions in our territory as he had to mention last year, though in the meantime the two Prime Ministers of the two great countries met, exchanged volumes of notes and held official talks for a peaceful settlement.

Since several hon. Members have referred to the talks between the Indian and Chinese officials on the border issue, I do not wish to say much except that I greatly admire the patience, perseverance and patriotic fervour with which the officials of the External Affairs Ministry conducted the talks with the Chinese officials. No doubt they rose to the high responsibility entrusted to them by the country.

To speak a few words on the Sino-Indian relations, I would like to begin by saying that we have been hearing of military movements, establishment of garrisons, collectionss of rations and other things just across the Indo-Tibetan border. It is anybody's guess what is the purpose of these preparations—a military offensive or just fortifications along the border. As the winter is receding and spring is coming, we shall know which way the Chinese wind is blowing, whether *Panchsheel* has a chance to live or the theory of inevitability of war has taken a practical shape in China. No doubt the Sino-Indian question is disturbing the mind of every Indian.

The President has given firm indication in his address that the Government of India is alive to the defensive preparedness of the country, while her traditional policy of peace will be more supreme. The President also expressed hope for a satisfactory settlement at an early date. I am also confident that since our case is just, our approach is honest, we shall have the desired result soon. Only, we have to be firm and patient. Our Prime Minister has made it clear in the Rajya Sabha yesterday that so far as India was concerned there was no dispute at all; because we have no doubt in our mind about our position in the matter, since the territory is ours and we have known it is ours. It was also heartening to hear from our Prime Minister that the border question with China would be settled when they vacate the Indian territory occupied by them. The determination and sincerity with which our Government, and specially our Prime Minister, is pursuing the border issue deserves support from all shades of opinion in the country. If we stand united and have faith in our Prime Minister's mature judgment, it might make the Chinese adopt the best course to practise *Panchsheel* in action

[Shrimati Mafida Ahmed]

and live territorially contented with India as a friendly neighbour. But at the same time I would venture to urge upon the Government to be alert to the changing tactics of Peking who is well trained in all the arts of communist strategy. The map attached to the Sino-Burmese treaty, the offer to Sikkin, Bhutan and Pakistan to negotiate for demarcation of boundaries are pointers of Peking's policy. So I hope our Government will engage all their attention to be prepared militarily for any attempt of territorial aggression on the part of China. Moreover the subversive elements of the country must be rooted out.

Sir, the House has discussed much about Congo; so I will not dilate on that point. Only, I want to say that the present unhappy situation in Congo sometime led me to think whether the cause of the Congolese leaders—mutual jealousies and struggle to gain power—is the easy way they got independence, or for political freedom they have not paid the price like other political leaders of Africa! If they had done so, surely they would have known the high moral standards which political leaders have to adopt when a country becomes free.

The situation in Congo is really very explosive. It is difficult for any one to say what the next few weeks might bring. But it is a happy trend that the U.N. is thinking of a firm action in Congo. It is important to save the lives of thousands of common Congolese. It would be the prime responsibility of the U.N. to create normal conditions in which a legal Government can be set up. I do not want to express any opinion on the wisdom or otherwise of the direct interest which big powers are taking in Congo. But I want to make it clear that if any country wants the U.N. to take firm action, it should give moral support to the U.N. Secretary-General, because he cannot be asked to act firmly on the one hand and denounced by the other.

But at the same time I wonder whether it is entirely the responsibility of the big powers, the neutral countries and the United Nations to advise the Congolese leaders. Should not the African leaders speak to their brethren in Congo and use their moral force to stop them in behaving in an uncivilised and brutal manner?

In his address the hon. President referred to the continued colonial rule in Goa and said that the Government of India stood committed to its peaceful liberation. It is true that the people of India and Goa feel very strongly about the colonial rule in Goa, when the mainland has been enjoying political freedom for the last thirteen and a half years. When India gained her political freedom by patient non-violent struggle, she cannot think of a different method of getting the Portuguese out of Goa except by peaceful means. I believe that justice may be delayed, but it cannot be denied to the Goans who have been aspiring along with their brethren in the mainland of India. I extend full sympathy to the people of Goa who have not yielded before the foreigner and are determined to fight out until their territory merges with India.

Next, the President referred to the persistent violation of human rights by the Government of South Africa where a sizeable population of Indian origin are being victimised. In this respect I want to say that a policy of racial discrimination and membership of the Commonwealth are contradictory things. The Commonwealth is a multi-racial union, and for one of its members to practise the cult of racial supremacy is an affront to the rest of the members I hope that in the forthcoming Commonwealth Prime Ministers' Conference our Prime Minister would take a stronger line. If the Government of South Africa would not mend their ways, the State should be ordered out of the community of free and civilised nations.

Sir, about our relations with Pakistan I have a few observations to make.

President Ayub Khan has been telling the world that his Government is determined to have friendly relations with India. Only a year back he proposed a Defence Pact with India; he wanted settlement on Kashmir; and he wanted closer relations between the people of India and Pakistan.

One must appreciate a little change of political climate which has come about in Pakistan since President Ayub Khan has taken over power in that country. Last year both the countries signed the Canal Waters Agreement which brought to a close a long standing and irritating problem. The Government and the people of Pakistan should realise that in the settlement of financial terms India has been sympathetic towards them at some cost to her own industrial needs. This was India's gesture towards having friendly relations with Pakistan. India has further given proof of her good intentions towards Pakistan by taking all the legal and constitutional steps to implement the Nehru-Noon Agreement. The sincerity with which India has sought to implement this agreement shows the sanctity our Prime Minister attaches to international agreements.

But what Pakistan has been doing? I am surprised at the peculiar way of Pakistan showing friendship for India —President Ayub Khan's great concern for the minorities, particularly the Muslims in India. If, as he said in Dacca last week, politically the minorities have been neutralised and economically finished, I do not know how scores of Muslims, Christians and Sikhs have found places in legislatures, judiciary, executive and diplomatic services and how I, a Muslim women, have been elected by a joint electorate to the country's highest legislature? I am extremely sorry that President Ayub Khan knows so little about the happy circumstances of all minorities in this country.

Coming to the home front, I have to say something about the set-up of the Nagaland. The President referred to the new set-up of Nagaland within the Indian Union. I wished that a reference had been made there about the four Indian airman who are still rotting in some jungle hide-outs as captives of the hostiles. The Government of India should make it clear to the new administrative set-up that the main task of them should be to get released all those four jawans and to explore the possibilities to restore peace and normalcy in that area.

On the 18th February, the interim body had been inaugurated and a five-man Executive Council from the elected representatives of various tribes has been formed. It is difficult for anyboy to prophecy at this stage whether the Governmnt of India has taken a right decision in conceding the demand of the Naga People's Convention. Reasonable douts have been expressed that the decision may lead to further disintegration of the country. No doubt, it is an extremely generous gesture on the part of the Government of India. And, I wish that the leaders of the Naga people will also rise to their new responsibilities shall endeavour to reciprocate the generous sentiments of the Government of India.

I want to say one thing more in this respect, that vigilance and stern measures are still necessary in that area. It is evident that the rebels are still active and more active than before. The hostiles, however small in number they may be, should be paralysed by firm measures. Whatever the Government policy may be, it must take due cognizance of the crucial fact that the area is one where there is very possibility of influences other than the Phizoites.

One more point and I shall conclude. I have something to say about the census which is currently being taken in the country. The census is an event of great importance, because it would provide the background for the future policies and programmes of

[Shrimati Mafida Ahmed]

the Government. The Census Commissioner and the census enumerators have a big responsibility on their shoulders. If any miscalculations are made, they would misdirect the Government and the nation. Since the matter is so important, the census enumerators should have been paid more than an honorarium of Rs. 10. I say this subject to correction. They are to work for three weeks and they have to go about long distances to cover the vast areas. This requires them to use buses, cycles and other transport facilities. Moreover, they are expected to be extra cautious in filling the questionnaire. Surely Rs. 10 is not enough incentive for such a responsible work. But I have no doubt that the country would greatly benefit from the census report of 1961. Lastly, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak these few words.

Shri Viswanatha Reddy (Rajampet): Mr. Speaker, for us on this side of the House it is a matter of happiness and gratification to see that in an election year on a general debate like this members of the opposition have not been able to be very critical of the Government. I do not say this to give a cue to the hon. Members of the opposition to start off at a tangent now but I say this in order to endorse the opinion expressed even by a great opponent of the governmental policies like Shri Dange when he said that the direction in which the policies of the Government of India are being carried on now, both in international affairs as well as in internal affairs, is in a right direction. With a little embellishments of the policies here and there, he was of the opinion, we would reach our goal. So also was the opinion expressed by Shri Asoka Mehta yesterday. The speeches made by both these leaders, with a little alterations, could very well have been made by any hon. Member on this side. Therefore, I am really very proud of the admission that even veteran opponents of the governmental policies have been forced to make in respect of the policies that are pursued by the Government of India. No doubt, there are certain voices expressed by the opposition which were rather critical, but these voices have been dismissed by Shri Asoka Mehta himself as representing the ideas of the 19th century political ideology plus the fading flame of feudalism. These voices cannot have much influence in the country and, therefore, need not be taken very seriously.

The shadow of the border problem that this country is faced with has been expressed in powerful terms and adequately by several hon. Members. I would not like to embark on a discussion on that subject at the moment but I would like to urge as passionately as I possibly can with regard to one matter which is agitating the minds of all enlightened and thinking persons in this country today, and that matter is the anxiety with regard to national discipline. Our Prime Minister has told us very often that sacrifices and burdens have to be borne by this country with calmness and determination not only during the darkest of our days but, if necessary, during the period of reconstruction. That is the advice which the Prime Minister has given us quite often. Now, there are others who have expressed the opinion that we are still not a nation.

Yesterday, both Shri Asoka Mehta and Shri Dange were referring to our citizens not being able to look up to higher values and their frittering away their energies in petty squabbles and they said that the disintegration of the country is slowly taking place. Now, all these voices have been expressed by several people, several thinkers and writers and they have been devoting a good deal of time and energy on this question. During the days of the freedom struggle, as all of us know, the nation was electrified into an effort which can be describe- as brotherhood.

17 hrs.

But today somehow something is lacking in this country. Our people are not electrified in the same way with regard to the reconstruction of the country. No doubt, reconstruction of a country might be a prosaic thing, but unless our leadership is able to inspire the country to that brotherhood on the basis of the reconstruction of the country there is not much hope, I suppose, for rapid progress in this country. Every single citizen of the country must be made to sacrifice whatever he can.

Mr. Speaker: He can continue tomorrow.

The House now stands adjourned to meet again at 11 o'clock tomorrow.

17.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 22nd February, 1961/*Phalguna* 3, 1882 (*Saka*).